हरियाणा विधान सभा
की
कार्यवाही

29 मार्च, 2016

खण्ड-1, अंक-10

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 29 मार्च, 2016

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(10) 1
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उतर	(10) 17
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(10) 35
विधान कार्य	(10) 66
(i) दि हरियाणा बैकवर्ड क्लासिज (रिजर्वेशन इन सर्विसेज एण्ड एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीच्यूशंज) बिल, 2016	(10) 66
(ii) दि हरियाणा बैकवर्ड क्लासिज कमीशन बिल, 2016	(10) 69
वर्ष 2016-17 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भ	(10) 70
हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री डॉ० महा सिंह का अभिनन्दन	(10) 72

मूल्य :

वर्ष 2016-17 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ) (10) 73

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों का अभिनन्दन (10) 75

वर्ष 2016-17 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ) (10) 75

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य का अभिनन्दन (10) 110

सदन की कार्यवाही में परिवर्तन (10) 110

बैठक का समय बढ़ाना (10) 110

वर्ष 2016-17 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ) (10) 110

बैठक का समय बढ़ाना (10) 117

वर्ष 2016-17 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ) (10) 117

बैठक का समय बढ़ाना (10) 120

वर्ष 2016-17 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ) (10) 120

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 29 मार्च, 2016

हरियाणा विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रात:10:00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल होगा।

To Promote Traditional Games

***1282. Shri Jasbir Singh :** Will the Sports & Youth Affairs Minister be plased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to promote the traditional games like Kabaddi, Wrestling; if so the details thereof ?

खेल मंत्री (श्री अनिल विज) : श्रीमान जी, कथन सदन के पटल पर रखे जाते हैं।

कथन

कुश्ती तथा कबड्डी राज्य के प्रसिद्ध खेल हैं। कुश्ती राज्य खेल है। अखाड़ों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षकों, खेल सामान तथा खुराक राशि की सहायता मुहैया करवाई जा रही है। काफी संख्या में नर्सरियां शुरू की जा रही हैं। भारत केसरी दंगल प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरू के शहीदी दिवस पर मनाया जायेगा जिसमें फ्री स्टाईल कुश्ती प्रतियोगिता मे हमेशा उच्चतर ईनाम दिए जायेंगे। ये दंगल भारतीय ओलम्पिक संघ तथा भारतीय कुश्ती संघ के सहयोग से मनाया जायेगा। भारत केसरी दंगल के विजेता को एक करोड़ रुपये का ईनाम दिया जाएगा, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर रहने वाले पहलवान को क्रमश: 50 लाख रुपये तथा 25 लाख रुपये दिये जायेंगे। देश में पहलवानों को सम्मान देने के लिए सरकार द्वारा भारत केसरी दंगल का आयोजन करवाए जाने के कदम उठाये गये हैं। सरकार द्वारा अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता में उच्च धनराशि का ईनाम देने का भी निर्णय लिया गया है। अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता की विजेता टीम को 1 करोड़ रुपये का ईनाम दिया जाएगा। अखिल भारतीय कबड्डी के आयोजन से भारत में कबड्डी प्रतियोगिता के प्रत्येक खिलाड़ी की महत्वाकांक्षाओं को बहुत बढ़ावा मिलेगा।

राज्य में अखाड़ों की संख्या को बढ़ाने के दृष्टिगत, सरकार ने निर्णय लिया है कि अखाड़ा प्रतियोगिता नियमित रूप से आयोजित की जाएगी।

जिला स्तरीय, जिला केसरी, जिला कुमार तथा राज्य स्तर पर, राज्य केसरी तथा राज्य कुमार के विजेताओं के लिए ईनाम राशि बढ़ा दी गई है।

[श्री अनिल विज]

राज्य स्तरीय अखाड़ा कुश्ती प्रतियोगिता

स्थिति	पूर्व नकद इनाम	वर्तमान बढ़ाया गया नकद इनाम
प्रथम	500 रुपये	5100 रुपये
द्वितीय	300 रुपये	3100 रुपये
तृतीय	200 रुपये	2100 रुपये

राज्य स्तरीय कुमार दंगल विजेता

स्थिति	पूर्व नकद इनाम	वर्तमान बढ़ाया गया नकद इनाम
प्रथम	21,000 रुपये	51,000 रुपये
द्वितीय	11,000 रुपये	31,000 रुपये
तृतीय	5,000 रुपये	21,000 रुपये

राज्य स्तरीय हरियाणा केसरी दंगल विजेता

स्थिति	पूर्व नकद इनाम	वर्तमान बढ़ाया गया नकद इनाम
प्रथम	31,000 रुपये	1,51,000 रुपये
द्वितीय	21,000 रुपये	1,00,000 रुपये
तृतीय	11,000 रुपये	51,000 रुपये

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सदन में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। हरियाणा सरकार परम्परागत खेलों के लिए प्रदेश में बहुत प्रयास कर रही है। पिछली सरकार ने खेलों के लिए जो किया मैं वह भी बताना चाहूंगा क्योंकि उसे बताना बहुत जरूरी है। पिछली सरकार में प्रदेश की खेल नीति का बहुत ढिंढोरा पीटा गया था। सच्चाई सामने आना बहुत जरूरी है। पिछली सरकारों में जो राज्यस्तरीय अखाड़ा कुश्ती प्रतियोगिताएं होती थी उनमें प्रथम पुरस्कार विजेता को केवल 500 रुपये दिये जाते थे। इतने रुपये तो खिलाड़ी की पॉकेट मनी भी नहीं होती है। हमारी सरकार ने प्रथम पुरस्कार की राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 5,100 रुपये कर दिये। यह राशि पहले दी जाने वाली पुरस्कार राशि से 10 गुना है। दूसरा पुरस्कार 300 रुपये था जिसे हमने बढ़ाकर 3,100 रुपये किये हैं और तृतीय पुरस्कार 200 रुपये था जिसे हमने बढ़ाकर 2,100 रुपये कर दिया है। जो राज्यस्तरीय कुमार दंगल आयोजित होते थे उनमें पिछली सरकारें प्रथम इनाम 21,000 हजार रुपये देती थी जिसे हमने बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया है, द्वितीय पुरस्कार विजेता को 11,000 रुपये दिये जाते थे जिसे हमने बढ़ाकर 31,000 रुपये कर दिया है और तृतीय पुरस्कार 5,000 रुपये था जिसे हमने बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया है। इसी तरह हमने राज्यस्तरीय हरियाणा केसरी दंगल के विजेताओं को दी जाने वाली राशि को बढ़ाया है। पिछली सरकारों में प्रथम पुरस्कार राशि 31,000 रुपये ही दी जाती थी जिसे बढ़ाकर हमने 1,51,000 रुपये कर दिया है, द्वितीय पुरस्कार की राशि 21,000 रुपये होती थी, उसे हमने बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दिया है और तृतीय पुरस्कार की राशि 11,000 रुपये थी, हमने उसे भी बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया है। हम इन ग्रामीण अंचल के खेलों को बढ़ावा देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रत्येक

गांव में अखाड़ा खुले। हमने इसी उद्देश्य से 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरू के शहीदी दिवस पर भारत केसरी दंगल आयोजित करने का निर्णय लिया है। भारत केसरी दंगल की पहली प्रतियोगिता हमने गुड़गांव में आयोजित करवा दी है। इस प्रतियोगिता में हमने पहले आठ स्थान पाने वाले खिलाड़ियों को इनाम दिए हैं। जो खिलाड़ी भारत केसरी बना है और जिसने प्रथम स्थान हासिल किया है उसको हमने 1 करोड़ रुपये दिए हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में कुश्ती प्रतियोगिता में इतनी बड़ी राशि कभी नहीं दी गई थी। हमने द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, तथा सप्तम स्थान पाने वाले पहलवानों को क्रमश: 50 लाख रुपये, 25 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, 5 लाख रुपये, 3 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 1 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी है। हमने अष्ठम स्थान तक पाने वाले खिलाड़ियों को बड़ी पुरस्कार राशि दी है। इसके अतिरिक्त हमने अन्य विजेता खिलाड़ियों को भी इनाम दिए हैं। हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक गांव में युवा शक्ति के सामने लक्ष्य तय हों कि हमें भी भारत केसरी बनना है, हमें 1 करोड़ रुपये जीतने हैं। हमारे इस निर्णय से प्रदेश में जो अखाड़े बंद हो चुके थे वे भी दोबारा खुलने लगे हैं। मुझे यह जानकारी एक खिलाड़ी ने दी है कि सारे देश में जो अखाड़े बंद थे वे दोबारा खुलने लगे हैं और दोबारा उन अखाड़ों में खिलाड़ी आना शुरू हो गए हैं। हमारी यह प्रतियोगिता समाप्त होते ही लोगों द्वारा अगले साल का भारत केसरी का खिताब जीतने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके अतिरिक्त हम सितम्बर महीने में राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी प्रतियोगिता भी कराने जा रहे हैं। कबड्डी हमारा परम्परागत खेल है इसलिए इसमें भी प्रथम ईनाम जीतने वाले को हम एक करोड़ रुपये इनाम देंगे। यह प्रतियोगिता 25 सितम्बर को कराई जाएगी। 25 सितम्बर को पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी का जन्म दिन है। पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी इंडियन फिलोस्फर, इक्नोमिस्ट और पोलिटिकल साइंटिस्ट हैं। उनकी विचारधारा और सोच पर ही भारतीय जनता पार्टी की सारी नीतियां बनती हैं। उन्होंने हमें समग्रता का विचार दिया है। उन्होंने कहा था कि शरीर, आत्मा, बुद्धि और मन चारों का मिलकर विकास होना चाहिए। दीन दयाल जी के 25 सितम्बर के जन्म दिन वाले दिन हर साल कबड्डी प्रतियोगिता कराई जाएगी और प्रथम आने वाले खिलाड़ी को एक करोड़ रुपये का इनाम दिया जाएगा। हमने कुश्ती की प्रतियोगिता के लिए भी पहले यही किया था और इसके लिए भी पहले इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामैंट करवाएंगे। विदइन डिस्ट्रिक्ट टूर्नामैंट करवाएंगे और फिर उनमें से जो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होंगे उनको छांटेंगे और वे स्टेट लैवल पर खेलेंगे। अध्यक्ष महोदय, पूरा महीना यह सिलसिला चलेगा और गांव-गांव में हम कम्पीटिशन करवाएंगे। सब-डिवीजन लैवल पर और जिला लैवल पर ये टूर्नामैंट करवाएंगे और उनमें से जो खिलाड़ी छांटेंगे वे स्टेट लैवल पर खेलेंगे। सारे देश की स्टेट वाइज टीमें आएंगी और उनकी कबड्डी प्रतियोगिता करवाई जाएगी। हमारा तीसरा परम्परागत खेल खो-खो है। अभी हमने उसके बारे में कोई शिडयूल तैयार नहीं किया है लेकिन हम इसका विचार ज़रूर रखते हैं कि खो-खो के खेल को भी बढ़ावा दिया जाए। ये तीनों गेम्ज ऐसी हैं जिनके लिए कोई अधिक संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती है। उसके लिए कहीं भी अखाड़ा खोलकर कुश्ती कराई जा सकती है, कबड्डी कराई जा सकती है और खो-खो खेल खेला जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त हमारे प्रदेश में कुश्ती का बहुत ज्यादा महत्व है और कुश्ती में अखाड़ों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हमने निर्णय किया है कि इस साल 100 अखाड़े छांटेंगे और हर अखाड़े को मैट और जिम देंगे ताकि बेहतरीन खिलाड़ी तैयार हो सकें। इसी साल अप्रैल या मई में सारे अखाड़े वालों को बुलाकर हम एक सम्मेलन करेंगे। सारे अखाड़े चलाने वाले और उनके जो शार्गिद हैं हम उनको बुलाकर यह सम्मेलन करना चाहते हैं। इसके

[श्री अनिल विज]`

अतिरिक्त हमने एक और निर्णय लिया है कि हर गांव में एक योगशाला खोलेंगे। उसके लिए 1100 ट्रेनर्स की भर्त्ती की इजाजत हमें मिल चुकी है और भर्त्ती की प्रक्रिया हमने आरम्भ कर दी है। हर गांव में एक योगशाला बनाई जाएगी। जिन गांवों ने इसके लिए जमीन दे दी है वहां इसी महीने या अगले महीने योगशाला का काम शुरू कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, दो एकड़ जमीन में एक योगशाला बनाई जाएगी और 5 जो स्थानीय गेम्ज होंगी वे हर गांव के हिसाब से छांटी जाएंगी तथा उन गेम्ज को वहां कराया जाएगा। कुल मिलाकर जो हम कर रहे हैं उसके पीछे हमारी सोच यह है कि हमारे युवा गलत रास्तों पर न जायें। उनके अंदर जो एनर्जी है और जो एनर्जी का स्त्रोत है उसका वे पूरा फायदा उठायें। (विघ्न) सर, प्रश्न ही इतना लम्बा है। सर, मैं इनके सारे सवालों का जवाब दूंगा। पहले मैं अपना उत्तर तो दे दूं। संधू साहब हमारे माननीय सदस्य हैं और बहुत पुराने सदस्य हैं मैं इनके हर सवाल का जवाब दूंगा। लेकिन पहले माननीय साथी ने जो प्रश्न पूछा है उनकी तसल्ली तो कर दूं। सर, कुल मिलाकर हम चाहते हैं कि गांव-गांव में सुबह-शाम योगा की क्लासिज लगें और हमारे युवा कबड्डी, कुश्ती और खो-खो आदि गेम्ज खेलें ताकि सारे प्रदेश का सुंदर वातावरण बने। हम चाहते हैं कि जो पोजीटिव एनर्जी है, उसका संचार पूरी तरह से हो और सही दिशा में हो।

श्री जसबीर देशवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने हर गांव में योगशाला खोलने की बात की है ताकि बच्चों को अच्छा वातावरण मिले। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि जिन गांवों में स्टेडियम बने हुए हैं वहां पर कोचिज की व्यवस्था नहीं है इसलिए गांवों के स्टेडियम में कोचिज की व्यवस्था की जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमैंटरी यह है कि मेरे हल्के में हाट गांव है जिसको मैंने गोद भी लिया हुआ है। उस गांव में स्टेडियम मंजूर हो गया था लेकिन किसी कारण से पिछली पंचायत ने स्टेडियम के लिए जमीन नहीं दी। अब जो नई पंचायत बनी है वह स्टेडियम बनाने के लिए जमीन देने के लिए तैयार है तो क्या मंत्री जी हाट गांव, सब डिविजन सफीदों में स्टेडियम बनाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने जहां तक स्टेडियम्ज में कोचिज नियुक्त करने की बात की है इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इनकी यह बात बिलकुल ठीक है कि हमारे पास कोचिज की काफी कमी है। इस समय हमारे पास केवल 441 कोच हैं और लगभग 600 कोचिज की पोस्ट्स अभी खाली हैं। इन 600 के करीब पोस्ट्स को भरने के लिए हमने डिमांड एस.एस. कमीशन के पास भेजी हुई है और कमीशन ने इनको एडवर्टाईज भी कर दिया है। जल्द ही कोचिज की भर्ती हो जायेगी और हम हर जगह पर कोच नियुक्त कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय साथी ने योगशाला खोलने की बात की है इस बारे में जानकारी देना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया है कि पहले फेज में हर विधान सभा क्षेत्र में जहां पर पंचायत द्वारा जमीन उपलब्ध करवाई जाए, 10-10 योगशालाएं बना दी जायें। उसमें कंडीशन यह है कि योगशाला बनाने के लिए जमीन आबादी के नजदीक होनी चाहिए। क्योंकि योगशाला यदि आबादी से दूर बनायेंगे तो वह न तो मेनटेन हो पायेगी और न ही वहां कोई जायेगा। योगाशालाओं में स्टाफ हम देंगे। जमीन देने का प्रस्ताव पंचायतें पास करके भिजवा दें। हमारा टार्गेट 6500 गांवों में योगशालाएं बनाने का है। सभी सदस्य पंचायतों से जमीन देने का प्रस्ताव पास करके विभाग को भिजवा दें, योगशालाएं हम बनाकर देंगे।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, जो सरकार ने रैसलिंग प्रतियोगिता गुड़गांव में करवाई है, डेढ़ साल में यही एक अच्छा काम किया है इसके लिए हम खेल मंत्री जी की सराहना करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन गांवों की पंचायतों के पास 2 एकड़ जमीन नहीं है क्या वहां पर सरकार अपने पैसे से जमीन एक्वायर करके योगशालाएं बनवायेगी ? मेरा दूसरा सप्लीमैंटरी यह है कि कबड्डी में नैशनल जीतने वाली टीम को एक करोड़ रुपये का ईनाम दिया जायेगा और रैसलिंग के लिए भी एक करोड़ रुपये का ईनाम दिया गया है। कबड्डी में कई खिलाड़ियों की एक टीम होती है और रैसलर एक होता है। पूरी टीम के लिए एक करोड़ रुपये की राशि कम है। क्या इस राशि को मंत्री जी बढ़ाने की कृपा करेंगे ? अध्यक्ष महोदय, मेरी तीसरी सप्लीमैंटरी यह है कि सरकार 'बेटी बचाओ' 'बेटी पढ़ाओ' का नारा दे रही है। क्या मंत्री जी जिस तरह से पुरूषों की रैसलिंग और कबड्डी की प्रतियोगिता करवा रहे हैं उसी तरह से महिलाओं की टीम की प्रतियोगिता कराने का कोई विचार है ?

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, हमारी सरकार 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के अभियान का क्रियान्वयन बड़ी गम्भीरता के साथ कर रही है। मैंने तो गुड़गांव में सरकार द्वारा आयोजित करवाये गये दंगल में सभी माननीय सदस्यों को विशेष रूप से इनवाईट किया था। मैंने उस कार्यक्रम से संबंधित कार्ड भी यहां पर बंटवाये थे और खड़े होकर पर्सनली भी प्रार्थना की थी कि सभी माननीय सदस्य इस कार्यक्रम में शिरकत करें। मैं यहां पर सभी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जब वहां पर वह फंक्शन हुआ तो मैंने अनाऊंस किया था कि आज हम पुरूष वर्ग की कुश्ती करवा रहे हैं और आगे आने वाले समय में हम महिलाओं की भी इसी प्रकार से कुश्ती करवायेंगे ऐसी हमारी योजना है। हम अपनी सरकार की इस योजना पर तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। ऐसा ही हम कबड्डी में भी करने जा रहे हैं। दूसरा सवाल माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि जिन गांवों के पास अपनी पंचायती ज़मीन नहीं है क्या हम उनमें भी योगशालाओं का निर्माण करवायेंगे। इस बारे में मैं माननीय सदस्य और पूरे सदन को यह बताना चाहूंगा कि फर्स्ट फेज़ में हम केवल उन्हीं गांवों में योगशालाओं का निर्माण करने जा रहे हैं जिनके पास अपनी पर्याप्त पंचायती ज़मीन है। हमारी सरकार का टारगेट है सभी गांवों में योगशालायें बनाने का। बाद में हम उन गांवों के बारे में विचार करेंगे जिनके पास अपनी पंचायती ज़मीन नहीं है। हमारी सरकार इस बारे में भी एक विशेष नीति बनायेगी। इसके अलावा मैं सभी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि हम न केवल गांवों में ही योगशालाओं का निर्माण करेंगे अपितु हम जगह की उपलब्धता होने पर हरियाणा प्रदेश के सभी शहरों की प्रत्येक बस्ती में भी योगशालाएं बनाने का विचार रखते हैं अर्थात ऐसी हमारी सरकार की योजना है। इसके लिए भी हम जगह देख रहे हैं। इसके बारे में भी माननीय सदस्य बता सकते हैं कि उनके विधान सभा क्षेत्र में अमुक-अमुक जगह पर इन योगशालाओं का निर्माण किया जाये। इसके लिए हमें सभी माननीय सदस्यों का सहयोग अपेक्षित रहेगा। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार पूरे हरियाणा प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा योगशालाओं का निर्माण करना चाहती है। जहां तक इन योगशालाओं के लिए कोचिज़ की भर्ती का सवाल है इस बारे में मैं यह बताना चाहूंगा कि योगशालाओं के कोचिज़ की भर्ती हम तत्काल शुरू करने जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि योगशालाओं के कोचिज़ की भर्ती की प्रक्रिया भी जल्दी से जल्दी पूरी हो जायेगी। जैसे ही योगशालाओं के कोचिज़ की भर्ती होगी हम अपनी योगशालाओं में क्लासिज़ लगाना शुरू कर देंगे।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : स्पीकर सर, सरकार ने जो हरियाणा प्रदेश में कुश्ती और कबड्डी को बढ़ावा दिया है वह वास्तव में ही सरकार का सराहनीय कदम है। इससे हमारी नौजवान पीढ़ी सही दिशा में और विकास के पथ पर आगे बढ़ेगी। मेरे हल्के में चौधरी भगत सिंह स्पोर्ट्स स्कूल, निडानी है। वहां के लड़के हरदीप ढ़िल्लों ने 98 किलोग्राम वज़न की श्रेणी में ग्रीको रोमन कुश्ती के लिए रियो ओलम्पिक में क्वालीफाई किया है। यह हमारे पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है क्योंकि यह इस प्रकार का दूसरा मौका है। इसी संस्थान के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय प्रतिस्पर्द्धाओं में 45 गोल्ड, 60 सिल्वर और 30 ब्रोंज मैडल जीते हैं। इस संस्थान में कुश्ती सहित अनेक खेलों के लिए तैयारी करवाई जाती थी लेकिन पिछली सरकार ने भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए इस इतने बढ़िया संस्थान को पूर्ण रूप से बंद कर दिया। मैंने माननीय मंत्री जी से इस बारे में बात भी की थी। मैं इस हाऊस में भी उनसे इस संस्थान को दोबारा से शुरू करने की अपील करता हूं ताकि वहां से निकलने वाले खिलाड़ी राज्यस्तरीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्द्धाओं में अपने जिले, प्रदेश और देश का नाम ऊंचा कर सकें। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार स्टेडियम्स के निर्माण के लिए बेहतर कदम उठा रही है, यह बहुत अच्छी बात है जबकि पिछली कांग्रेस सरकार ने तो स्टेडियम्स के नाम पर केवल मात्र चारदीवारी ही खड़ी कर दी थी जो कि स्टेडियम कम और पशुओं की चारागाह ज्यादा लगते थे। मेरे हल्के में कोई राज्य स्तरीय स्टेडियम नहीं है और न ही मेवात में ही कोई राज्यस्तरीय स्टेडियम है। क्या मंत्री जी विधान सभा क्षेत्र के हैडक्वॉर्टरज़ पर जहां पर स्टेडियम के लिए ज़मीन दी जा चुकी है और जहां पर चारदीवारी का भी निर्माण हो चुका है वहां पर राज्यस्तरीय सुविधाओं को उपलब्ध करवाया जायेगा ताकि वहां के बच्चों का खेलों के प्रति रूझान बढ़ सके और खेलों के मामले में प्रदेश और देश का नाम ऊंचा हो?

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, आदरणीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है कि उनके जींद जिले में एक स्पोर्ट्स संस्थान है जिसको पिछली कांग्रेस सरकार ने भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए बंद कर दिया था। उसके बारे में मैं श्री परमिन्दर सिंह ढुल के साथ-साथ सभी माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि मैं पिछली सरकार के सारे के सारे भेदभावों को दूर कर दूंगा। स्पीकर सर, हम इसी सत्र में या फिर इसके तुरंत बाद एक स्पोर्ट्स कौंसिल एक्ट लाने जा रहे हैं। सभी खेल संस्थाओं का उस एक्ट के तहत पंजीकरण होगा और जितने खिलाड़ी होंगे उन का भी पंजीकरण होगा। मैंने खेल विभाग की एक वैबसाईट तैयार करवाई है जिसमें हर खेल का, हर खिलाड़ी का, हर वर्ग का और हर नर्सरी व हर खेल के मैदान का डिजिटल डाटा तैयार करवाया जा रहा है। हमारे हरियाणा प्रदेश में ही नहीं बल्कि यह पूरे हिन्दुस्तान में पहली बार हुआ है। आज कोई भी व्यक्ति यह नहीं बता सकता कि हमारे हरियाणा प्रदेश में फुटबॉल के कितने प्लेयर हैं और इसी प्रकार से कबड्डी के कितने प्लेयर हैं। लेकिन जब हमारी वैबसाईट पूरी तरह से तैयार हो जायेगी तो किसी को भी एक क्लिक में पता चल जायेगा कि हमारे हरियाणा प्रदेश में भिन्न-भिन्न खेलों के कितने प्लेयर हैं। सभी सैन्टर्स पर हम बायोमीट्रिक मशीन लगाने जा रहे हैं ताकि पता चल सके कि कितने खिलाड़ी मैदान पर जाते हैं, कोई घर बैठ कर हाजिरी लगा कर सरकार से बेनिफिट तो नहीं ले रहा है। हमें अगर खिलाड़ियों को मिलने वाली राशि डबल भी करनी पड़ी तो वह भी हम करेंगे लेकिन जो जैन्युअन खिलाड़ी हैं उनको ही देंगे। इसी प्रकार से खिलाड़ियों की जो प्राईवेट नर्सरीज हैं जो अच्छे खिलाड़ी तैयार करती हैं उनको भी सरकार एडॉप्ट करेगी और उनको भी पूरी सुविधाएं प्रदान की जायेंगी। अध्यक्ष महोदय, कुछ सदस्यों ने स्टेडियम की बात भी उठाई है। हम खेलों के लिए बहुत गुणगान करते रहे हैं। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि कुछ

गेम्स ऐसे हैं जिनमें हमारे खिलाड़ी नैशनल गेम्स, एशियाड और ऑलम्पिक में मैडल लेकर आ जाते हैं लेकिन जिनका हमारे प्रदेश में आज तक एक भी स्टेडियम नहीं है। पिछली सरकार केवल मार्केटिंग करती रही। अगर मैं शूटिंग रेंज की बात करूं तो हरियाणा प्रदेश में कोई भी शूटिंग रेंज नहीं है। इस काम के लिए हमने राई स्पोर्ट्स स्कूल में साढ़े सात करोड़ रुपये शूटिंग रेंज के लिए दिये हैं। इसी प्रकार से साईकलिंग के लिए वैलोड्रम होता है और वह हमारे प्रदेश में कहीं पर भी नहीं है। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि कुरुक्षेत्र में हम वैलोड्रम बनाने जा रहे हैं। हमने यह नीतिगत फैसला लिया है कि हम मैपिंग करवायेंगे और हर गेम का जहाँ पर भी जरूरत होगी वहाँ पर एक इन्टरनैशनल लैवल का स्टेडियम बनायेंगे।

श्रीमती लतिका शर्मा : अध्यक्ष महोदय, कालका में स्टेडियम के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री महोदय द्वारा घोषणा भी की जा चुकी है और पिछले साल का सवा करोड़ रुपया दिया हुआ है। हमारा कालका क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ता है। नशे की लत में सबसे ज्यादा युवा हमारे क्षेत्र का है। मैं यह भी कहना चाहूँगी कि चूंकि हमारे इलाके में कुश्ती का बहुत ज्यादा शौक है इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वहाँ पर यथाशीघ्र स्टेडियम का निर्माण करवाया जाये।

श्री तेजपाल सिंह तंवर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के 10 गांवों ने 2-2 एकड़ जमीन स्टेडियम के निर्माण के लिए खेल विभाग को दी हुई है लेकिन अभी तक वहाँ पर स्टेडियम नहीं बने हैं इसलिए जल्दी से जल्दी वहाँ पर स्टेडियम का निर्माण करवाया जाये। इसके अतिरिक्त सोहना में जो ताऊ देवी लाल स्टेडियम बना हुआ है उसकी मरम्मत भी करवाई जाये तथा उसमें कबड्डी और कुश्ती के कोच नहीं हैं इसलिए वहाँ पर कोच भी यथाशीघ्र नियुक्त किये जायें। इसके अतिरिक्त उन स्टेडियमों में बेसिक सुविधाएं अवश्य प्रदान की जायें।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इस बात के लिए बहुत चिंतित हैं कि हरियाणा में खेलों में मैडल तो सबसे ज्यादा आते हैं लेकिन उनको सुविधाएं सबसे कम मिलती हैं। यह बात सही है कि जिस स्तर के खिलाड़ी हरियाणा में हैं उनको प्रदेश में उस स्तर की सुविधाएं बहुत कम मिलती हैं। जिस समय हमारी सरकार थी उस समय केन्द्र में श्रीमती उमा भारती खेल मंत्री थी, हमने इस बात के लिए प्रयास किये कि Sports Authority of India का एक रीजनल सैन्टर हरियाणा में खोला जाये ताकि प्रदेश में खेलों को बढ़ावा दिया जा सके। केन्द्रीय खेल मंत्री ने उसकी मंजूरी दे दी और वह बना दिया गया। आज वहाँ पर बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जिनकी वजह से खिलाड़ियों को अच्छा प्रशिक्षण दिया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि देश में नैशनल गेम्स होने जा रहे हैं, पहले ये नैशनल गेम्स गोवा में होने थे लेकिन गोवा नैशनल गेम्स करवाने में सक्षम नहीं है इसलिए नये सिरे से ऑलम्पिक ऐसोसिएशन्स की मीटिंग होने वाली है अगर खेल मंत्री जी सही मायनों में प्रदेश में खेलों के लिए चिंतित हैं तो आप प्रदेश की तरफ से एक प्रतिनिधि वहाँ पर भेजें। अध्यक्ष महोदय, और उस बिड में खेल मंत्री जी हिस्सा लें तो मैं उनसे वायदा करता हूं कि अगर हरियाणा उस बिड में आएगा तो मैं अपने हरियाणा को नैशनल गेम अलॉट करवा कर दूंगा। अगर हरियाणा को नैशनल गेम अलॉट हो जाएगी तो फिर आप मानकर चलो कि ये सारी सुविधाएं जिनको लेकर आज चिन्ता व्यक्त की जा रही है, चाहे वह सूटिंग रेस की है, चाहे वह साईकलिंग के लिए ग्राऊंड

[श्री अभय सिंह चौटाला]
बनाने की बात है, चाहे आपके इन्डोर स्टेडियम बनाने की बात है, चाहे कोई और दूसरी चीजों के लिए है तो फिर वह सारी सुविधाएं उसमें आ सकती हैं लेकिन इसके लिए आपको सीरियसली टेकअप करना पड़ेगा और हम आपकी मीटिंग के लिए भी बाकायदा तौर पर ओलम्पिक की तरफ से लिख कर भेज देंगे। अगर आप इसमें इच्छुक हैं तो आप उस मीटिंग में आएं। मैं आपको ओलम्पिक की तरफ से चिट्ठी लिखकर भिजवा दूंगा और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसको सीरियसली टेकअप करने का काम करेंगे।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि कल ही हमारे पास ओलम्पिक के जनरल सैक्रेटरी का फोन आया था और उन्होंने हमें यहां हरियाणा में नैशनल गेम्ज कराने का ऑफर किया था जिसकी चर्चा हमने कल कैबिनेट में कर ली है और प्रिंसिपली इसमें हमारी सारी कैबिनेट सहमत भी है। अगर हमें यह अवसर मिलता है तो हम यह ओलम्पिक गेम्स जरूर करवाएंगे जिसके लिए हमने कल भारत सरकार के खेल के चीफ सैक्रेटरी से भी बात की है, अन्य अधिकारियों से भी बात की है और इसके लिए हमारे स्पोर्ट्स के ए.सी.एस. ने भी बात की है लेकिन उसमें एक अड़चन है जो बहुत बड़ी अड़चन है जिसको अगर अभय चौटाला जी चाहें तो उसको दूर कर सकते हैं। उसमें जो अड़चन है वह यह है कि हमारे प्रदेश में ओलम्पिक संघों का झगड़ा पड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, यहां पर तीन ओलम्पिक संघ बने हुए हैं जिससे खिलाड़ियों का भी बहुत नुकसान हो रहा है क्योंकि खिलाड़ियों के मन में भी यह रहता है कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं मैं किधर जाऊं उनका मन बड़ा मुश्किल में रहता है कि किधर जाऊं और जब तक उसे दोबारा ओलम्पिक से या किसी और से मान्यता न हो तो वह किसी गेम में जाकर खेल भी नहीं सकता। इसके लिए हमने नैशनल में भी इण्डियन ओलम्पिक ऐसोसिएशन्स से रिक्वेस्ट करके एक टैम्प्रेरी एडहॉक कमेटी बनाकर एक टीम भेजी है क्योंकि वह हमारी टीम को नैशनल में एन्ट्री नहीं दे रहे थे और अब नैशनल गेम्ज कराने के लिए जो बिड होती है उसका एक फॉर्म होता है जो हमने कल मंगवाया है। उस फॉर्म के ऊपर स्टेट के और ओलम्पिक प्रेजीडेंट के दोनों के साईन होने जरूरी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने अभय चौटाला जी से खुद मिलकर भी कहा था कि खेल के इन्ट्रस्ट के लिए, खिलाड़ियों के फायदे के लिए ये जो झगड़ा चल रहा है इससे खिलाड़ियों का कोई फायदा नहीं हो रहा है। सर, मैंने जितने भी ओलम्पिक के संघ हैं, जितने आई.ओ.ए. के अध्यक्ष हैं वहां खुद जाकर रामचन्द्रन जी के साथ मीटिंग की जिसमें मैंने उनको कहा कि जितने भी हमारे ओलम्पिक संघ हैं सारे संघ अपने-अपने इस्तीफे देकर दोबारा फिर से चुनाव करवा लें। वह चाहे किसी इंडीपेंडेंट बॉडी के तहत करवा लें, चाहे हाई कोर्ट की कमेटी के तहत करवा लें, चाहे आई.ओ.ए. के तहत करवा लें। उसमें जो भी चुना जाए चाहे वह किसी पार्टी का हो, चाहे किसी रंग का हो, चाहे किसी रीजन का हो हम उसको सैल्यूट करेंगे और हम उसको एक्सैप्ट करेंगे। चाहे जो भी हो लेकिन उसके लिए पहल करनी पड़ेगी। अगर इस बात में बैठे रहेंगे कि पहले मैं क्यों करूं वह पहले करेगा इस तरह के रवैये से तो खिलाड़ियों का नुकसान हो जाएगा ? सर, यह तो एक ओपरच्युनिटी मिल रही है we want to grab that opportunity. यह अभी फाइनल नहीं है क्योंकि फाइनल तो वहां जो मीटिंग होगी उसमें जो डिसाईड होगा तभी होगा लेकिन हमें नैशनल गेम्ज कराने की ऑफर जरूर आई है और मैं आपको एक बात और बता दूं कि वह हरियाणा जो सबसे ज्यादा मैडल लेता है जिसके बारे में पिछली सरकारों ने ढ़िंढोरा पीटा हुआ था कि खेलों में हरियाणा सबसे आगे है तो लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि उस

हरियाणा में आज तक एक भी नैशनल गेम्ज नहीं हुए हैं, इसके अलावा छोटे-छोटे प्रदेशों में हुए हैं, अभी छत्तीसगढ़ में होने जा रहे हैं। परन्तु अफसोस हरियाणा प्रदेश के समृद्ध प्रदेश होने के बावजूद भी आज तक यहां पर नैशनल गेम्स नहीं हुई हैं। हमारी सरकार इन नैशनल गेम्स को हरियाणा में कराना चाहती है और इसके लिए बिड लगाना चाहती है लेकिन उसके लिए थोड़ा सा माहौल बनाने की जरूरत है। मैं अभय चौटाला जी से कहना चाहूँगा कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते वह भी खिलाड़ियों के हितों की दिशा में पहल करें और हरियाणा के सभी ओलम्पिक एसोसिएशंज के आपसी मतभेदों को खत्म करते हुए इनमें नये सिरे से चुनाव करवाये जायें क्योंकि इनकी टर्म भी पूरी होने वाली है। (विघ्न)

श्री रविन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय खेल मंत्री जी से यह प्रार्थना करता हूँ कि हरियाणा विधान सभा में हरियाणा की जनता ने हम लोगों को चुनकर भेजा है। यदि सदन के सभी पार्टियों के सदस्यों की एक कबड्डी की टीम बना दी जाये तो अच्छा रहेगा। यदि पार्टीवाईज टीम बनाई जाती है तो उस सूरत में सदन के स्वतंत्र सदस्यों की अलग से कबड्डी टीम बना दी जाये। हम सभी स्वतंत्र सदस्य दूसरी सभी पार्टियों के सदस्यों के साथ कबड्डी खेलने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। (शोर एवं हंसी)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इस समय एक बात को क्लीयर करना बहुत जरूरी है। अभी सदन में माननीय विज साहब ने ओलम्पिक एसोसिएशंज में विवाद की बात कही है। मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि ओलम्पिक एसोसिएशंज को लेकर कोई विवाद नहीं है। अशोक अरोड़ा की अध्यक्षता वाले हरियाणा ओलम्पिक एसोसिएशन को इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से एफिलियेशन मिली हुई है। अगर इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन ने किसी को एफिलियेशन दी है तो फिर झगड़ा किस बात का है। वास्तव में यह झगड़ा केवल मात्र कांग्रेस की सरकार के समय शुरू हुआ था। वर्ष 2005 में मैं हरियाणा ओलम्पिक ऐसोसिएशन का प्रेजिडेंट हुआ करता था और उस वक्त चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने उस वक्त हरियाणा ओलम्पिक एसोसिएशन के पैरलल एक अलग से बॉडी बनवाई थी और नवीन जिंदल को उसका अध्यक्ष बनाया गया था। नवीन जिंदल खुद एक स्पोर्ट्समैन था। वह घुड़सवारी का भी बहुत अच्छा प्लेयर था। वह इंडिया की तरफ शूटिंग के लिए क्वालीफाई करके एशियन गेम्ज में खेलकर आया था। वह सब प्रकार की टैक्निकलटीज से अच्छी तरह से वाकिफ था इसलिए उसने बीच में ही अध्यक्ष के पद से रिजाईन कर दिया था और कह दिया था कि मैं किसी पचड़े में नही पड़ना चाहता क्योंकि यह एक गलत परम्परा है। आज भी हरियाणा में जितनी भी ओलम्पिक से एफिलियेटिड एसोसिएशंज हैं उसके 75 प्रतिशत से ज्यादा लोग उस एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं जिसके अशोक अरोड़ा जी प्रधान हैं। इसी तरीके से पिछले दिनों जिम्नास्टिक एसोसिएशन का भी इशू आया था। जब यह बात मेरी जानकारी में आई मैंने तुरन्त दोनों ग्रुप्ज को बैठाकर उनका फैसला करवा दिया था और इस बात को लेकर आज भी कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा केवल मात्र यह था कि उस वक्त जब चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे, तब हमने सरकार से दो एकड़ जमीन लेकर और हरियाणा ओलम्पिक एसोसिएशन की तरफ से फंड इकट्ठा करके एक ओलम्पिक भवन का निर्माण करवाया था। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा हरियाणा ओलम्पिक एसोसिएशन के बड़े आफिस को देखकर यह सोचने लग गये थे कि शायद इस एसोसिएशन से कांग्रेस पार्टी को कुछ फायदा पहुंचाया जाए इसलिए उसने एक अलग से

[श्री अभय सिंह चौटाला]

ओलम्पिक एसोसिएशन बनाकर उस समय के कांग्रेस सदस्य और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्री धर्मबीर सिंह को अध्यक्ष चुना। उसके बाद तीसरा ओलम्पिक संघ बनाया गया जिसका अध्यक्ष श्री श्याम सिंह राणा जी को बनाया गया। कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि जिस ओलम्पिक संघ की एफिलियेशन इंडियन ओलम्पिक के साथ होगी वह अपने ओलम्पिक संघ के कितने भी सदस्य बना सकता है उसको कौन रोक सकता है। अब मैं इसके बारे में संक्षेप में बताना चाहूँगा एक डिस्प्यूट कमेटी बनाई गई थी जिसमें श्री पी.वी.राठी की अध्यक्षता वाले ओलम्पिक एसोसिएशन के लोग तथा श्री अशोक अरोड़ा की अध्यक्षता वाले ओलम्पिक एसोसिएशन के लोग शामिल हुए। उस डिस्प्यूट कमेटी के हैड श्री आर.के.आनन्द, एडवोकेट ने फैसला दिया था कि श्री अशोक अरोड़ा जी का जो ओलम्पिक एसोसिएशन है, वह बिल्कुल सही है। अध्यक्ष महोदय, आज भी अशोक अरोड़ा की अध्यक्षता वाली ओलम्पिक एसोसिएशन को इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से एफिलियेशन मिली हुई है। आज भी अगर कोई भी नेशनल गेम्ज होती हैं तो मैं बाकायदा तौर पर इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन पर दबाव बनाता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में हरियाणा प्रदेश का कोई भी खिलाड़ी नैशनल गेम्ज में हिस्सा लेने से छूटना नहीं चाहिए चाहे इसके लिए एडहॉक कमेटी ही क्यों न बुलानी पड़े। इस तरह के प्रयास के फलस्वरूप ही हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों को विदेश में खेलने के अवसर प्राप्त होते हैं। अदरवाईज अगर मैं यह चाहूंगा कि जिसकी एफिलियेशन है, उसी के अनुरूप खिलाड़ी खेलने जायेंगे, तो दूसरे खिलाड़ियों को वहां एन्ट्री ही नहीं मिलेगी। लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें कोई राजनीति ना हो। अध्यक्ष महोदय, हमारी मंशा है कि प्रदेश का हर खिलाड़ी उसमें हिस्सा ले। मैं तो इस बात के लिए हमेशा से तैयार रहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ आपके माध्यम से एक ही बात कहता हूँ कि जिन लोगों ने एक पैरलल एसोसिएशन बनाकर हमारे ऑफिस पर कब्जा किया था और एफ.आई.आर. भी दर्ज करवाई थी, माननीय मंत्री जी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने जो बताया है उससे मैं सहमत हूँ। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो प्रदेश का कदम-कदम पर बेड़ा गर्क तो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री रहे चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने किया है। हरियाणा प्रदेश में खेलों का भी बेड़ागर्क किया गया है। अब यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। अध्यक्ष महोदय, हम तो कोर्ट में भी पार्टी बनना चाहते थे, ताकि कोर्ट में पार्टी बनकर कोर्ट से रिकवैस्ट करें कि आप अपनी देख-रेख में चुनाव करवा दीजिए जिससे यह मसला खत्म हो जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रतिपक्ष के नेता से कहना चाहूँगा कि आप बड़े मन से नये चुनाव करवाने के लिए रास्ता प्रशस्त करें, चाहे उसमें कोई भी चुनाव जीतकर आए इससे हमें कोई मतलब नहीं है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, चुनाव ड्यू हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, चुनाव ड्यू हैं तो माननीय प्रतिपक्ष के नेता पहले चुनाव करवा लें। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं लड़ नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ बात को बता रहा हूँ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हम सरकार को भी चिट्ठी लिख देंगे कि आप अपना ऑब्जर्वर भेज दें ताकि यह पता लग सके कि चुनाव में कौन-कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि सही लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और सरकार भी अपनी तरफ

से लिखकर दें कि यह जो संघ बन रहा है, वह बिल्कुल सही है।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो चुनाव ड्यू हैं। हम नैशनल के लिए बिड कर सके, इसके लिए चुनाव की बात कर रहे हैं ताकि हमें एडहॉक कमेटी ना बनानी पड़े। यदि हमें एडहॉक कमेटी बनानी पड़ेगी तो फिर उसी के मुताबिक काम करना पड़ेगा।

श्री अभय सिंह चौटाला : विज जी, आप यह मानकर चलो चाहे आप एडहॉक कमेटी बना लो या काउंसिल बना लो, लेकिन भारतीय ओलंपिक संघ एडहॉक कमेटी को कभी भी मान्यता नहीं देगी। यदि इसमें कोई नया पचड़ा खड़ा करेंगे तो प्रदेश के खिलाड़ियों का ही नुकसान होगा।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, इससे यह साफ हो गया कि राष्ट्रीय खेलों के रास्ते में रूकावट है।

श्री अभय सिंह चौटाला : विज जी, इसमें कोई भी रूकावट नहीं है।

श्री अनिल विज : अभय जी, आप यह कह रहे हो कि भारतीय ओलंपिक संघ स्वीकार नहीं करेगा।

श्री अभय सिंह चौटाला : विज जी, मैं तो यह कह रहा हूँ कि आप उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो जिन्होंने गलत काम किए हैं।

श्री अनिल विज : अभय जी, आप यह कहो कि एडहॉक कमेटी को भारतीय ओलंपिक संघ स्वीकार करेगी और यह कमेटी पहले भी भारतीय ओलंपिक संघ ने बनाई है। यह कोई हमने नहीं बनाई है। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर एक बार कहूँगा कि आप थोड़ा सा अपना मन बड़ा करो।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रतिपक्ष के नेता से अनुरोध करूँगा कि इस विषय पर बहुत चर्चा हो गई है और यह सारा विषय सबके ध्यान में आ गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि अब अगले प्रश्न टेकअप किए जायें।

Network of Irrigation Channels/Minors

***1178. Shri Parminder Singh Dhull :** Will the Irrigation Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to widen the network of irrigation water channels and minors in the Julana Assembly constituency; and

(b) the current status of Biroli minor and new Karela minor togetherwith the time by which these are likely to be completed ?

कृषि मंत्री (श्री ओमप्रकाश धनखड) :

(क) नहीं, श्री मान जी।

(ख) बरौली माइनर के निर्माण, की योजना छोड़ दी गई थी तथा करेला सब माइनर के निर्माण की योजना भूमि उपलब्धता के बाद शुरू कर दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 'आदर्श ग्राम योजना' के तहत विधायकों द्वारा जो गांव अपने-अपने क्षेत्रों में एडौप्ट किए

हैं, उनमें विकास करने के लिए एक-एक करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई है। (इस समय मेजें थपथपाई गई।

श्री राम बिलास शर्मा: बलकौर जी, आपको घोषणा के बारे में पता चल गया होगा।

श्री महीपाल ढांडा: अध्यक्ष महोदय, यह तो पैसे की योजना है, इसलिए सभी माननीय सदस्यों को इस घोषणा के लिए ज्यादा से ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तारीफ करनी चाहिए।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इनके क्षेत्र की किला जफ़रगढ़ माइनर को चौड़ा करने का कार्य चल रहा है। इसके लिए कोई नया प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। नई करेला माइनर को पूरा करने के लिए हमें जमीन एक्वायर करनी है। जैसे ही हमें जमीन प्राप्त हो जाएगी हम काम शुरू कर देंगे। आजकल जमीन अधिग्रहण करना बड़ा मुश्किल काम है। अगर माननीय सदस्य हमें जमीन उपलब्ध करवा दे तो हम इसका काम तुरंत शुरू करवा देंगे। इसके लिए विभाग पेमैंट करने को भी तैयार है। करेला माइनर के लिए स्टेट टैक्नीकल कमेटी 22 जनवरी, 2010 को पहले ही 'ना' कर चुकी है। इसके उन्होंने दो कारण बताए हैं। एक कारण तो यह बताया है कि इस माइनर का कमांड एरिया यानी इस माइनर ने जितने क्षेत्र में सिंचाई करनी है वहां सिंचाई की सघनता 115 है। इसके अतिरिक्त वहां पर बाकी लोगों के खेतों में ट्यूबवैल्ज या दूसरे चैनल से सिंचाई की जाती है। दूसरा कारण उन्होंने बताया है कि यह माइनर 8-9 क्यूसिक की है। जब किसी छोटी माइनर में थोड़ी-सी भी चोरी शुरू हो जाए तो टेल एंड तक पानी पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन दो कारणों की वजह से अभी इस माइनर के लिए हमने हामी नहीं भरी है। मैं माननीय सदस्य श्री परमिन्दर सिंह ढुल की प्रशंसा करूंगा। इनसे बाकी विधायकों को सीखना चाहिए कि हल्के के विकास कार्य कैसे कराए जाते हैं। ये अकेले ऐसे विधायक हैं जिन्होंने इतने कम समय में विधान सभा में प्रश्न पूछ-पूछकर सत्ता पक्ष के विधायकों से भी ज्यादा 33 करोड़ रुपये अपने क्षेत्र में नहरी विभाग से लगवाए हैं।

श्री परमिन्दर सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : ढुल जी, अब तो आपको खुश होना चाहिए चूंकि आपकी माननीय मंत्री जी ने प्रशंसा की है।

श्री परमिन्दर सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि मेरे प्रश्न की सैंस चेंज हो गई है। माननीय मंत्री जी ने इस नैटवर्क को चौड़ा करने की बात की है जबकि मैंने इस नैटवर्क को दुरूस्त करने के बारे में प्रश्न पूछा था। मेरे क्षेत्र के रजवाहा नं० 4 में 0-50 बुर्जी से आगे पानी नहीं जा रहा है। इस रजवाहे को अपने कमांड एरिया के मुताबिक पानी नहीं मिल रहा है। यदि इसके 0-50 बुर्जी तक दोनों तरफ के किनारों को ऊंचा कर दिया जाए तो पानी टेल एंड तक पहुंच जाएगा। दूसरा, मेरे क्षेत्र में एक लुदाना माइनर है जिसका बैड टूट चुका है। इसमें पानी पहुंचे 12 साल हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त मेरे क्षेत्र में शादीपुर माइनर और जुलाना सब-माइनर है जिसे पिछली सरकार ने बनाया था परंतु इनका बिल्कुल बेड़ा गर्क हो चुका है। इनमें भी 12 साल से पानी नहीं पहुंचा है। एक तो आप इसके बारे में जानकारी दें और दूसरा बरौली माइनर के लिए मैं विभाग

को जमीन दिलवाने के लिए प्रयासरत हूं। इस बारे में मैंने एस.ई. से भी बात की है। इस विषय में हम मिलकर प्रयास करेंगे तभी आगे बढ़ सकेंगे। अगर माननीय मंत्री जी इस माइनर को जमीन मिलने पर बनाने का आश्वासन दे रहे हैं तो मैं जल्दी ही जमीन भी दिलाने का प्रयास करूंगा। इस माइनर के लिए मैंने विधान सभा में प्रश्न पूछा था और इसे वर्ष 2011 में बनाने का आश्वासन दिया गया था परंतु राजनीतिक कारणों से यह केवल आश्वासन ही रह गया। इससे दो गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हैं- गांव पडाना और गांव निदानी। इन गांवों में पशुओं के पीने के लिए पानी भी पर्याप्त नहीं है। इन गांवों को इस माइनर से ही पानी मिल सकता है। इन गांवों में पानी की बहुत भारी कमी है और माननीय मंत्री जी को सर्वे कराकर वहां पानी पहुंचाना चाहिए। इन गांवों को चाहे एक सब माइनर प्लान करके और उसका एरिया बढ़ाकर या निदानी माइनर या साभरी माइनर का कमांड एरिया बढ़ाकर अगर पानी दिया जाए तो इनकी समस्या दूर हो सकती है। इसके अतिरिक्त मान लीजिए मैं एक किसान हूं और जब मेरा पानी चोरी होता है तो नहरी विभाग मुझसे तवान वसूलता है और दंडित भी करता है लेकिन अगर किसान को पानी नहीं मिल रहा है तो फिर तवान वसूलने का क्या फायदा है ? नहरी पानी पर अगर किसान का एक बार वार चला गया तो फिर दूसरे वार के लिए उसे 45 दिन तक इंतजार करना पड़ता है। मेरा प्रश्न यह है कि जब आप पूरे हरियाणा से करोड़ों रुपये तवान वसूलते हो तो क्या आप उसे कोई सुविधा भी प्रदान करोगे ? नहरी पानी न मिलने पर जब किसान को दूसरे किसी साधन से खेत में पानी पहुंचाना पड़ता है तो उससे उसका खर्च बढ़ जाता है। आज तक किसी सरकार ने किसानों को ऐसी सुविधा देने का प्रयास नहीं किया है। किसान का पानी चोरी होता है, सरकार पैसा वसूलती है और किसान को कोई फायदा नहीं होता है। क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे किसान को कुछ फायदा हो सके? अगर माननीय मंत्री जी मेरे क्षेत्र की 3-4 माइनर्स की रिमॉडलिंग कर दें तो जो एग्जिस्टिंग पानी है वह हमें मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त रजवाहा नं० 4 में जो साढ़े तीन सौ एकड़ जमीन है उस पर आबादीदेह हो चुकी है लेकिन वहां आज भी पानी चल रहा है। हरियाणा में इस तरह के बहुत से रजवाहे हैं जो आबादीदेह के अंदर आ चुके हैं और वहां कंस्ट्रक्शन भी हो चुकी है लेकिन पानी लगातार चल रहा है इसलिए उस पानी को वहां से कट करके टेलएंड तक पहुंचाया जा सकता है। क्या सरकार इसके लिए कोई प्रयास करेगी ? अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बीबीपुर सब-माइनर के लिए भी 'हां' भरी थी इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज मुझे आश्वासन दे दिया जाए कि बीबीपुर की सब-माइनर निकाली जाएगी। (विघ्न)मंत्री जी की हमारे यहां के जिस गांव से रिश्तेदारी है उसके बारे में इनको पता है कि वहां 15 सालों से एक बूंद भी पानी नहीं गया। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यहां दो तीन विषय पडाना और निदानी के उठाए गए हैं। मैं अपने माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि इनके बारे हम डिपार्टमैंट से अध्ययन करवा लेंगे। यदि पानी की ऐसी कोई कठिनाई है तो इन गांवों तक कैसे पानी पहुंचाया जाए उसके बारे में हम विचार कर लेंगे। माननीय साथी ने दूसरा सवाल कहा है कि जहां पानी की आवश्यकता ही नहीं है वहां कई जगह पानी ऐसे ही बेकार चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने बहुत अच्छी बात कहीं है। ऐसी जो भी जगहें हैं जहां पानी वेस्ट हो रहा है, हम उसको बचाकर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बारे जरूर विचार करेंगे। तीसरे सवाल में इन्होंने तवान के विषय को उठाया है, इसके लिए मैं इनको बताना चाहूंगा कि हम इस विषय में इजरायल के पैटर्न पर आगे बढ़ रहे हैं। हम 13 पॉयलट प्रोजैक्ट इस साल कम्पलीट करेंगे। नहर विभाग इसके लिए जिम्मेवारी

[श्री ओम प्रकाश धनखड़]

लेगा कि हम किसान के खेत तक पानी पहुंचाएं। धीरे-धीरे ज्यों ही हम इस प्रोजैक्ट को पूरा कर लेंगे उसके बाद हम हर ब्लॉक में एक पॉयलट प्रोजैक्ट देंगे। आने वाले सालों में हम माइक्रो इरीगेशन सिस्टम द्वारा पानी की बचत का पूरा प्रयास करेंगे। जिस प्रकार जल विभाग रसोई तक पानी पहुंचाने का काम करता है उसी तरह हमारा नहरी विभाग किसान के खेत तक पानी पहुंचाने का काम करेगा और इस रास्ते पर हम आगे बढ़ भी रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एक और उपलब्धि का भी मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा। इस उपलब्धि में ढुल जी के सवाल की बजाय मैं नैना चौटाला जी के सवाल की बात करूंगा। रामकली और भैभलपुर को जोड़ने वाली बात के बारे में जैसा इन्होंने कहा भी है कि इसमें वहीं जमीन वाली बात है इसलिए यदि आप यह जमीन का इंतजाम करवा देंगे तो बीबीपुर वाले इशू पर हम आगे बढ़ पाएंगे।

श्री परमिन्दर सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, बीबीपुर के लिए माइनर जाएगी तभी पीने का पानी भैभलपुर जा सकता है अन्यथा उस गांव में पीने के पानी के लिए और कोई रास्ता नहीं बचा है।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को कहना चाहता हूं कि हम इस विषय को भी पूरा कर देंगे।

श्री तेजपाल तंवर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में नहरों की बहुत कमी है। घंघोला माइनर में से दो तीन पाइप्स में पानी नहीं जाता। इसके लिए हमने कई बार प्रार्थना कर ली है कि इस घंघोला माइनर को ठीक करवाया जाए। इसके साथ-साथ हरचंदपुर डिस्ट्रीब्यूट्री जोकि 20 साल पहले बनी थी। उसके लिए जमीन एक्वायर हुई थी। वह थोड़ी तो चली है लेकिन बाकी ऐसे ही पड़ी हुई है। उसमें सरकार का बहुत पैसा लगा था इसलिए मेरी अपील है कि इसको चालू करवाया जाए ताकि हमारे किसानों को कुछ एरिया में तो पानी मिल सके।

श्री अध्यक्ष : तेजपाल जी, मंत्री जी इस बारे में विचार कर लेंगे।

Upgradation of Schools

***1317. Shri Gian Chand Gupta :** Will the education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the High Schools of villages Khetpurli and Bataur as senior Secondary Schools of Panchkula; if so, the time by which these schools are likely to be upgraded?

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : श्रीमान् जी, जिला पंचकुला के राजकीय उच्च विधालय, खेतपुराली को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर स्तरोन्नत करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। अन्तिम निर्णय यथासमय हो जाएगा। परन्तु जिला पंचकुला के राजकीय उच्च विद्यालय, बतौड़ को स्तरोन्नत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ज्ञान चंद गुप्ता जी ने खेतपुराली तथा बतौड़ गांवों के उच्च विद्यालयों का दर्जा बढ़ाने के बारे में पूछा है तो मैं अपने माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि विद्यालयों का दर्जा बढ़ाने के हमारे कुछ नार्म्ज हैं। हाई स्कूल को अपग्रेड करने के लिए 9वीं से 10वीं क्लास तक के बच्चों की संख्या 150 होनी चाहिए, उस स्कूल में दो एकड़ जमीन होनी चाहिए तथा 14 कमरे होने चाहिएं। खेतपुराली के स्कूल में इस समय 9 से 10वीं क्लास के बच्चों की संख्या 125 हैं। खेतपुराली गांव से हमारी कुछ भावनाएं जुड़ी हुई हैं। शिव प्रसाद जी

चार बार विधायक रहे हैं और खेत पुराली उनका गांव है। मैं माननीय विधायक ज्ञान चंद गुप्ता जी से कहूंगा कि इस विद्यालय में बच्चों की संख्या कम है उसके बावजूद भी हम खेतपुराली के इस स्कूल को इसी सत्र में ही अपग्रेड करने बारे विचार करेंगे। जहां तक बतौड़ गांव के स्कूल को स्तरोन्नत करने का सवाल है वहां पर एक कि0मी0 के रेडीयस में तीन सीनियर सैकेंडरी स्कूल हैं इसलिए उसका दर्जा नहीं बढ़ाया जा रहा और खेतपुराली का दर्जा इसी सत्र से बढ़ायेंगे।

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने खेतपुराली के स्कूल को अपग्रेड करने का आश्वासन दिया है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि पिछले दस साल से बार-बार आश्वासन ही मिलता रहा है लेकिन इस स्कूल को अपग्रेड नहीं किया गया। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इसी सत्र से इस स्कूल को अपग्रेड किया जाये।

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने कहा कि पिछले दस साल से आश्वासन ही मिलते रहे हैं। वे दस साल तो बहुत भयंकर थे उसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं है। मैं माननीय साथी को फिर से बताना चाहूंगा कि खेतपुराली के स्कूल का दर्जा इसी सत्र से बढ़ाकर उसका नाम शिव प्रसाद जी के नाम से रखेंगे।

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि पंचकुला सैक्टर-26 में पांच एकड़ जमीन पिछले पांच साल से बाउंडरी वाल होकर ऐसे ही पड़ी है। क्या वहां पर सरकार का सीनियर सैकेंडरी स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव है ? वहां पर 8 नये सैक्टर आबाद हो चुके हैं जिसके कारण वहां की आबादी बहुत ज्यादा हो चुकी है इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां पर सीनियर सैकेंडरी स्कूल जल्द से जल्द खोला जाए।

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, आपका यह अलग सवाल है। इसमें मंत्री जी जवाब यही देंगे कि यह अलग प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न पूछने से सदन का समय बर्बाद होता है। इस तरह के प्रश्न पूछने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। आपने जो प्रश्न पूछ रखा है आप उसी पर स्टैंड रहें। (विघ्न) यदि बतौड़ का सवाल पूछा है और कोई सदस्य मोरनी का सवाल करेगा तो मंत्री जी के लिए पोसिबल नहीं है कि वे पूरे प्रदेश के स्कूलों का जवाब दे सकें।

Functioning of Solid Waste Management Plant

***1427 Shri Ghanshyam Dass :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state -

(a) the date on which the solid waste management plant situated at village Kail in Municipal Corporation, Yamuna Nagar-Jagadhari was started togetherwith the period for which it remained functional;

(b) whether the abovesaid plant is not functioning properly at present; if so, the time by which it is likely to be made functional; and

(c) whether any action has been taken against the person/institution responsible for non-functioning of the abovesaid plant ?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमती कविता जैन) :

(क) नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी के गांव कैल में स्थित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र

दिनांक 3.8.2012 को प्रारम्भ किया गया तथा यह संयंत्र दिनांक 3.8.2012 से 30.11.2014 तक कार्यशील रहा।

(ख) हां, श्रीमान् जी। वर्तमान में यह संयंत्र कार्य नहीं कर रहा है। कंसैसनेयर के साथ संविदा समाप्त करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। वर्तमान संविदा समाप्त होने उपरांत संयंत्र 6 माह के अन्दर कार्यशील कर दिया जायेगा।

(ग) नगर निगम, यमुनानगर-जगाधरी द्वारा वर्तमान कंसैसनेयर मैसर्ज हाईड्रोएयर टैक्टोनिक्स प्राईवेट लि०, को कार्यक्षमता सुचारु ना होने के कारण दिनांक 2.7.2014 एवं 28.8.2015 को कार्य समाप्ति के नोटिस जारी किये गये। नोटिस कंसैसनेयर की ₹ 65.00 लाख की बैंक गारन्टी को जब्त करने के लिये दिया गया है।

श्री धनश्याम दास : अध्यक्ष महोदय, माननीया मंत्री जी ने जितने दिन इस संयंत्र को सुचारु रूप से चलने की बात कही है यह सही नहीं है क्योंकि यह संयंत्र वास्तविक रूप से एक दिन भी ठीक से नहीं चल पाया। जिसके कारण नगर निगम का जितना वेस्ट है वह एक जगह इकट्ठा हो रहा है और वह बहुत मात्रा में हो गया है। वहां पर इस वेस्ट के कारण कभी भी कोई भी महामारी फैल सकती है। इसके साथ ही मंत्री महोदया ने कहा है कि अभी 6 महीने का समय इसको पूरा करने में लगेगा तो इस 6 महीने में वहां की क्या स्थिति होगी, कृपा इस विषय पर भी प्रकाश डालें ?

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी ने एक बहुत ही अच्छा सवाल किया है। सफाई व्यवस्था को दुरूस्त करना न केवल हमारी हरियाणा सरकार का लक्ष्य है बल्कि हमारी केन्द्र सरकार का भी सर्वप्रथम लक्ष्य है और इस सफाई व्यवस्था को लेकर हमारी राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की पूर्ण प्रतिबद्धता है। माननीय विधायक जी ने जो उस संयंत्र, वहां की सफाई व्यवस्था और बीमारी के डर के प्रति चिंता व्यक्त की है वह पूरी तरह से जायज़ है। मैं उनको यह बताना चाहूंगी कि यह समस्या केवल उनके यमुनानगर की ही नहीं है बल्कि यह समस्या आज हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश की है। अध्यक्ष महोदय, इस समय हमारी 80 अर्बन लोकल बॉडीज़ का एरिया है। इन 80 अर्बन लोकल बॉडीज़ की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 88 लाख है और वहां से 4285 टन प्रति दिन सॉलिड वेस्ट निकलता है। इस समय हमारे हरियाणा प्रदेश में सॉलिड वेस्ट मैनेजमैंट के 6 प्लांट हैं। हमारे प्रदेश की सभी नगरपालिकाओं और नगर निगमों ने सफाई व्यवस्था को लेकर अपने-अपने स्तर पर इंतज़ाम किये हुए हैं। यह बात मैं भी स्वीकार करती हूं कि कहीं-कहीं ऐसा हो सकता है कि वे सही रूप से काम नहीं कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने प्रदेश में सफाई व्यवस्था के अभियान को बहुत गम्भीरता के साथ लिया हुआ है और पूरे प्रदेश में प्राथमिकता के आधार पर इसके ऊपर काम किया जा रहा है। नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की गाईडलाइंस के मुताबिक हमने अपने पूरे हरियाणा प्रदेश को 15 क्लस्टर ज़ोन में बांटा है और वहां पर सॉलिड वेस्ट मैंनेजमैंट के प्लांट लगाये जायेंगे। हमारे प्रदेश में सॉलिड वेस्ट की मुख्य रूप से दो समस्याएं हैं पहली तो सॉलिड वेस्ट को उठाना और उसके बाद उसका निष्पादन करना। वर्तमान समय में सॉलिड वेस्ट का डम्प हुआ जा रहा है लेकिन उसका निष्पादन अर्थात ट्रीटमैंट नहीं हो रहा है। इसी कारण से चाहे यमुनानगर हो, गुड़गांव हो या जहां-जहां पर ये सॉलिड वेस्ट ट्रीटमैंट प्लांट लगे हुए हैं वहां-वहां पर यह समस्या बढ़ती ही जा रही है। हमारी सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए इंटीग्रेटिड सॉलिड वेस्ट

मैनेज़मैंट का एक मॉडल तैयार किया है। ऐसा करके हमारी सरकार इस क्षेत्र में पूरे देश के अंदर अग्रणी भूमिका निभाने का काम कर रही है। अगर हम सॉलिड वेस्ट टू एनर्जी के प्लांट की बात करें तो पूरे देश में इस प्रकार के पांच प्लांट हैं। हमने न केवल 15 ऐसे क्लस्टर आईडैंटीफाई कर लिये हैं बल्कि हमने इस दिशा में आगे की कार्यवाही भी आरम्भ कर दी है। कैबिनेट की सब-कमेटी हमारे इस कार्य को अप्रूवल दे चुकी है। शीघ्र ही हम इस काम के लिए 21 अप्रैल, 2016 को टैण्डर फ्लोट कर देंगे। इस प्रक्रिया के अंतर्गत submission of bids की जो हमारी डेट होगी वह 21 मई, 2016 होगी। उसके बाद 30 जून, 2016 को हम कांट्रेक्ट साईन कर देंगे। इस प्रकार से प्रदेश के अंदर जो क्लस्टर हमने आईडैंटीफाई किये हैं उन सभी के अंदर काम करना हम शुरू कर देंगे। इससे हम न केवल सॉलिड वेस्ट का निष्पादन करेंगे बल्कि हम सॉलिड वेस्ट को एनर्जी में कंवर्ट करने का काम भी करेंगे। चाहे हम उससे बिजली बनायेंगे या फिर कम्पोस्ट खाद बनायेंगे लेकिन उसको उचित तरीके से हर हालत में एनर्जी में कंवर्ट किया जायेगा। इस प्रक्रिया के बाद जो वेस्ट बचेगा उसको हम लैंड फिल करने के लिए यूज़ करेंगे। इस कांट्रैक्ट की एक खास बात यह भी है कि इसमें एक कम्पोनैंट यह भी होगा कि जो भी कोई पार्टी इस तरह के प्लांट लगायेगी जो वेस्ट बचेगी अगर वह 20 परसैंट से ज्यादा होगी तो उसके ऊपर पैनल्टी लगाने का काम भी हमारे विभाग द्वारा किया जायेगा। स्पीकर सर, आज हरियाणा प्रदेश में सफाई व्यवस्था को लेकर एक प्रश्न हमारी माननीय विधायक ने उठाया है। इस सम्बंध में मैं उनके साथ पूरे सदन को यह जानकारी भी देना चाहूंगी कि ये 15 क्लस्टर के रूप में तो हमने उन जगहों को आईडैंटीफाई किया है जहां पर सॉलिड वेस्ट 500 टन प्रति दिन के हिसाब से होगा। इसके अलावा जो हमारे दूसरे छोटे अर्बन लोकल बॉडी एरियाज़ हैं जहां पर सॉलिड वेस्ट की मात्रा इतनी ज्यादा नहीं है वहां के लिए हम लोग अलग से स्कीम बनाने जा रहे हैं जिसके तहत जो हमारे बैंक्वेट हॉल्ज़ हैं, जो हमारे हॉस्टल हैं जिनसे किचन वेस्ट या गार्डन वेस्ट ज्यादा निकलता है उनके लिए आज छोटी मशीनें मार्किट में आई हुई हैं जो उसको वहीं की वहीं कम्पोस्ट कर देती हैं। हम इन सम्भावनाओं पर भी विचार कर रहे हैं कि भविष्य में हम इसको ऐसे संस्थानों के लिए इस प्रकार की मशीनों को लगाना मैनडेटरी करने जा रहे हैं ताकि इस प्रकार के संस्थानों से निकलने वाले सॉलिड वेस्ट का वहीं पर ट्रीटमैंट सम्भव हो सके। गुड़गांव शहर के अंदर बहुत सी ऐसी ग्रुप हाऊसिंग सोसायटीज़ हैं जहां पर इस प्रकार की मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ हमने अपनी सभी नगरपालिकाओं और नगर निगमों को ये निर्देश स्पष्ट रूप में दिये हुए हैं कि वे अपने स्तर पर कांट्रैक्ट करके अपनी-अपनी सफाई व्यवस्था को दुरूस्त कर लें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Construction of Water Tank

***1322. Shri Sukhwinder :** Will the Public Health Engineering Minster be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a water tank in village Bilawal of Badhra Block; if so, the detials thereof ?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री (श्री घनश्याम सर्राफ) : नहीं, श्री मान जी।

Upgradation of Sub-Centre

***1270. Shri Aseem Goel :** Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Sub-Centre of Health Department to PHC in village Jodhpur of Ambala City Constituency; if so, the time by which it is likely to be upgraded togetherwith the details thereof ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : नहीं श्रीमान जी।

Route of Buses in Mewat

***1260. Shri Zakir Hussain :** Will the Transport Minister be pleased to state—

(a) the details of sanctioned routes of Haryana Roadways Buses and Private Buses in Mewat district; and

(b) the details of Haryana Roadways Buses Plying against the total sanctioned strength in Mewat district ?

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : श्रीमान् जी, सदन के पटल पर विवरण रख दिया गया है।

विवरण

वर्तमान में हरियाणा राज्य परिवहन, नूंह द्वारा 59 मार्गों पर निम्न विवरण अनुसार बस सेवाएं दी जा रही है:-

क्र० सं०	संचालित मार्ग
1	2
1.	नूहँ-पुन्हाना - फिरोजपुर झिरका
2.	नूहँ-गुडगांव-फिरोजपुर झिरका
3.	नूहँ-पुन्हाना-फिरोजपुर झिरका-बडकली-पुन्हाना
4.	नूहँ-उमरी-उठावड-पटौदी-नूहँ
5.	नूहँ-पुन्हाना-होडल-नूहँ-पुन्हाना
6.	नूहँ-शिकरवा-अलीगढ-नूहँ
7.	नूहँ-फिरोजपुर झिरका-दिल्ली-जहटाना
8.	नूहँ-पुन्हाना-बडकली-होडल-नूहँ
9.	नूहँ-नीमखेडा-शिकरवा-पुन्हाना
10.	नूहँ-पुन्हाना-होडल-नूहँ-उटावड
11.	नूहँ-पुन्हाना-बडकली-नूहँ

1	2
12.	नूहँ-पलवन-फिरोजपुर झिरका-गुडगांव
13.	नूहँ-उलेटा-गुडगांव-उलेटा
14.	नूहँ-सिरोली-धौला कुआं-फिरोजपुर झिरका
15.	नूहँ-सुंध-तावडू-होडल
16.	हथीन-नूहँ-फिरोजपुर झिरका
17.	बिछौर-गुडगांव-नूहँ-फिरोजपुर झिरका
18.	नूहँ-मेडिकल-कोर्ट
19.	पुन्हाना-फिरोजपुर झिरका-नूहँ (लडकियों के लिए)
20.	फिरोजपुर झिरका-मथुरा-गुडगांव
21.	पुन्हाना-अलवर-धौला कुआं-नूहँ
22.	पिनगंवा-धौला कुआं-अलवर-नूहँ
23.	जौरासी-तावडू-चण्डीगढ़
24.	जौरासी-धौला कुआं-फिरोजपुर झिरका
25.	पुन्हाना-चण्डीगढ़-गुडगांव
26	पुन्हाना-तिगांव-फिरोजपुर झिरका-गुडगांव
27.	पिनगांवा-गुडगांव-अलवर
28.	नूहँ-फिरोजपुर झिरका-नूहँ-चण्डीगढ़
29.	नूहँ-दिल्ली-अलवर-नूहँ
30.	नूहँ-झांडा-दिल्ली-अलवर-नूहँ
31.	नूहँ-बल्लभगढ़-अलवर-नूहँ
32.	नूहँ-अलवर-चण्डीगढ़-नूहँ
33.	नूहँ-अलवर-तिजारा-धौला कुआं-जयपुर-नूहँ
34.	नूहँ-अलवर-जयपुर-नूहँ
35.	नूहँ-दिल्ली-अलवर-जयपुर-नूहँ
36.	नूहँ-महेन्द्रगढ़-गुडगांव-अलवर-नूहँ
37.	नूहँ-यमुनानगर-नूहँ
38.	नूहँ-गुडगांव-अलवर-नूहँ
39.	नूहँ-पुन्हाना-दिल्ली-जयपुर-नूहँ
40.	नूहँ-धौला कुआं-जयपुर-नूहँ
41.	नूहँ-फिरोजपुर झिरका-दिल्ली-जयपुर-नूहँ
42.	नूहँ-गुडगांव-अलवर-नूहँ (विशेष)

1	2
43.	नूहँ-फिरोजपुर झिरका-गुडगांव-नूहँ-अलवर-नूहँ
44.	नूहँ-अलवर-धौला कुआं-फिरोजपुर झिरका-नूहँ
45.	नूहँ-गुडगांव-रोहतक-गुडगांव-फिरोजपुर झिरका-नूहँ
46.	नूहँ-पलवल-नूहँ-बल्लभगढ़-नूहँ
47.	नूहँ-फिरोजपुर झिरका-नूहँ-दिल्ली-चण्डीगढ़-शिमला-चण्डीगढ़-दिल्ली-नूहँ
48.	नूहँ-गुड़गांव-रोहतक-नरवाना-गुडगांव-नूहँ
49.	नूहँ-गुडगांव-रोहतक-जींद-गुडगांव-नूहँ
50.	नूहँ-भिवानी-नूहँ
51.	नूहँ-रेवाड़ी-सोहना-पलवल-मथुरा-गुडगांव-फिरोजपुर झिरका-नूहँ
52.	नूहँ-रेवाड़ी-नारनौल-रेवाड़ी-नूहँ
53.	नूहँ-कोसली-नूहँ-रेवाड़ी-नूहँ
54.	नूहँ-दिल्ली-अजमेर-नूहँ
55.	नूहँ-फिरोजपुर झिरका-नूहँ
56.	नूहँ-फिरोजपुर झिरका-सिरसा-नूहँ
57.	नूहँ-दादरी-नूहँ-अलवर-नूहँ
58.	नूहँ-गुडगांव-अलवर-नूहँ (कर्मचारी वर्ग)
59.	नूहँ-बल्लभगढ-फिरोजपुर झिरका

नूहँ आगार में उपलब्ध 96 बसों में से 89 से 90 बसें प्रतिदिन संचालित की जा रही हैं तथा शेष 6 से 7 बसों की कर्मशाला में मरम्मत/सर्विस/रखरखाव आदि की जाती है।

उपरोक्त के अलावा सहकारी परिवहन समितियों द्वारा निम्नलिखित मार्गों पर बस सेवाएं प्रदान की जा रही हैं:-

क्र० सं०	**मार्ग का नाम**	**संचालित बसों की संख्या**
1	तावडू से उटावट चौक वाया छारोडा, नूहँ, उजीना, मलाई	3
2	तावडू से फिरोजपुर झिरका वाया नूहँ, बडकाली चौक, माण्डीखेड़ा	2
3	तावडू से गुडगांव वाया शिकरपुर, सोहना, भौंडसी, बादशाहपुर	1
4	पलवल से पिनगवां वाया हथीन	5

वर्तमान में हरियाणा राज्य परिवहन, नूहँ (मेवात) में 96 बसों का बस बेडा है, जिन्हें उपरोक्त प्रथम तालिका में दिये गए 59 मार्गों पर बस सेवा के लिये संचालित किया जाता है।

————————

Construction of Building of Government Girls College in Pali

***1312. Dr. Banwari Lal :** Will the Education Minister be pleased to state—

(a) wheather it is a fact that the Govt. Girls College of Pali, District Rewari is functioning in the building of Government School at present; if so, the time by which building of the college is likely to be constructed; and

(b) the time by which the posts of teaching and non-teaching staff for said college are likely to be sanctioned and filled up?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) :

(क) हाँ, श्रीमान जी। भवन का निर्माण ग्राम पंचायत पाली (रेवाडी) की 70 कनाल 8 मरला भूमि का टुकड़ा उच्चतर शिक्षा विभाग को स्थानान्तरित होने उपरांत किया जाएगा।

(ख) श्रीमान जी, अध्यापन एवं गैर-अध्यापन अमले के पदों की स्वीकृति का प्रस्ताव वित्त विभाग के पास विचाराधीन है। जैसे ही पदों की स्वीकृति प्राप्त होगी, तदानुसार भर लिये जाएंगे।

———————

Problem of Water Logging

***1108 Smt. Naina Singh Chautala :** Will the Irrigation Minister be pleased to state:—

(a) Whether it is a fact that there is problem of water logging in about 500 acres of land due to damage in BMB canel passing through village Lakhuana (Dabwali constituency); if so, the action taken by the Government; and

(b) the compensation or relief given by the Government to the affected farmers alongwith details thereof ?

कृषि मंत्री (श्री ओमप्रकाश धनखड़) : श्रीमान जी, विवरणी सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरणी

गांव लखुआना में सेम की कोई समस्या नहीं है। हालांकि दिनांक 21.09.2015 को भाखड़ा मेन ब्रांच नहर की बुर्जी संख्या 413000 पर टूटने के कारण डबवाली निर्वाचन क्षेत्र के गांव लखुआना के समीप 81.50 एकड़ भूमि में फसलें नष्ट हो गई थी। मामला अभी भी विचाराधीन है। अब तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

———————

Shortage of Drinking Water

*** 1309. Shri Mahipal Dhanda :** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether it is a fact that there is a great shortage of drinking water in 79 unapproved colonies of Panipat Rural constituencey; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to provide the drinking water in the abovesaid unapproved colonies; if so, the time by which it is likely to be materialized ?

जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी राज्य मंत्री (श्री घनश्याम सर्राफ) : श्रीमान जी, 36 अस्वीकृत कालोनियों में पहले से ही 46 नलकूपों द्वारा जल आपूर्ति की जा रही है। 9 अस्वीकृत कालोनियों में जल आपूर्ति के लिए 4 नलकूप स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। शेष 34 अस्वीकृत कालोनियों में जल आपूर्ति के लिए नलकूपों की ड्रिलिंग करने हेतु भूमि उपलब्ध करने के लिए नगर निगम से कहा गया है।

To Upgrade Government Hospital Fatehabad

***1195. Shri Balwan Singh Daulatpuria :** Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade Government Hospital of Fatehabad from 100 beds to 200 beds; if so, the time by which it is likely to be upgraded ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : नहीं, श्रीमान जी।

Bus Service from Barwala to Hisar

***1136. Shri Ved Narang :** Will the Transport Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide direct Bus Service from Barwala city to Hisar for the Girl Students; if so, the details thereof ?

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : श्रीमान जी, नहीं।

Construction of Bridge

***1154. Shri Ravinder Baliala :** Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a bridge on Ghaggar River between village Baliala and Lali; if so, the time by which it is likely to be constructed?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : नहीं श्रीमान जी। इसलिए, यह सवाल ही नहीं उठता।

Upgradation of Schools

***1367. Shri Ranbir Gangwa :** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the middle school of villages Bure up to 10th class and the Girls School of village Gangwa up to 12th class; if so, the details thereof ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : श्रीमान जी, राजकीय कन्या विद्यालय, गंगवा को पहले ही राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विधालय के स्तर तक स्तरोन्नत किया जा चुका है। लेकिन, राजकीय माध्यमिक स्कूल, बूरे को स्तरोन्नत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

———————

To Open a Sub-Depot in Firozpur Jhirka

***1229. Shri Naseem Ahmed :** Will the Transport Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Sub-Depot of Haryana Roadways in Firozpur Jhirka ?

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : श्रीमान जी, नहीं।

Problem of Soil Salinity

***1235. Shri Rajdeep Phogat :** Will the Irrigation Minister be pleased to state whether it is a fact that about one thousand acreage of land of village Birhi and Barsana have become saline due to seepage in Loharu canal passing through abovesaid villages; if so, the steps taken or likely to be taken to rehabilitate the abovesaid land ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) :

(क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) इसलिए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

———————

New Sports Policy in the State

***1240. Shri Abhay Singh Chautala :** Will the Sports and Youth Affairs Minister be pleased to state —

(a) The facilities being provided to the players after the implementation of the new sports policy in the Government together with the gamewise details of medals received after the implementation of new sports policy; and

(b) Whether Coaches of all games togetherwith other facilities are available in the stadiums of villages; if so, the details thereof ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : श्रीमान जी, कथन सदन के पटल पर रखे जाते हैं।

कथन

(क) हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर 12 जनवरी, 2015 को रोहतक में हरियाणा खेल तथा शारीरिक उपयुक्तता नीति, 2015 जारी की है।

नि:शुल्क प्रशिक्षण, कोचिंग कैम्प, खेल अवसंरचना, खेल उपकरण प्रशिक्षण केन्द्रों पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। दिनांक 1-12-2015 से 117 स्पीड नर्सरियां शुरु की गई है। मैडलों का ब्यौरा निम्न अनुसार है:-

राष्ट्रीय खेलें-2015 केरल

खेल	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
एथलैटिक	04	04	06	14
बॉय हैण्डबाल	00	00	01	01
बैडमिन्टन	00	02	00	02
बॉक्सिंग	01	03	02	06
साईकलिंग	01	04	02	07
फुटबाल	00	00	01	01
फैंसिंग	00	01	00	01
जिमनास्टिक	00	01	00	01
वेटलिफिटंग	02	02	00	04
हैण्डबाल	01	00	00	01
हाकी	00	01	01	02
जूडो	02	04	05	11
कबड्डी	02	00	00	02
नैटबाल	02	00	00	02
रग्बी 7 एस	01	00	00	01
शूटिंग	02	09	04	15
तैराकी	02	03	00	05
ताइक्वांडो	02	02	03	07
कुश्ती	18	02	02	22
वुशू	0	02	00	02
कुल जोड़	**40**	**40**	**27**	**107**

राजीव गांधी खेल अभियान योजना के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिता 19 वर्ष से नीचे वर्ष 2015-16 में हरियाणा की खेल उपलब्धियां

क्र0 सं0	खेल	स्थान	स्वर्ण पदक	रजत पदक	कांस्य पदक	कुल	टिप्पणी
1.	हाकी लड़के	हरियाणा	01	00	00	01	प्रथम स्थान
	हाकी लड़कियां	हरियाणा	01	00	00	01	प्रथम स्थान
2.	हैंण्ड बाल लड़के	हरियाणा	01	00	00	01	प्रथम स्थान
	हैंण्ड बाल लड़कियां	हरियाणा	01	00	00	01	प्रथम स्थान
3.	धनुर्विद्या लड़की		00	00	05	05	तीसरा स्थान
4.	बॉक्सिंग लड़के	तमिलनाडू	05	01	09	09	प्रथम स्थान
	बाक्सिंग लड़कियां	तमिलनाडू	08	01	01	10	प्रथम स्थान
5.	एथलैटिक लड़के	आन्ध्रप्रदेश	03	01	10	14	दूसरा स्थान
	एथलैटिक लड़कियां	आन्ध्रप्रदेश	01	03	06	10	प्रथम स्थान
6.	वालीबाल लड़के	आन्ध्रप्रदेश	01	00	00	01	प्रथम स्थान
7.	फुटबाल लड़की	पांडीचेरी	01	00	00	01	प्रथम स्थान
8.	जूडो लड़के	पांडीचेरी	01	00	00	01	सम्पूर्ण विजेता
	जूडो लड़कियां	पांडीचेरी	04	03	02	09	सम्पूर्ण विजेता
9.	बास्केटबाल लड़के	तेलंगाना	01	00	00	01	प्रथम स्थान
	बास्केटबाल लड़कियां	तेलंगाना	00	01	00	01	दूसरा स्थान
10.	कुश्ती लड़के	तेलंगाना	06	00	00	06	प्रथम स्थान
	कुश्ती लड़कियां	तेलंगाना	10	00	00	10	प्रथम स्थान
11.	कबड्डी लड़के	गुजरात	01	00	00	01	प्रथम स्थान
	कबड्डी लड़कियां	गुजरात	00	01	01	02	दूसरा स्थान
	कुल		**47**	**16**	**28**	**91**	

राष्ट्रीय महिला खेल प्रतियोगिता आर0जी0के0ए0 वर्ष 2015-16 में हरियाणा की उपलब्धि

क्र0 सं0	खेल	स्थान	स्वर्ण पदक	रजत पदक	कांस्य पदक	कुल
1.	एथलैटिक	जम्मू कश्मीर	01	02	04	07
2.	बैडमिन्टन	जम्मू कश्मीर	01	01	00	02
3.	वालीबाल	पटियाला (पंजाब)	00	01	00	01
4.	हाकी	पटना (बिहार)	00	00	01	01
5.	हैण्डबाल	पटना (बिहार)	00	01	00	01
	कुल		**02**	**05**	**05**	**12**

(ख) गांव में खेल मैदानों पर दी जाने वाली सुविधाएं तथा गांव में नियुक्त प्रशिक्षकों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र0सं0	जिला का नाम	प्रशिक्षक का नाम	खेल	सैंटर/गांव
1	2	3	4	5
1.	पंचकुला	श्री श्याम सुन्दर	एथलैटिक्स	राजीव गांधी खेल परिसर, नग्गल
2.	पंचकुला	श्री अश्वनी शर्मा	कुश्ती	राजीव गांधी खेल परिसर, पपलोहा
3.	पंचकुला	श्रीमती कोमल चौधरी	फैन्सिंग	इम्पलोई एजुकेशन स्कूल, पिंजौर
4.	पंचकुला	श्री सन्दीप कुमार	हैण्डबाल	राजीव गांधी खेल परिसर, नटवाल
5.	कैथल	श्री चेतन शर्मा	जुडो	राजीव गांधी खेल परिसर, बाता
6.	कैथल	श्री राजेश कुमार	हैण्डबाल	राजीव गांधी खेल परिसर, क्योड़क
7.	कैथल	श्री सतनाम सिंह	एथलैटिक्स	डी0ए0वी0 कालेज, चीका
8.	कैथल	श्री अश्वनी कुमार	वॉलीबाल	जनता कालेज, कौल
9.	कैथल	श्री राजेन्द्र कुमार	बास्केटबाल	राजीव गांधी खेल परिसर, भाना
10.	कैथल	श्रीमती उषा	जिम्नास्टिक	राजीव गांधी खेल परिसर, फतेहपुर
11.	कैथल	श्री सन्दीप	हॉकी	राजीव गांधी खेल परिसर, मलिकपुर
12.	कैथल	श्री दवेन्द्र कुमार	कुश्ती	माता बस्ती अखाड़ा, चीका
13.	कैथल	श्री संजय कुमार	कुश्ती	राजीव गांधी खेल परिसर, भांगल
14.	कुरुक्षेत्र	श्री शमशेर सिंह	कुश्ती	कुश्ती हाल, गांव उमरी
15.	कुरुक्षेत्र	श्री गुरनाम सिंह	एथलैटिक्स	श्री गुरनानक प्रितम गर्ल्ज हाई, हाई स्कूल, शाहाबाद
16.	कुरुक्षेत्र	श्रीमती रजनी देवी	वॉलीबाल	राजीव गांधी खेल परिसर, अमीन
17.	कुरुक्षेत्र	श्री गुरबाज सिंह	हॉकी	मारकण्डेश्वर हाकी स्टेडियम, शाहाबाद
18.	कुरुक्षेत्र	श्री पंजाब सिंह	साईकलिंग	राजीव गांधी खेल परिसर, बाखली

1	2	3	4	5
19.	यमुनानगर	श्री नरेश कुमार	एथलैटिक्स	गुर्जर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, देवधर
20.	यमुनानगर	श्रीमती किरण गुलाटी	योग	गुर्जर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, देवधर
21.	यमुनानगर	श्री विदया नन्द	कबड्डी	राजीव गांधी खेल परिसर, लाधपुर
22.	झज्जर	श्री कृष्ण लाल	एथलैटिक्स	राजीव गांधी खेल परिसर, दुबलधन
23.	झज्जर	श्रीमती लक्ष्मीपंत	योग	होशियार सिंह स्टेडियम, बहादुरगढ़
24.	झज्जर	श्री नरेन्द्र कुमार	कुश्ती	रतन अखाड़ा, गांव मंडुठी
25.	झज्जर	श्री अनिल कुमार	जुडो	राजीव गांधी खेल परिसर, डिघल
26.	झज्जर	श्री कैलाश रोहिल	एथलैटिक्स	राजीव गांधी खेल परिसर, खड़कड़
27.	झज्जर	श्री कदम सिंह	कुश्ती	राजीव गांधी खेल परिसर, सिलानी
28.	झज्जर	श्रीमती पूनम रानी	वॉलीबाल	राजीव गांधी खेल परिसर, डीघल
29.	झज्जर	श्रीमती सुमन	हॉकी	होशियार सिंह स्टेडियम, बहादुरगढ़
30.	झज्जर	श्री सुदेश	कुश्ती	होशियार सिंह स्टेडियम, बहादुरगढ़
31.	झज्जर	श्रीमती शर्मिला	साईकलिंग	राजीव गांधी खेल परिसर, पलडा
32.	झज्जर	श्री राजबीर	कबड्डी	राजीव गांधी खेल परिसर, महराना
33.	झज्जर	श्रीमती सुमन	हैण्डबाल	राजीव गांधी खेल परिसर, बहराना
34.	झज्जर	श्री प्रदीप कुमार	फुटबाल	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भम्भेवा
35.	झज्जर	श्री रविन्द्र सिंह	तैराकी	राजीव गांधी खेल परिसर, मदनपुर
36.	झज्जर	श्री विरेन्द्र सिंह	कुश्ती	सतीश अखाड़ा, गांव ससरौली
37.	रोहतक	श्री राजेश कुमार	एथलैटिक्स	जय किशन मैमोरियल सी0सै0 स्कूल, कलानौर

1	2	3	4	5
38.	रोहतक	श्री सुखबीर सिंह	फुटबाल	राजीव गांधी खेल परिसर, मदीना
39.	रोहतक	श्री राजेश	हैण्डबाल	ऋषिकुल सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, बुसाना
40.	रोहतक	श्री प्रदीप गुलिया	कुश्ती	जुनियर कृष्णांट पब्लिक स्कूल कटेसरा
41.	रोहतक	श्री अशोक कुमार	कुश्ती	राजीव गांधी खेल परिसर, सुन्डाना
42.	रोहतक	श्री रवीन कुमार	कुश्ती	राजीव गांधी खेल परिसर, करौन्था
43.	सोनीपत	श्रीमती निर्मला	जिम्नास्टिक	राजीव गांधी खेल परिसर, सिसराना
44.	सोनीपत	श्री पाल	कबड्डी	राजीव गांधी खेल परिसर, खानपुर-स्पीड नर्सरी
45.	सोनीपत	श्री दविन्द्र सिंह दहिया	कुश्ती	प्रताप हाई स्कूल, स्पीड नर्सरी, खरखौदा
46.	सोनीपत	श्री मनोज कुमार	क्रिकेट	गुरुकुल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, मटिण्डु
47.	सोनीपत	श्री अमित सरोहा	एथलैटिक्स	रिजनल सैंटर, साई बहालगढ़
48.	सोनीपत	श्री मनोज कुमार	योग	राजीव गांधी खेल परिसर, सिसाना
49.	सोनीपत	श्री कुलबीर सिंह	कुश्ती	राजीव गांधी खेल परिसर, भटगांव
50.	सोनीपत	श्री रामनिवास	बॉक्सिग	राजीव गांधी खेल परिसर, मोहम्मदपुर-स्पीड नर्सरी
51.	सोनीपत	श्री यशबीर सिंह	भारोतोलन	राजीव गांधी खेल परिसर, हलालपुर
52.	सोनीपत	श्री कंवलजीत	तैराकी	राजीव गांधी खेल परिसर, गढ़ी
53.	सोनीपत	श्री राजेश कुमार	वुशू	राजीव गांधी खेल परिसर, जुआं
54.	सोनीपत	श्री गौरव	लॉनटैनिस	सर छोटूराम यूनिवर्सिटी, मुरथल
55.	सोनीपत	श्री दवेन्द्र	कुश्ती	राजीव गांधी खेल परिसर, पुरखास
56.	सोनीपत	श्री सुरजीत	बास्केटबाल	सर छोटूराम माडर्न सी0 सैकेण्ड्री स्कूल, रतनगढ़

1	2	3	4	5
57.	सोनीपत	श्री योगेन्द्र	बास्केटबाल	राजीव गांधी खेल परिसर, औरंगाबाद
58.	पानीपत	श्री चन्द्र पाल	कबड्डी	मिनी स्टेडियम, बुड़शाम
59.	पानीपत	श्री अनूप सिंह	एथलैटिक्स	राजीव गांधी खेल परिसर, बबैल
60.	पानीपत	श्री बंसी लाल	एथलैटिक्स	राजीव गांधी खेल परिसर, बापोली
61.	पानीपत	श्री अनुज जागलान	कुश्ती	राजीव गांधी खेल परिसर, इसराना
62.	पानीपत	श्री भूपेन्द्र सिंह	फुटबाल	राजकीय उच्च विद्यालय, सिवाह
63.	पानीपत	श्री विजेन्द्र	कुश्ती	राजीव गांधी खेल परिसर, आहर-इसराना
64.	पानीपत	श्री मनदीप	कुश्ती	राजकीय सी0 सै0 स्कूल, बुवाना लाखू
65.	पानीपत	श्री राजेश कौशिक	साईकलिंग	राजीव गांधी खेल परिसर, मडलौडा
66.	करनाल	श्री कर्मचन्द	कुश्ती	राजकीय सी0सै0 स्कूल, बोगोटा-स्पीड नर्सरी
67.	करनाल	श्री जयभगवान	कबड्डी	ब्रह्मानंद पब्लिक स्कूल, चोरकरसा
68.	करनाल	श्रीमती आशा रानी	वॉलीबाल	ब्रह्मानंद पब्लिक स्कूल, चोरकरसा
69.	करनाल	श्री सुरेन्द्र प्रताप	हॉकी	राजकीय सी0सै0 स्कूल, जयसिंह पुरा
70.	करनाल	श्री जयवीर	कुश्ती	राजीव गांधी खेल परिसर, घोघड़ीपुर
71.	जीन्द	श्री जुगमिन्द्र सिंह	हैण्डबाल	नवदीप स्टेडियम, नरवाना
72.	जीन्द	श्री जोगिन्द्र सिंह	कुश्ती	नवदीप स्टेडियम, नरवाना
73.	जीन्द	श्री जगदीश चन्द्र	कुश्ती	राजीव गांधी खेल परिसर, गंगोली
74.	जीन्द	श्री कृष्ण कुमार	हॉकी	चौ0 भरत सिंह मैमोरियल स्कूल, निडानी
75.	जीन्द	श्री दिलबाग सिंह	कुश्ती	दिलबाग सिंह कुश्ती अखाड़ा, निडानी

1	2	3	4	5
76.	जीन्द	श्री दलबीर सिंह	कबड्डी	राजीव गांधी खेल परिसर, अलेवा
77.	जीन्द	श्री ओम प्रकाश	जुडो	नवदीप स्टेडियम, नरवाना
78.	जीन्द	श्री बीरबल	एथलैटिक्स	राजीव गांधी खेल परिसर, सिलाखेड़ी
79.	जीन्द	श्री अनिल कुमार	बास्केटबाल	राजीव गांधी खेल परिसर, नन्दगढ़
80.	जीन्द	श्री विवेक कुमार	वॉलीबाल	राजीव गांधी खेल परिसर, अलेवा
81.	जीन्द	श्री सत्यवान	बाक्सिंग	नवदीप स्टेडियम, नरवाना
82.	जीन्द	श्री मनजोत कुमार	हैण्डबाल	नवदीप स्टेडियम, नरवाना
83.	जीन्द	श्री रामनिवास	कुश्ती	राजीव गांधी खेल परिसर, खरकबूरा
84.	जीन्द	श्री दीपक हुड्डा	फुटबाल	महाराजा जन्मजेय स्टेडियम, सफीदों
85.	जीन्द	श्री अनिल कुमार	कुश्ती	राजीव गांधी खेल परिसर, भोडिया
86.	फतेहाबाद	श्री जगजीत सिंह	हॉकी	राजीव गांधी खेल परिसर, स्पीड नर्सरी, गोरखपुर
87.	फतेहाबाद	श्री नरबीर सिंह	बॉक्सिंग	इन्दिरा गांधी कालेज, टोहाना
88.	फतेहाबाद	श्री सुबे सिंह	एथलैटिक्स	राजीव गांधी खेल परिसर, भोडिया
89.	फतेहाबाद	श्री ओम प्रकाश	क्रिकेट	राजीव गांधी खेल परिसर, भोडिया
90.	फतेहाबाद	श्री जगदीप सिंह	फुटबाल	राजीव गांधी खेल परिसर, भोडिया
91.	फतेहाबाद	श्रीमती सीमा रानी	जुडो	राजीव गांधी खेल परिसर, भोडिया
92.	फतेहाबाद	श्रीमती राजबाला	हॉकी	राजीव गांधी खेल परिसर, धामियां
93.	फतेहाबाद	श्री सूरज सिंह	वॉलीबाल	राजीव गांधी खेल परिसर, भट्टू कलां
94.	फतेहाबाद	श्री सुन्दर लाल	एथलैटिक्स	राजकीय सी0सै0 स्कूल, स्पीड नर्सरी बनगांव

1	2	3	4	5
95.	फतेहाबाद	श्री सतपाल सिंह	हैण्डबाल	राजीव गांधी खेल परिसर, समेन
96.	फतेहाबाद	श्री रफीक खान	एथलैटिक्स	राजीव गांधी खेल परिसर, पीली मंदोरी
97.	फतेहाबाद	श्री बलवंत सिंह	कुश्ती	राजीव गांधी खेल परिसर, भोडिया
98.	फतेहाबाद	श्री सत्यनारायण	कुश्ती	शमशेर अखाड़ा, नहला
99.	फतेहाबाद	श्री मनीष शर्मा	जिम्नास्टिक	राजीव गांधी खेल परिसर, भोडिया
100.	सिरसा	श्री राजेश कुमार	एथलैटिक्स	राजीव गांधी खेल परिसर, जमाल
101.	सिरसा	श्री सुरजीत सिंह	हैण्डबाल	राजकीय व0मा0 विद्यालय, मण्डी डबवाली
102.	सिरसा	श्री अशोक कुमार	हैण्डबाल	राजीव गांधी खेल परिसर, डबवाली
103.	सिरसा	श्री हरविन्द्र सिंह	हाकी	राजीव गांधी खेल परिसर, धोलपालिया
104.	सिरसा	श्री सुरेन्द्रजीत सिंह	हाकी	राजीव गांधी खेल परिसर, बालासर
105.	सिरसा	श्रीमती पूनम	कुश्ती	राजीव गांधी खेल परिसर, कंवर पुरा
106.	हिसार	श्री रामकेश	एथलैटिक्स	दीपचन्द मेमोरियल स्कूल, बिटमड़ा
107.	हिसार	श्री कुलदीप	एथलैटिक्स	आर्य भट्ट, पब्लिक स्कूल, हवनगढ़
108.	हिसार	श्री हैप्पी असीजा	साईकलिंग	राजीव गांधी खेल परिसर, प्रभुवाला
109.	हिसार	श्री कुलदीप मक्कड़	फुटबाल	राजकीय सी0सै0 स्कूल, मंगोली
110	हिसार	श्री सतपाल	हैण्डबाल	राजकीय सी0सै0 स्कूल, लाडवा
111	हिसार	श्री जगदीप	हाकी	राजकीय सी0सै0 स्कूल, बनदाहवी
112	हिसार	श्री बलविन्द्र सिंह	कबड्डी	राजकीय सी0सै0 स्कूल, सात रोड़ कलां
113	हिसार	श्री विष्णुदास	कुश्ती	राजीव गांधी खेल परिसर, सीसाई

1	2	3	4	5
114	हिसार	श्री राहुल सिंह	कुश्ती	राजकीय सी0सै0 स्कूल, भैणी अमीरपुर
115	भिवानी	श्री राजेन्द्र सांगवान	कुश्ती	सुभाष अखाड़ा, गांव सांगा
116	भिवानी	श्री श्यामसुन्दर	कुश्ती	राजीव गांधी खेल परिसर, धारेडु
117	भिवानी	श्री प्रितम सिंह	वालीबाल	राजीव गांधी खेल परिसर, चांदवास
118	भिवानी	श्री रविशंकर	बॉक्सिग	बाक्सिग अकेडमी, चरखीदारी
119	भिवानी	श्री विकास कुमार	कबड्डी	राजीव गांधी खेल परिसर, आदमपुर
120	भिवानी	श्रीमती शकुन्तला देवी	कबड्डी	जनता कालेज, चरखीदादरी
121	भिवानी	श्री राजेन्द्र शास्त्री	कुश्ती	नरेश अखाड़ा, बोन्द कलां
122	भिवानी	श्रीमती सोनिका	फुटबाल	राजकीय उच्च विद्यालय, अलखपुरा
123	भिवानी	श्री विनोद कुमार	एथलैटिक्स	राजीव गांधी खेल परिसर, बहल
124	भिवानी	श्री रमेश कुमार	कुश्ती	रणधीर अखाड़ा, बहल
125	भिवानी	श्री पवन कुमार	एथलैटिक्स	राजीव गांधी खेल परिसर, तोशाम
126	भिवानी	श्री विजेन्द्र	एथलैटिक्स	राजीव गांधी खेल परिसर, पेटावास
127	भिवानी	श्री रनदीप	कुश्ती	राजीव गांधी खेल परिसर, टिघाना
128	भिवानी	श्री नरेश	हैण्डबाल	मिनी स्टेडियम, कालूवाला
129	मेवात	श्री मनोज कुमार	बॉक्सिग	राजकीय सी0सै0 स्कूल, नगीना
130	मेवात	श्री नरेन्द्र सिंह	कुश्ती	जमाल अखाड़ा, गसेरा
131	गुड़गांव	श्री महाबीर सिंह	एथलैटिक्स	राजीव गांधी खेल परिसर, दौलताबाद
132	गुड़गांव	श्रीमती दीपा मलिक	एथलैटिक्स	राजीव गांधी खेल परिसर, दौलताबाद

1	2	3	4	5
133	गुड़गांव	श्री प्रवीण रंगा	क्रिकेट	राजीव गांधी खेल परिसर, दौलताबाद
134	गुड़गांव	श्री राजेन्द्र यादव	फुटबाल	राजकीय सी0सै0 स्कूल, गढ़ीहसारू
135	गुड़गांव	श्री संदीप	हैण्डबाल	राजीव गांधी खेल परिसर, पटौदी
136	गुड़गांव	श्री रमन	जूडो	राजीव गांधी खेल परिसर, दौलताबाद
137	गुड़गांव	श्री रामपाल	कोर्फबाल	राजकीय सी0सै0 स्कूल, कादीपुर
138	फरीदाबाद	श्री सुरेश कुमार	कुश्ती	लीलू अखाड़ा, बल्लभगढ़
139	रिवाड़ी	श्री शमशेर सिंह	एथलैटिक्स	राजीव गांधी खेल परिसर, मनेठी
140	रिवाड़ी	श्री विजेन्द्र कुमार	हैण्डबाल	राजीव गांधी खेल परिसर, गुरवारा
141	रिवाड़ी	श्री विरेन्द्र सिंह	हॉकी	ग्रामीण खेल परिसर, कनवाली
142	रिवाड़ी	श्री प्रियदत्त	कुश्ती	राजीव गांधी खेल परिसर, पंचोर
143	रिवाड़ी	श्री सतबीर	एथलैटिक्स	राजीव गांधी खेल परिसर, कोसली
144	रिवाड़ी	श्रीमती ममता देवी	बॉक्सिंग	राजीव गांधी खेल परिसर, कोसली
145	नारनौल	श्री प्रशांत राय	हैण्डबाल	राव प्रहलाद सिंह हाई स्कूल, महेन्द्रगढ़
146	नारनौल	श्री दिनेश शर्मा	कुश्ती	राजीव गांधी खेल परिसर, सिंहामा
147	नारनौल	श्री रविन्द्र	कुश्ती	राजकीय सी0सै0 स्कूल, अटेली मण्डी
148	नारनौल	श्री आनंद	हॉकी	राजीव गांधी खेल परिसर, छितरोली
149	नारनौल	श्री नरेश पाल	हैण्डबाल	स्वामी विवेकानंद उच्च विद्यालय, महरमपुर
150	नारनौल	श्री डी0पी0 सिंह	वॉलीबाल	राजकीय माध्यमिक स्कूल, घनोटा

———————

Construction of Road

***1290. Shri Makhan Lal Singla :** Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the road from Nattar to Sahidanwali upto Pashchim Phirni in Sirsa Assembly Constituency; if so, the details thereof ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : नहीं, श्रीमान जी, प्रश्न के इस भाग का सवाल उठता ही नहीं है।

Construction of Grain Market

***1250. Shri Naresh Kaushik :** Will the Agriculture Minister be pleased to state –

(a) Whether it is a fact that about 57 acreage of land has been acquired in village Balaur for the construction of grain market but a resolution has been passed by the gram panchayat against acquiring the said land;

(b) Whether it is also fact that the farmers of village Barahi are ready to give their land for which a resolution was passed by gram panchayat and which has been sent to Hon'ble Chief Minister on 09-02-2015; and

(c) if so, the action taken in this regard togetherwith the details thereof ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) :

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख) हां, श्रीमान जी।

(ग) गांव बालौर की भूमि, अनाज मंडी बहादुरगढ़ के विस्तार के लिए अधिग्रहण किये जाने की प्रक्रिया 09.07.2009 को शुरू कर दी गई थी। भूमि चयन समिति की सिफारिशों पर गांव बालौर/नया गांव की भूमि का चयन 21.02.2013 को फाईनल कर दिया गया था। भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत सैक्शन-4, सैक्शन-6 और सैक्शन-7 की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा क्रमश: दिनांक 13.08.2013, 25.06.2014 तथा 21.08.2014 को की गई थी। दोनों गांवों की पंचायतों के प्रस्तावों पर सरकार ने उपायुक्त, झज्जर से टिप्पणी मांगी थी। उपायुक्त, झज्जर ने अपने पत्र क्रमांक 833/एल0ए0सी0, दिनांक 21.01.2016 द्वारा रिपोर्ट दी कि गांव बराही की भूमि बाई-पास से दूर है तथा यह अनाज मंडी की स्थापना के उद्देश्य से बहुत व्यस्त है। जहां तक बालौर की भूमि के अधिग्रहण का प्रश्न है, जिला अधिकारियों ने रिपोर्ट दी कि गांव बालौर की भूमि अनाज मंडी की स्थापना के लिए उपयुक्त है।

भूमि अर्जन अधिकारी-कम-जिला राजस्व अधिकारी, झज्जर द्वारा 54 एकड़, 7 कनाल, 7 मरले भूमि के अधिग्रहण का पंचाट 29.02.2016 को घोषित किया जा चुका है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 68.02 करोड़ रुपये की राशि मुआवजे के भुगतान के लिए जमा करवाई जा चुकी है। अब तक 15.43 करोड़ रुपये की राशि 11 एकड़ भूमि के भू-स्वामियों को वितरित की जा चुकी है। इस प्रकार भूमि अर्जन की कार्यवाही पहले ही पूर्ण कर ली गई है।

Construction of Over Bridge

***1255. Shri Sri Krishan Hooda :** Will the PW(B&R) Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Over Bridge on Gohana-Meham road at Gohana; and

(b) if so, the time by which it is likely to be constructed?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) :

(क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) इसलिए यह सवाल ही नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

To Reduce Maternal Mortality/Infant Mortality

290. Shri Hari Chand Middha : Will the Health Minister be pleased to state-

(a) the rate of Maternal Mortality in the State for the period from 1-04-2015 to 29-02-2016;

(b) The rate of Infant Mortality in the State for the period from 1-04-2015 to 29-02-2016; and

(c) the steps taken or proposed to be taken by the Government to reduce Maternal Mortality and Infant Mortality in the State?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : श्रीमान जी,

(क) भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS, एस0आर0एस0) से समय-समय पर मातृ मृत्यु दर का आकलन करता है। नवीनतम सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एस0आर0एस0) बुलेटिन 2011-2013 के अनुसार, हरियाणा का मातृ मृत्यु दर अनुपात (एम0एम0आर0) 127 प्रति 1,00,000 जीवित जन्म है। राज्य में 1.04.2015 से 29.02.2016 तक अवधि के मातृ मृत्यु दर अनुपात के बारे में अलग से सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा सरकार के आन्तरिक सर्वेक्षण के अनुसार, राज्य में अप्रैल, 2014 से जनवरी, 2016 तक की अवधि के लिए अन्तिम आकलन के अनुसार, मातृ मृत्यु दर अनुपात 106 प्रति 1,00,000 जीवित जन्म है।

(ख) सितम्बर,2014 में प्रकाशित सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS, एस0आर0एस0) 2013 के अनुसार, हरियाणा का शिशु मृत्यु दर (IMR, आईएमआर) 41 प्रति 1000 जीवित जन्म है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2015-16 के लिए प्रकाशित नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 (NFHS-4,एनएफएचएस-4) के अनुसार, राज्य का शिशु मृत्यु दर (IMR, आईएमआर) 33 प्रति 1000 जीवित जन्म है। राज्य की 1.04.2015 से 29.02.2016 की अवधि की शिशु मृत्यु दर अलग से उपलब्ध नहीं है।

[श्री अनिल विज]

(ग) मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए राज्य ने अनेक उपाय किए हैं और इनमें से निम्न उल्लेखनीय हैं:—

- संस्थागत प्रसव दर बढ़ाने के लिए प्रयास:

  सैन्ट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, (सीआरएस CRS) के अनुसार राज्य में संस्थागत प्रसव दर 2006 में 49 प्रतिशत से बढ़कर 2015 में 89.1 प्रतिशत हो गई है। उल्लेखनीय है कि सरकारी संस्थाओं में प्रसव दर 2006 में 16.3 प्रतिशत से बढ़कर 2015 में 51.1 प्रतिशत हो गई है।

- राज्य में प्रसव सेवाएं प्रतिदिन 24 घण्टे प्रदान करने के लिए 391 स्वास्थ्य केन्द्रों को प्रसव स्थलों के रूप में, अतिरिक्त मानव संसाधन एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवा कर सुदृढ़ किया गया है।

- सीजेरियन सेवा और नवजात देखरेख सेवाएं प्रदान करने के लि 38 स्वास्थ्य संस्थानों को प्रथम रेफरल यूनिट (FRU, एफआरयू) के रूप में निर्धारित किया गया है। विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध न होने की स्थिति में मांग/अनुबंध आधार पर विशेषज्ञ चिकित्सक नियुक्त करके इन एफआरयू को सुदृढ़ किया गया है।

- प्रदेश में सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में सर्वोत्तम प्रसव सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य मुख्यालय अधिकारियों और जिला अधिकारियों द्वारा निरन्तर एवं औचक निरीक्षण किया जाता है।

- गर्भवती महिलाओं को प्रसव देखरेख सेवा के लिए घर से सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों में लाने और उन्हें वापस घर छोड़ने के लिए ठोस रेफरल परिवहन प्रणाली स्थापित की गई है।

- राज्य में संस्थागत प्रसवों को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं जैसे कि: 'जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम' (जे0एस0एस0के0), 'जननी सुरक्षा योजना' (जे0एस0वाई0) (भारत सरकार योजना) और 'जननी सुरक्षा योजना' (जे0एस0वाई0) (राज्य सरकार योजना) चलाई जा रही है।

- राज्य में 22 विशेष नवजात देखभाल इकाई (SMCU, एसएनसीयू), 66 नवजात स्थिरीकरण इकाई (NBSU, एनबीएसयू) और 318 नवजात देखरेख कार्नर (NBCC, एनबीसीसी) के माध्यम से केन्द्र आधारित नवजात देखरेख सेवा सुनिश्चित की गई है। 1.4.2015 से 20.2.2016 तक एसएनसीयू में कुल 22,400 नवजात शिशुओं को भर्ती किया गया है।

- 'आशा' द्वारा माताओं और नवजात शिशुओं के लिए गृह आधारित जन्म उपरान्त देखरेख (HBPNC, एचबीपीएनसी) सेवाएं प्रदान की जाती हैं। 1.4 2015 से 29.02.2016 तक कुल 2,61,220 परिवारों को ये सेवाएं प्रदान की गई हैं।

- शिशु एवं युवा बाल आहार (IYCF, आईवाईसीएफ) और गहन दस्त नियन्त्रण पखवाड़ा (IDCF, आईडीसीएफ) कार्यक्रमों के तहत 19 लाख परिवारों को परामर्श सेवाएं और 16 लाख परिवारों को ओआरएस पैकेट मुहैया करवाए गए।

- राज्य वैक्सिन से रोकथाम योग्य 9 रोगों के लिए नि:शुल्क टीकाकरण सेवाएं भी प्रदान कर रहा है।

एमएमआर और आईएमआर में और कमी करने हेतु नए प्रयास:

- गर्भवती महिलाओं में प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जिसके अन्तर्गत खून की अत्यधिक कमी का उपचार इंजेक्टेबल आयरन सूक्रोज द्वारा शुरु किया जा रहा है।

- अनीमिया ट्रैकिंग माड्यूल (एटीएम) के अनुसार, 2012-2013 में, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रसव के लिए भर्ती हुई कुल गर्भवती महिलाओं में से प्रसव के समय 24 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं में खून की अत्यधिक कमी पाई गई। इंजेक्टेबल आयरन सूक्रोज उपचार शुरू करने के बाद (अक्तूबर, 2013), स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं में खून की कमी का प्रतिशत घटकर 2015-2016 में 8 प्रतिशत (फरवरी 2016 तक) रह गया है।

- प्रसव के दौरान और बच्चे के जन्म के बाद की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए प्रसव कक्षों की गुणवत्ता में सुधार, राज्य मुख्यालय द्वारा व्यापक फील्ड दौरों के दौरान जिला प्राधिकारियों को विस्तृत जानकारी तथा साइट पर प्रशिक्षण देकर प्रसव कक्ष में सर्वोत्तम प्रक्रियाओं एवं संक्रमण रोकथाम के उपायों का पालन, औषधियों, उपकरणों, रिकार्ड के रख-रखाव तथा प्रसव कक्षों में कुशल स्टाफ की तैनाती आदि करके किया गया है। इस समय प्रसव केन्द्रों के लगभग सभी प्रसव कक्ष प्रसव के दौरान और प्रसव के तत्काल बाद गुणवत्तापूर्ण प्रसव सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

- राज्य अप्रैल, 2016 में रोटावायरस से सम्बन्धित दस्त के रोगियों की संख्या तथा मृत्यु दर की रोकथाम के लिए रोटावायरस वैक्सिन (आरवीवी) और पोलियो से दोहरी सुरक्षा के लिए इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सिन (आईवीवी) शुरू करने की योजना बना रहा है।

- राज्य के सभी 21 जिलों में स्पैशल न्यूबोर्न केयर युनिट (एस0एन0सी0यू0) के अतिरिक्त कंगारू मदर केयर यूनिट (KMCU, के0एम0सी0यू0) स्थापित किए जाने की योजना है।

- राज्य में इंडिया न्यूबोर्न एक्शन प्लान (INAP, आई0एन0ए0पी0) की सिफारिशें लागू की जा रही हैं।

[श्री अनिल विज]

० राज्य मातृ और शिशु मृत्यु की रिपोर्ट करने की प्रणाली (MIRDS, एमआईआरडीएस) और मातृ एवं शिशु मृत्यु समीक्षा प्रणाली का सुदृढ़ीकरण कर रहा है।

To Construct a Stadium

302. Shri Rajdeep Phogat : Will the Sports & Youth Affairs Minister be pleased to sate whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a sports stadium in Baund Town; if so, the time by which it is likely to be constructed ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : नहीं, श्रीमान जी।

Repair of Distributory of Siwani Canal

243. Shri Om Parkash Barwa: Will the Irrigation Minister be pleased to state whether it is a fact that Isharwal Distributory of Siwani Canal has been damaged; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the said distributory ?

कृषि मंत्री (श्री ओमप्रकाश धनखड़) : हां, श्रीमान जी। इसके अलावा में यह भी बताना चाहूंगा कि ईशरवाल डिस्ट्रीब्यूट्री की बुर्जी संख्या 0 से 67350 का निर्माण सन 1973-74 में हुआ था। यह डिस्ट्रीब्यूट्री सिवानी नहर की बुर्जी संख्या 63000 दाएं से निकलती है इसके प्रथम छोर पर डिस्चार्ज 68 क्यूसिक है और इससे ईशरवाल, तलवानी, कलाली, मंडौली कलां और मंडौली खुर्द आदि गांव लाभान्वित होते हैं। लगातार प्रवाह और काफी समय होने के कारण लाईनिंग की ईटों के जोड़ खुल गए हैं और बहुत ज्यादा लम्बाई बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। लाईनिंग की मरम्मत कराने में कोई फायदा नहीं है। इसलिए रिसाव को रोकने एवं पानी को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूट्री के पुनर्वास की तुरन्त आवश्यकता है। जिसके लिए ईशरवाल डिस्ट्रीब्यूट्री की बुर्जी संख्या 0 से 67350 तक का परियोजना अनुमान तैयार किया जा रहा है, जिसको अनुमोदित करवाया जाएगा। इस डिस्ट्रीब्यूट्री की परियोजना के अनुमान की स्वीकृति मिलते ही पुनर्निर्वासन का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

Illegal Possession of Land

330. Shri Jasbir Deswal: Will the Education Minister be pleased to state whether it is a fact that illegal possession has been made by a person on seven acreage of land of Government College of Safidon; if so, the details thereof ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : जी हां, श्रीमान जी। राजकीय महाविद्यालय, सफीदों की 56 कनाल 8 मरले भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है। यद्यपि राजकीय महाविद्यालय, सफीदों द्वारा श्री प्रेमचन्द गांगले, एच0सी0एस0 के फैसले के विरुद्ध अपील दायर की गई है। यह अपील आयुक्त हिसार मण्डल के न्यायालय में लम्बित है और आगामी सुनवाई की तिथि 19-04-2016 लगी है।

Camera Traps to Observe Wild Life

261. Shri Parminder Singh Dhull: Will the Forest Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact the Government has installed camera-traps to survey or observe wildlife at the Kalesar Nation Park; if so, when the project was undertaken together with the cost thereof: and

(b) the detailed list of the species trapped with the help of above said cameras so far together with species count as per the latest survey conducted along with the time when the survey was conducted?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) :

(क) हां, श्रीमान जी। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य कालेसर में तेंदुओं की पारिस्थितिक स्थिति का मूल्यांकन करने हेतु भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून की सहायता से कैमरे स्थापित करके एक अध्ययन करवाया गया है यह अध्ययन कुल 19,89,500/- (उन्नीस लाख नवासी हजार पांच सौ) रुपये की लागत के साथ वर्ष 2014-15 में क्रियान्वित किया गया।

(ख) कैमरा ट्रैपिंग में कुल 19 स्तनधारी प्रजातियां दर्ज की गई। तेंदुओं की आबादी लगभग 23 होने का अनुमान लगाया गया और प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 15 तेन्दुओं का घनत्व होने का अनुमान लगाया गया। अन्य प्रजातियों की गिनती नहीं की गई क्योंकि अध्ययन मुख्य रूप से कालेसर के जंगलों में तेदुओं की संख्या व घनत्व का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से किया गया था। यह सर्वेक्षण दिसम्बर, 2014 से अप्रैल, 2015 तक करवाया गया। कैमरे द्वारा ट्रैप की गई प्रजातियों की विस्तृत सूची निम्न प्रकार है:-

क्र०सं०	प्रजाति का नाम	वैज्ञानिक नाम
1	तेंदुआ	Panthera pardus
2	तेंदुआ बिल्ली	Prionailurus bengalensis
3	रस्टी स्पोटिड बिल्ली	Prionailurus rubiginosus
4	जंगली बिल्ली	Felis chaus

[श्री नरबीर सिंह]

5	गीदड़	Canis aureus
6	एशियाई हाथी	Elaphus maximus
7	चीतल	Axis axis
8	सांभर	Rusa unicolor
9	बार्किंग डीयर	Muntiacus muntjak
10	गोरल	Nemorhaedus goral
11	नीलगाय	Boselaphus tragocamelus
12	सेह	Hystrix indica
13	स्माल इंडियन सिविट	Viverricula indica
14	कॉमन पाम सीविट	Paradoxurus hermaphrodites
15	ग्रे लंगूर	Semnopithecus hector
16	रीसस मकाक	Macaca muatta
17	ग्रे नेवला	Hepestes edwardsii
18	जंगली सुअर	Sus scrofa
19	इंडियन खरगोश	Lepus nigricollis

इस क्षेत्र से रस्टी स्पोटिड बिल्ली पहली बार रिपोर्ट हुई है।

Up-gradation of Krishna Ayurvedic College, Kurukshetra

335. Dr. Pawan Saini: Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade Shri Krishna Ayurvedic College, Kurukshetra as University; if so, the time by which Shri Krishna Ayurvedic College, Kurukshetra is likely to be upgraded as university ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : हां, श्रीमान जी, कुरुक्षेत्र में आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में आवश्यक रूप रेखा तैयार करने का कार्य किया जा रहा है। क्योंकि मामला प्रस्ताव स्तर पर है, कोई विशेष समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र समय पर स्थापित करने के लिए प्रयास किया जाएगा।

Permission to Builders

339. Shri Karan Singh Dalal: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the name of Builders who have been given permission to carry on the works of construction of Housing Projects/Flats construction in the State during the year 2012 to till date;

(b) whether the builders at "a" above have allotted flats to the persons of economical weaker sections of the society;

(c) the names of such defaulting builders who have not allotted flats to EWS people; and

(d) the action taken against such defaulting builders?

मुख्य मंत्री (श्री मनोहर लाल) : महोदय,

(क) ऐसे बिल्डर, जिनको वर्ष 2012 से लेकर आज तक, प्लोटिड/ग्रुप हाउसिंग/अफोर्डेएबल ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं को विकसित करने हेतु लाइसेन्स प्रदान किए गए हैं, उनकी सूची **अनुबंध-क**, के रूप में संलग्न है।

(ख और ग) कुछ बिल्डरों द्वारा ग्रुप हाउसिंग कालोनियों में निर्धारित नीति के मापदण्डों अनुसार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के फ्लैटों का आवंटन किया जाना बाकी है, ऐसी ग्रुप आवासीय परियोजनाओं की सूची **अनुबंध-ख**, के रूप में संलग्न है।

(घ) दोषियों पर दिनांक 16.08.2013 की नीतिनुसार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के फ्लैटों के आवंटन के समय निम्नलिखित दरों के अनुसार जुर्माना लगाया जाता है:-

क्र0 सं0	श्रेणी	उच्चतम	उच्च	मध्यम और कम
(i)	एक मुश्त जुर्माना यदि आबंटन 31.12.2012 से पहले पूरा कर लिया गया हो	₹ 1 लाख	₹ 50,000/-	₹ 25,000/-
(ii)	एक मुश्त जुर्माना यदि आबंटन 31.12.2012 के बाद, परन्तु 30.06.2014 से पहले पूरा किया गया हो	₹ 2 लाख	₹ 1 लाख	₹ 50,000/-
(iii)	आवर्ती जुर्माना यदि आबंटन 30.06.2014 के बाद पूरा किया गया हो	₹ 1 लाख प्रति कालोनी, प्रति मास	₹ 30,000/- प्रति कालोनी, प्रति मास	₹ 25,000/- प्रति कालोनी, प्रति मास

दोषी बिल्डरों की सूची अनुबंध-ग, पर संलग्न है जिनसे या तो जुर्माना प्राप्त कर लिया या सूचित कर दिया गया है।

Annexure-A

List of Builders to whom licences have been granted for plotted/Group Housing /affordable Group Housing projects from the year 2012 till date

Sr.	Name of the Coloniser	City	Sector No.	License Granted for
1	Swiftrans InternationL Pvt. Ltd.	Rewari (Dharuhera)	24	Group Housing
2	Unitech Ltd.	Gurgaon	70	Group Housing
3	Minus Collections Pvt. ltd.	Faridabad	70	Plotted
4	Great Value HPL Infratech Pvt. Ltd.	Gurgaon	104	Group Housing
5	New Age Town Planners ltd. (Countrywide/BPTP)	Faridabad	77 & 78	Addl. Plotted
6	Prime IT Solution Pvt. Ltd.	Gurgaon	37-C	Affordable Group Housing
7	DLF Utilities Ltd.	Gurgaon	91 & 92	Addl. Plotted
8	Shree Vardhman Township Pvt. Ltd.	Kurukshetra	30	Plotted
9	Ashiana Realtech Pvt. Ltd.	Rewari (Dharuhera)	23	Group Housing
10	DLF New Gurgaon Homes Developers Pvt. Ltd.	Gurgaon	73	Addl. Plotted
11	Bestech India Pvt. Ltd. (Sh. Jagdish Khattar)	Gurgaon	79	Group Housing
12	RMS Estates Pvt. Ltd.	Gurgaon	107	Group Housing
13	Radhey Buildhome Pvt. Ltd.	Gurgaon	102,102A	Group Housing
14	Raheja Developers Pvt. Ltd.	Gurgaon-Sohana	11,14	Plotted
15	Ansal Properties & Infrastructure Ltd.	Gurgaon	67	Addl. Plotted
16	DLF Utilities Ltd.	Gurgaon	76,77	Plotted
17	Gold Developers P. Ltd. (Experion Dev's P. Ltd.)	Gurgaon	112	Addl. Group Housing
18	Aakarshan Estate Pvt. Ltd.	Gurgaon	102, 102 A	Group Housing
19	Aakarshan Estate Pvt. ltd.	Gurgaon	102A	Group Housing
20	Ansal Properties & Infrastructure Ltd.	Sonipat	61,62,63	Group Housing
21	Identity Buildtech Pvt. Ltd.	Gurgaon	103	Group Housing
22	Manglam Multiplex Pvt. Ltd.	Gurgaon	107	Group Housing
23	Juventus Estate Ltd.	Gurgaon	104	Group Housing
24	Mapsko Buidwell Pvt Ltd .	Gurgaon	78,79	Group Housing
25	AMD Estate Pvt. Ltd.	Dharuhera	23,34	Plotted
26	Balaji Builder Coloniser & Land Developers	Bhiwani (Dadri)	9	Plotted

27	DLF New Gurgaon Homes Developers Pvt. Ltd.	Gurgaon	86	Group Housing
28	Idyllic Resorts Pvt. Ltd.	Panchkula Ext. II	12	Plotted
29	Ambience Project & Infst. Pvt. Ltd.	Gurgaon	22	Group Housing
30	Chintels India Pvt. Ltd.	Gurgaon	109	Group Housing
31	Subhagya Coloniser Pvt. Ltd.	Ambala	4	Plotted
32	SN Realtors Pvt. Ltd.	Yamuna Nagar	Jagadhari	Plotted
33	DLF New Gurgaon Homes Developers Pvt. Ltd.	Gurgaon	76	Group Housing
34	Maryada Estate Pvt. Ltd.	Fatehabad	7	Plotted
35	Commander Realtors Pvt. Ltd.	Gurgaon	58,59,60,61,62	Plotted
36	Sepset Properties Ltd.	Gurgaon	106	Group Housing
37	Selene Constructions Pvt. Ltd. (India Bulls)	Gurgaon	103	Addl. Group Housing
38	Athena Infrastructure Ltd. (India Bulls)	Gurgaon	103	Addl. Group Housing
39	Juventus Estate Ltd.	Gurgaon	104	Addl. Group Housing
40	Juventus Estate Ltd.	Gurgaon	104	Addl. Group Housing
41	Florentine Estate of India Ltd.	Gurgaon	104	Group Housing
42	Empire Realtech Pvt. Ltd.	Gurgaon	106	Group Housing
43	Intime Promoters (TDI)	Sonipat	19	Group Housing
44	Navjyoti Overseas	Sonipat	61	Group Housing
45	Parsavnath Developers	Karnal	35	Plotted
46	Fantasy Buildwell	Gwal Pahari	2	Group Housing
47	Emaar MFG	Gurgaon	102	Group Housing
48	Uppal Housing (P) Ltd.	Gurgaon	78	Addl. Group Housing
49	Jai Shakti Builders	Faridabad	70	Group Housing
50	Airmid Developers Ltd.	Gurgaon	106	Group Housing
51	Shivnandan Buildtech	Gurgaon	99	Addl, Group
52	Green Developers	Fatehabad	6	Plotted
53	CSN Estates (P) Ltd.	Gurgaon	113	Addl. Group Housing
54	CSN Estates (P) Ltd.	Gurgaon	113	Addl. Group Housing
55	Puri Construction (P) Ltd.	Gurgaon	111	Addl. Group Housing
56	Uddar Gagan Properties Pvt.Ltd.	Rohtak	27-28	Plotted
57	Desert Moon Realtors Pvt.Ltd.	Gurgaon	103	Group Housing
58	Uddar Gagan Properties Pvt. Ltd.	Rohtak	27	Addl. Plotted
59	Sadan Realtech Pvt. Ltd.	Gurgaon	104	Group Housing
60	Uddar Gagan Properties Pvt.Ltd.	Rohtak	27	Addl. Plotted

61	Resolve Estate Pvt. Ltd.	Gurgaon	86	Addl. Group Housing
62	One Point Realty	Rohtak	37	Addl. Plotted
63	H.L. Residency Pvt. Ltd.	Bahadurgarh	37	Plotted
64	International Green Scapes Ltd.	Gurgaon	86	Group Housing
65	Herman Properties Ltd.	Ambala	42	Plotted
66	Emmar MGF Land Ltd.	Gurgaon	102	Group Housing
67	Konark Rajhans Estates Pvt.Ltd.	Panchkula Extn.	14	Group Housing
68	DLF New Gurgaon Homes Devos Pvt. Ltd.	Gurgaon	73	Addl. Plotted
69	SU Estates	Gurgaon	66	Addl. Group Housing
70	DLF Ltd.	Gurgaon	81	Group Housing
71	Orris Infrastructure Pvt. Ltd.	Gurgaon	85	Group Housing
72	Cadillac Buildwell	Bahadurgarh	15	Addl. Group Housing
73	SRS Real Estate	Palwal	6	Group Housing
74	Ansal Properties &Infrastructure	Panipat	19	Addl. Plotted
75	Planet Earth Estates Pvt. Ltd.	Gurgaon	99	Group Housing
76	Prime Zone Developers Pvt.Ltd.	Assandh	10	Plotted
77	Taneja Developers and Infrastructure	Panipat	36 & 39	Addl. Plotted
78	Ninex Developers	Gurgaon	76	Group Housing
79	DLF New Gurgaon Homes Developers	Gurgaon	63	Group Housing
80	CHD Developers Ltd.	Karnal	45	Addl. Plotted
81	1000 Trees Housing Pvt. Ltd.	Gurgaon	105	Group Housing
82	Ramprastha Estates	Gurgaon	37C, 37D	Plotted
83	Vipul Ltd.	Gurgaon	48	Addl. Plotted
84	Emaar MGF Land Ltd.	Gurgaon	112	Group Housing
85	Precision Realtors Pvt. Ltd.	Gurgaon	67A	Group Housing
86	Jindal Realty Pvt. Ltd.	Sonipat	33	Group Housing
87	Jop International Ltd.	Rohtak	28	Group Housing
88	Unitech Ltd.	Gurgaon	South City-II, 49,50	Addl. Plotted
89	Monex Infrastructure Pvt. Ltd.	Gurgaon	99A	Group Housing
90	S.K.G. Buildcon Pvt. Ltd.	Dharuhera	22	Group Housing
91	Raj Buildwell Pvt. Ltd.	Gurgaon	71	Group Housing
92	Media Video Ltd.	Yamuna Nagar	27,29	Group Housing
93	Ajay Enterprise Pvt. Ltd.	Faridabad	43	Group Housing
94	Adson Software Pvt. Ltd.	Gurgaon	61	Group Housing
95	Sun Breeze Builders & Developers Pvt. Ltd.	Panipat	40	Group Housing

96	DLF New Gurgaon Homes Developers	Gurgaon	93	Group Housing
97	Florentine Estate of India Ltd.	Gurgaon	104	Group Housing
98	Puri Construction Pvt. Ltd.	Gurgaon	111	Group Housing
99	S.N. Jee Buildwell Pvt. Ltd.	Dharuhera	3, 3A & 4	Plotted
100	Oxygen Realtors Pvt. Ltd.	Gurgaon	37C	Group Housing
101	Hasta Infrastructure Pvt. Ltd.	Gurgaon	99A	Group Housing
102	Delta Propcon Pvt. Ltd.	Gurgaon	36A	Group Housing
103	Blue Jays Realtech Pvt. Ltd.	Gurgaon	36A	Group Housing
104	Bestech India Pvt. Ltd.	Gurgaon	89A	Group Housing
105	Vatika Ltd.	Gurgaon	89A	Group Housing
106	Vatika Ltd.	Gurgaon	88A	Group Housing
107	International Land Developers Pvt. Ltd.	Gurgaon	33	Group Housing
108	Vatika Ltd.	Gurgaon	88A	Group Housing
109	Sterling Infrastructure Pvt. Ltd.	Gurgaon	79	Group Housing
110	Shree Dham Developers Pvt. Ltd.	Jind	7A	Plotted
111	Ansal Properties & Infrastructure Ltd.	Sonipat	63	Group Housing
112	Rurban Development Corporation Pvt. Ltd.	Palwal	7	Group Housing
113	Tulip Infratech Pvt. Ltd.	Sonipat	35	Addl. Group Housing
114	Anant Raj Industries Ltd.	Gurgaon	63A	Group Housing
115	Magnolia Propbuild Pvt. Ltd.	Panchkula	3,4 & 4A	Addl. Plotted
116	Experion Developers Pvt. Ltd.	Gurgaon	108	Plotted
117	Chintels India Pvt. Ltd.	Gurgaon	106,108 & 109	Addl. Plotted
118	Orris Infrastructure Pvt. Ltd.	Gurgaon	89-90	Plotted
119	Emaar MGF Land Ltd.	Gurgaon	77	Group Housing
120	Pyramid Buildtech Pvt. Ltd.	Faridabad	49	Group Housing
121	Raheja Developers Pvt. Ltd.	Gurgaon	99A	Group Housing
122	Planet Earth Estates Pvt. Ltd.	Gurgaon	99	Group Housing
123	Vatika Ltd.	Gurgaon	88B	Group Housing
124	Omaxe Ltd.	Bahadurgarh	3A& 14	Addl. Plotted
125	DLF Ltd.	Gurgaon	24,25,25A,26A & 28	Addl. Plotted
126	Florentine Estate of India Ltd.	Gurgaon	104	Group Housing
127	DLF New Gurgaon Homes Developers	Gurgaon	70A	Group Housing
128	Magnolia Propbuild Pvt. Ltd.	Pinjore-Kalka	3 & 4	Addl. Plotted
129	DSS Buildtech Pvt. Ltd.	Sohna	35	Group Housing

130	MVL Ltd.	Yamunanagar-Jagadhari	29	Plotted
131	Ansal Properties Infrastructure Ltd.	Gurgaon	67 & 67A	Addl. Plotted
132	Piyush Colonisers Ltd.	Palwal	8	Group Housing
133	Mapsko Builders Pvt. Ltd.	Sohna	2	Group Housing
134	Prime Time Infraprojects Pvt. Ltd.	Pataudi	84	Plotted
135	Oasis Buildhome Pvt. Ltd.	Gurgaon	88A & 89A	Group Housing
136	Puri Construction Pvt. Ltd.	Gurgaon	111	Group Housing
137	Vatika Ltd.	Gurgaon	89A	Group Housing
138	Omaxe Ltd.	Bahadurgarh	35	Group Housing
139	International Land Developers Ltd.	Sohna	36	Group Housing
140	Vatika Ltd.	Gurgaon	88B	Group Housing
141	Vatika Ltd.	Gurgaon	88B	Group Housing
142	Bestech India Pvt. Ltd.	Dharuhera	7	Addl. Plotted
143	Vatika Ltd.	Gurgaon	88A & 88B	Plotted
144	Omaxe Ltd.	Palwal	11,14	Addl. Plotted
145	Delta Propcon Pvt. Ltd.	Gurgaon	36A	Group Housing
146	Vaastu Infratech Pvt.Ltd.,	Karnal	35	Group Housing
147	Gwar Infra Pvt. Ltd.	Ratia	1 1	Plotted
148	Ozone GSP Infratech	Faridabad	31	Group Housing
149	Omaxe Ltd.	Bahadurgarh	15	Addl. Plotted
150	North Star Apartments Pvt. Ltd.	Gurgaon	84,85 & 90	Plotted
151	Sarv Realtors Pvt. Ltd.	Gurgaon	68	Group Housing
152	Sarv Realtors Pvt. Ltd.	Gurgaon	68	Group Housing
153	ROF Infrastructure & Housing Pvt. Ltd.	Sohna	36	Group Housing
154	Everlike Buildcon Pvt. Ltd.	Gurgaon	28	Group Housing
155	Pareena Infrastructure Pvt. Ltd.	Gurgaon	68	Group Housing
156	SRS Real Estate Ltd.	Palwal	6	Addl. Plotted
157	Aum Shri Hotels & Resorts Pvt. Ltd.	Sohna	33	Group Housing
158	Ansal Properties & Infrastructure Ltd	Sonipat	35-36	Addl. Plotted
159	Sharad Farms & Holdings Pvt. Ltd.	Rohtak	34-35	Addl. Plotted
160	Leo Agro Pvt. Ltd.	Gurgaon	99A	Group Housing
161	M.G. Estates Pvt. Ltd.	Nilokheri- Taraori	1	Plotted
162	M.G. Estates Pvt. Ltd.	Nilokheri-	1	Plotted
163	ARC Projects Pvt. Ltd.	YamunaNagar	39-39A	Group Housing
164	Landmark Infonet Pvt. Ltd.	Shahabad	9	Plotted
165	Nani Resorts & Floriculture Pvt.Ltd.	Gurgaon	102	Affordable Group Housing

166	Perfect Buildwell Pvt. Ltd.	Gurgaon	104	Affordable Group
167	Pivotal Infrastructure Pvt. Ltd.	Gurgaon	84	Affordable Group
168	Randhawa Construction Pvt. Ltd.	Sohna	2 &35	Affordable Group
169	PSL Infratech Pvt. Ltd.	Sohna	2	Group Housing
170	AVL Infrastructure Pvt. Ltd.	Gurgaon	36A	Affordable Group
171	Raheja Developers Pvt. Ltd.	Sohna	11 & 14	Addl. Plotted
172	Universe Heights (India) Pvt. Ltd.	Sohna	33	Group Housing
173	Prime Infradevelopers Pvt. Ltd.	Gurgaon	99A	Affordable Group
174	Jai Buildwell Pvt. Ltd.	Rewari	25	Group Housing
175	Praise Construction Pvt. Ltd.	Rewari	22	Group Housing
176	Jindal Reality Pvt. Ltd. & Ors.	Sonipat	33,34 & 35	Plotted
177	Roots Developers Pvt. Ltd.	Gurgaon	95A	Group Housing
178	VK Motors Pvt. Ltd.	Sohna	11	Affordable Group
179	NB Buildcon Pvt. Ltd.	Sohna	7	Group Housing
180	Goldsouk Infrastructure Pvt. Ltd.	Sohna	17	Group Housing
181	M2M Buildtech Pvt. Ltd.	Rohtak	27A	Group Housing
182	Goldsouk Infrastructure Pvt. Ltd.	Sohna	17	Addl. Plotted
183	Goldsouk Infrastructure Pvt. Ltd.	Sohna	17	Group Housing
184	Faith Buildtech Pvt. Ltd.	Sohna	35	Group Housing
185	Faith Buildtech Pvt. Ltd.	Sohna	35	Group Housing
186	Commander Realtors Pvt. Ltd.	Gurgaon	63A	Group Housing
187	Nucleus Conbuild Pvt. Ltd.	Gwal Pahari	2	Group Housing
188	Juventus Estates Ltd.	Gurgaon	104	Group Housing
189	Juventus Estates Ltd.	Gurgaon	104	Group Housing
190	Faith Buildcon Pvt. Ltd.	Sohna	4	Group Housing
191	Desi Construction Pvt. Ltd.	Sohna	5	Group Housing
192	Lotus Rea/tech Pvt. Ltd.	Gurgaon	111	Affordable Group
193	MVN Infrastructure Pvt. Ltd.	Sohna	5	Affordable Group
194	Santur Realtors Pvt. Ltd.	Gurgaon	3	Group Housing
195	Rambha Construction Pvt. Ltd.	Sohna	5	Group Housing
196	Signature Builders Pvt. Ltd.	Gurgaon	107	Affordable Group
197	DHL Infratech Pvt. Ltd.	Rohtak	27A	Group Housing
198	St. Pat ricks Realty Pvt. Ltd.	Sohna	29,30,32,33	Plotted
199	SRS Hitech Projects Ltd.	Faridabad	84	Affordable Group

200	S3 Buildwell Pvt. Ltd.	Faridabad	82	Affordable Group
201	H.L. Promoters Pvt. Ltd.	Bahadurgarh	37	Group Housing
202	Aster Infrahome Pvt. Ltd.	Gurgaon	90	Affordable Group
203	Aster Infrahome Pvt. Ltd.	Gurgaon	90	Affordable Group
204	Manira Developers Pvt. Ltd.	Gurgaon	81	Affordable Group
205	Shree Vardhman Developers Pvt. Ltd.	Sohna	2	Group Housing
206	CHD Developers Ltd.	Karnal	45	Addl. Plotted
207	Vatika Ltd.	Gurgaon	81,82,82A,83 & 84	Plotted
208	Breeze Builders & Developers Pvt. Ltd.	Sohna	33	Affordable Group
209	AAR Housing Pvt. Ltd.	Sohna	31	Affordable Group
210	Tulsiani Construction & Developers Ltd.	Sohna	35	Affordable Group
211	SRS Real Estate Ltd.	Palwal	7	Affordable Group
212	Anantraj Industries Ltd.	Gurgaon	63A	Addl, Plotted
213	Raheja Developers Ltd.	Gurgaon	99A	Group Housing
214	BM Gupta Developers Pvt. Ltd.	Rewari	26,27	Affordable Group
215	AVL Infrastructure Pvt. Ltd.	Gurgaon	36A	Affordable Group
216	Arete India Projects Pvt. Ltd.	Sohna	6	Affordable Group
217	Mahamaya Exports Pvt. Ltd.	Gurgaon	63A	Group Housing
218	Stanza Developers & Infrastructure Pvt. Ltd.	Panipat	19	Group Housing
219	Chintels India Ltd.	Gurgaon	106,108 & 109	Addl. Plotted
220	Emaar MGF Land Ltd.	Gurgaon	81	Group Housing
221	Alton Buildtech India Pvt. Ltd.	Gurgaon	88A,89A	Affordable Group
222	Sunrays Heights Pvt. Ltd.	Gurgaon	63A	Affordable Group
223	St. Pat ricks Realty Pvt. Ltd.	Sohna	32	Group Housing
224	Bluejays Realtech Pvt. Ltd.	Gurgaon	36A	Group Housing
225	Pivotal Infrastructure Pvt. Ltd.	Gurgaon	99	Affordable Group
226	Eco Green Ultra Home Pvt. Ltd.	Faridabad	19	Group Housing
227	DLF Ltd.	Gurgaon	78	Group Housing
228	DSC Estate Developer Pvt. Ltd.	Gurgaon	68	Group Housing
229	Faith Buildtech Pvt. Ltd.	Sohna	32	Group Housing
230	DLF Homes Developers Ltd.	Gurgaon	78	Group Housing
231	Pareena Infrastructure Pvt. Ltd.	Gurgaon	68	Group Housing
232	Hans Propcon Pvt. Ltd.	Gurgaon	68	Group Housing
233	Pareena Infrastructure Pvt. Ltd.	Gurgaon	68	Group Housing
234	Garg Villas Pvt. Ltd.	Sohna	2	Group Housing

235	Lord Venkateshwara Buildcon Pvt. Ltd.	Dharuhera	3	Group Housing
236	Santur Builders Pvt. ltd.	Sohna	2	Group Housing
237	Kashi Promoters Pvt. Ltd.	Bahadurgarh	3	Group Housing
238	Vatika Ltd.	Ambala	21,22,23 & 25	Plotted
239	Max Heights Township & Projects Pvt. Ltd.	Sonipat	35	Group Housing
240	M3M India Ltd.	Gurgaon	95	Group Housing
241	Kashi Promoters Pvt. Ltd.	Bahadurgarh	37	Affordable Group
242	Green Space Infraheights Pvt. Ltd.	Panchkula Extn-II	14	Affordable Group
243	Pareena Infrastructure Pvt. Ltd.	Gurgaon	99A	Affordable Group
244	Dwarkadhis Buildwell Pvt. Ltd.	Dharuhera	22 & 23	Addl. Plotted
245	Auric Homes Pvt. Ltd.	Faridabad	86	Affordable Group
246	Sterling Infrastructure Pvt. Ltd.	Gurgaon	79	Group Housing
247	GLS Infracon Pvt. Ltd.	Sohna	4	Group Housing
248	Premium Infracon Pvt. Ltd.	Hisar	MC	Plotted
249	GNEX Realtech Pvt. Ltd.	Bahadurgarh	36	Plotted
250	Manglam Multiplex Pvt. Ltd.	Gurgaon	65	Group Housing
251	Raheja Developers Ltd.	Sohna	14	Affordable Group
252	Pyramid Infratech Pvt. Ltd.	Gurgaon	70-A	Affordable Group
253	Ajay Enterprises	Faridabad	39	Group Housing
254	Pareena Infrastructure Pvt. Ltd.	Gurgaon	68	Group Housing
255	CHD Developers Ltd.	Karnal	45	Affordable Group
256	H.L. Promoters Pvt. Ltd.	Bahadurgarh	37	Group Housing
257	Tarang Resorts Pvt. Ltd.	Faridabad	88	Affordable Group
258	Manglam Multiplex Pvt. Ltd.	Gurgaon	65	Group Housing
259	Countrywide Promoters Pvt. Ltd.	Gurgaon	102	Group Housing
260	Parsvnath Developers Ltd.	Sohna	2	Plotted
261	Sidhartha Buildtech Pvt. Ltd.	Gurgaon	110	Group Housing
262	Jagran Agents Pvt. Ltd.	Kurukshetra	29,30	Addl. Plotted
263	Signature Builders Pvt. Ltd.	Gurgaon	107	Addl. Affordable
264	DlF Homes Developers Ltd.	Gurgaon	28	Group Housing
265	Ramsons Organics Pvt. Ltd.	Gurgaon	95	Affordable Group
266	Premium Infratech Pvt. Ltd.	Gurgaon	69	Affordable Group
267	Victory Buildestate Pvt. Ltd.	Rewari	27	Affordable Group
268	DSC Estate Developer Pvt. Ltd.	Gurgaon	68	Group Housing
269	Sarv Realtors Pvt. Ltd.	Gurgaon	68	Group Housing
270	Sarv Realtors Pvt. Ltd.	Gurgaon	68	Group Housing

271	Revital Reality Pvt. Ltd.	Gurgaon	78-79A	Plotted
272	Sarvpriya Securities Pvt. Ltd.	Gurgaon	71	Affordable Group
273	GPM Developers Pvt. Ltd.	Faridabad	63	Group Housing
274	Lord Venkateshwara Buildcon Pvt. Ltd.	Dharuhera	3	Group Housing
275	Parsvnath Developers Ltd.	Karnal	35	Plotted
276	Max Heights Promotors Pvt. Ltd.	Sonipat	61	Affordable Group
277	H.L. Residency Pvt. Ltd.	Bahadurgarh	37	Addl. Plotted
278	Regards Developers Pvt.Ltd.	Sonipat	63	Group Housing
279	SRS Retreat Services Ltd.	Faridabad	87	Affordable Group
280	Shyam Kirpa Infrastructure Pvt.Ltd.	Gurgaon	109	Affordable Group
281	Ansal ousing & Construction Ltd.	Yamuna Nagar	20	Plotted
282	Oasis Buildhome Pvt. Ltd.	Gurgaon	88A	Group Housing
283	MG Housing Pvt. Ltd.	Dharuhera	19&24	Plotted
284	M3M India Ltd.	Gurgaon	95	Group Housing
285	Pyramid Infratech Pvt. Ltd.	Gurgaon	86	Affordable Group
286	Athena Infrastructure Ltd.	Gurgaon	105	Group Housing
287	Baderwals Infrastructure Pvt. Ltd.	Mahendergarh	11,10	Plotted
288	JMK Holding Pvt. Ltd.	Gurgaon	103	Affordable Group
289	Omaxe Ltd.	Rohtak	22D	Plotted
290	S3 Infra realty Pvt. Ltd.	Faridabad	82	Affordable Group
291	DLF New Gurgaon Homes Developers	Gurgaon	69	Group Housing
292	Shiv Mega Projects Pvt. Ltd.	Bawal	lOA	Affordable Group
293	Metro Technobuild Pvt. Ltd.	Sohna	2	Group Housing
294	Revital Reality Pvt. Ltd.	Gurgaon	79B	Affordable Group
295	Revital Reality Pvt. Ltd.	Gurgaon	79, 79B	Affordable Group
296	Fantabulous Town Planner Pvt. Ltd.	Faridabad	88,89	Plotted
297	Sharad Farms & Holdings Pvt. Ltd.	Rohtak	34,35,36	Addl. Plotted
298	Suncity Projects Pvt. Ltd.	Gurgaon	102	Affordable Group
299	Santur Spaces Pvt. Ltd.	Karnal	35	Affordable Group
300	Dream Merchant Promoters Pvt. Ltd	Dharuhera	7A	Group Housing
301	USG Promoters Pvt. Ltd.	Nilokheri-Taraori	16	Affordable Group
302	Pandit Land and Infrastructure Pvt. Ltd.	Yamuna Nagar	20	Group Housing
303	Vatika Ltd.	Gurgaon	88A & 88B	Addl, Plotted
304	RMG Developers Pvt. Ltd.	Gurgaon	37C	Affordable Group
305	Agarsain Spaces LLP	Faridabad	70	Affordable Group
306	Signature Builders Pvt. Ltd.	Gurgaon	93	Affordable Group
307	AEGIS Value Homes Ltd. (JD Universal)	Karnal	32A	Affordable Group

Annexure-B

List of such defaulting builders of group housing colonies who have not allotted flats to EWS catagory as per the prescribed parameters.

Sr. No.	Name of the Coloniser	City	Sector No.	Area in acres	Licence No. and Date	Building Plans approval date	No. of EWS Flats Appr-oved	Status of Occupation Certifi-cate
1	Swiftrans International Pvt. Ltd.	Rewari (Dharuhera)	24	10.343	1/12.1.2012	12.03.2012	126	Not granted
2	Great Value HPL Infratech Pvt. Ltd.	Gurgaon	104	3.631	10/3.2.2012 in licence no. 63 of 2011	26.06.2012	79	Not granted
3	Bestech India Pvt. Ltd. (Sh. Jagdish Khattar)	Gurgaon	79	10.1	22/27.3.2012	16.04.2014	92	Not granted
4	RMS Estates Pvt. Ltd.	Gurgaon	107	18.0625	23/27.3.2012	17.01.2013	169	Not granted
5	Aakarshan Estate Pvt. Ltd.	Gurgaon	102, 102A	15.72	29/10.4.2012	10.10.2012	134	Not granted
6	Aakarshan Estate Pvt. Ltd.	Gurgaon	102A	3.518	30/10.4.2012 including licence no. 29 of 2012	10.10.2012		Not granted
7	Manglam Multiplex Pvt. Ltd.	Gurgaon	107	18.8813	33/t2.4.2012	12.12.2014	175	Not granted
8	Juventus Estate Ltd.	Gurgaon	104	4	37/22.4.2012	06.06.2014	0	Not granted
9	Mapsko Buidwell Pvt. Ltd	Gurgaon	78, 79	16.369	38/22.4.2012	20.09.2012	150	Not granted
10	Ambience Project & Infst. Pvt. Ltd.	Gurgaon	22	14.819	48/12.5.2012	20.05.2014	143	Not granted
11	DLF New Gurgaon Homes Developers Pvt Ltd	Gurgaon	76	10.059	55/24.5.2012	01.09.2014	94	Not granted
12	Sepset Properties Ltd.	Gurgaon	106	13.762	61/13.6.2012	29.12.2012	132	Not granted
13	Juventus Estate Ltd.	Gurgaon	104	1.28125	66/21.6.2012	06.06.2014	180	Not granted
14	Juventus Estate Ltd.	Gurgaon	104	2.5	67/21.6.2012 including licence no. 37 of 2012 and 66 of 2012	06.06.2014		Not granted
15	Florentine Estate of India Ltd.	Gurgaon	104	15.337	68/21.6.2012	17.01.2013	115	Not granted
16	Navjyoti Overseas	Sonipat	61	3.16	72/7.7.2012 including licence no.79 of 2008	12.03.2013	166	Not granted

17	Fantasy Buildwell	Gwal Pahari	2	10.096	74/31.7.2012	20.12.2012	27	Not granted
18	Emaar MGF	Gurgaon	102	13.531	75/31.7.2012	22.01.2013	119	Not granted
19	Uppal Housing (P) Ltd.	Gurgaon	78	7.342	77/1.8.2012 Including licence no. 38 of 2008	04.03.2013	180	Not granted
20	Jai Shakti Builders	Faridabad	70	10.1	78/1.8.2012	15.05.2015	110	Not granted
21	Shivnandan Buildtech	Gurgaon	99	1.289	82/27.8.2012 including licence no. 70 of 2011	29.12.2011	110	Not granted
22	CSN Estates {P} Ltd.	Gurgaon	113	8.875	85/29.8.2012	02.04.2013	117	Not granted
23	CSN Estates{P} Ltd.	Gurgaon	113	1.99375	86/29.8.2012 including licence no.85 /29.8.2012 & 105 of 2011	02.04.2013	1	Not granted
24	Puri Construction {P} Ltd.	Gurgaon	111	4.268	87/29.8.2012	19.02.2015	138	Not granted
25	Desert Moon Realtors Pvt. Ltd.	Gurgaon	103	10.919	94/5.9.2012	27.02.2013	104	Not granted
26	Sadan Realtech Pvt. Ltd.	Gurgaon	104	15.331	98/7.9.2012	06.05.2013	133	Not granted
27	Resolve Estate Pvt. Ltd.	Gurgaon	86	5.119	100/7.9.2012 including licence no. 48 of 2011	03.09.2013	171	Not granted
28	International Green Scapes Ltd.	Gurgaon	86	6.475	104/6.10.2012	19.08.2015	154	Not granted
29	Emmar MGF Land Ltd.	Gurgaon	102	12	107/ 10.10.2012	26.02.2013	103	Not granted
30	Konark Rajhans Estates Pvt. Ltd.	Panchkula Extn.	14	10.081	108/12.10.2012	11.08.2014	120	Not granted
31	SU Estates	Gurgaon	66	0.90625	113/5.11.2012 including licence no. 20 of 2008 114/ 15.11.2012 including licence no. 61 of 2011	26.11.2013	104	Not granted
32	DLF Ltd.	Gurgaon	81	10.563		16.01.14	163	Not granted
33	Orris Infrastructure Pvt. Ltd.	Gurgaon	85	10.043	115/16.11.2012	18.03.2013	84	Not granted
34	Planet Earth Estates Pvt. Ltd.	Gurgaon	99	10.0313	119/6.12.2012	22.10.2014	0	Not granted

35	Ninex Developers	Gurgaon	76	3.4875	122/13.12.2012	26.11.2015	137	Not granted
36	1000 Trees Housing Pvt. Ltd.	Gurgaon	105	13.078	127/27.12.2012	15.07.2013	116	Not granted
37	Emaar MGF Land Ltd.	Gurgaon	112	10.744	4/18.2.2013	02.05.2014	68	Not granted
38	Precision Realtors Pvt.	Gurgaon	67A	37.5125	5/21.2.2013	23.07.2013	315	Not granted
39	Jindal Realty Pvt. Ltd.	Sonipat	33	13.644	6/4.2.2013	09.02.2015	138	Not granted
40	Jop International Ltd.	Rohtak	28	6.0875	7/4.2.2013	18.02.2014	78	Not granted
41	Monex Infrastructure Pvt. Ltd.	Gurgaon	99A	10.5875	10/12.3.2013	25.07.2013	96	Not granted
42	S.K.G. Buildcon Pvt. Ltd.	Dharuhera		13.237	13/18.3.2013	14.07.2014	168	Not granted
43	Ajay Enterpriese Pvt. Ltd.	Faridabad	43	52.825	20/17.5.2013	23.01.2014	312	Not granted
44	SunBreeze Builders & Developers Pvt. Ltd.	Panipat	40	11.531	27/17.5.2013	22.01.2014	122	Not granted
45	DLF New Gurgaon Homes Developers	Gurgaon	93	12.153	28/17.5.2013	13.03.2014	120	Not granted
46	Puri Construction Pvt. Ltd.	Gurgaon	111	1.29375	33/25.5.2013 Including licence no. 55 of 2010 & 87 of 2012	19.02.2015	138	Not granted
47	Hasta Infrastructure Pvt. Ltd.	Gurgaon	99A	11.5875	37/3.6.2013	26.05.2014	92	Not granted
48	Blue Jays Realtech Pvt. Ltd.	Gurgaon	36A	25.1	39/4.6.2013	29.08.2014	104	Not granted
49	Bestech India Pvt. Ltd.	Gurgaon	89A	24.7475	40/4.6.2013	16.04.2014	237	Not granted
50	Vatika Ltd.	Gurgaon	89A	14.3	41/6.6.2013	17.10.2014	112	Not granted
51	Vatika Ltd.	Gurgaon	88A	10.1	42/6.6.2013	25.07.2014	51	Not granted
52	International Land Developers Pvt. Ltd.	Gurgaon	33	11.6125	44/4.6.2013	12.03.2015	126	Not granted
53	Vatika Ltd.	Gurgaon	88A	14.025	46/6.6.2013	18.06.2015	134	Not granted
54	Sterling Infrastructure	Gurgaon	79	14.5938	47/6.6.2013	20.08.2014	197	Not granted

Annexure-C

Licencees from whom composition charges have been recovered/to be recovered for delay in allotment of EWS flats

Sr. No.	Name of the coloniser	City	Sector No.	Area in acres	Licence No and Date	Building Plans approval date	No. of EWS Flats approved	Status of Occupation Certificate	Status of allotment	Action taken
1	Identity Buildtech Pvt. Ltd.	Gurgaon	103	11.7	32/12.4.2012	14.06.2013	110	Not granted	Allotted	Composition fee of Rs. 2 lac recovered
2	DLF New Gurgaon Homes Developers Pvt Ltd.	Gurgaon	86	2.79	44/5.5.2012 including licence no. 31 of 2010	12.12.2012	120	Not granted	Allotted	Composition fee of Rs. 2 lac recovered
3	Chintels India Pvt. LTd.	Gurgaon	109	8.294	50/17.5.2012 including licence no. 250 of 2007	26.07.2013	139	Not granted	Allotted	Composition fee of Rs. 8 lac recovered
4	Selene Constructions Pvt Ltd. (India Bulls)	Gurgaon	103	3.025	63/19.6.2012 including licence no. 252 of 2007, 50 of 2011	18.04.2013	182	Not granted	Allotted	Composition fee of Rs. 4 lac conveyed for recovery
5	Athena Infrastructure Ltd. (India Bulls)	Gurgaon	103	3.256	64/20.6.2012 including 213 of 2007 & 10 of 2011	23.08.2013	83	Not granted	Allotted	Composition fee of Rs. 4 lac conveyed for recovery
6	Empire Realtech Pvt. Ltd.	Gurgaon	106	12.344	69/3.7.2012	17.09.2012	114	Not granted	Allotted	Composition fee of Rs. 7 lac recovered
7	Oxygen Realtors Pvt. Ltd.	Gurgaon	37C	1.3711	35/31.5.2013 including licence no. 34 of 2010	22.08.2014	139	Not granted	Allotted	Composition fee of Rs. 11 lac conveyed for recovery

Theft of Vehicles in the State

319. Dr. Hari Chand Middha: Will the Chief Minister be pleased to state the number of cases related to theft of vehicles registered in the State during the period from December, 2014 to February, 2016 togetherwith the district-wise details thereof alongwith the total number of vehicles recovered by the police?

मुख्य मंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान जी, वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

जिला	वाहन चोरी	
	दर्ज मुकदमें	बरामद किये गये वाहन
गुड़गांव	4456	565
फरीदाबाद	1927	295
अम्बाला-पंचकूला	606	183
हिसार	1010	305
सिरसा	316	76
भिवानी	474	157
जीन्द	447	95
फतेहाबाद	243	87
रेवाड़ी	887	69
पलवल	906	70
नारनौल	235	69
मेवात	366	68
रोहतक	784	184
सोनीपत	630	187
पानीपत	836	133
झज्जर	656	132
करनाल	757	182
यमुनानगर	605	185
कुरुक्षेत्र	587	151
कैथल	333	90
रेलवेज	81	17
कुल योग	**17142**	**3300**

Historical Shameshwar Pond

303. Shri Rajdeep Phogat: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to revive the Historical Shameshwar Pond of Dadri city: if so, the time by which it is likely to be revived?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : नही, श्रीमान जी।

---

318. Shri Parminder Singh Dhull: Will the Industries and Commerce Minister be pleased to State—

(a) the number of Industrial/commercial/residential/plots allotted in industrial estate/IMT surrendered to HSIIDC during the period from 31.10.2014 to 31.12.2015 together with reason thereof and the price of allotment of these plots: and

(b) the number of person to whom the amount has been refunded togetherwith detail thereof ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : हां, श्रीमान जी।

(क) आठ नं० आवासीय व व्यावसायिक प्लाटो का विवरण विस्तार से अनुबंध-1 पर है।

(ख) 31-10-2014 से लेकर 31-12-2015 तक की अवधि के दौरान 129 औद्योयागिक प्लाटों को एच०एस०आई०आई०डी०सी० को वापस कर दिये गये है। इन प्लाटो को वापस करने के कारण व प्लाटो की कीमत का विवरण अनुबंध-।। में दिया गया। उक्त 129 प्लाटों में से सिर्फ एक प्लाट को छोड़कर सभी मामलो में निगम द्वारा, नीति अनुसार राशि वापस कर दी गई है। जिसका ब्यौरा अनुबंध-।। में भी दिया गया है।

Annexure-1

Residential & Commercial

Sr. No.	Category	Plot No.	Size in sp. Mtr.	Estate/ IMT	Price of Allotment	Reason	Remarks
1.	Residential	277	450	IMT Barwal	1,14,97,950/-	Allottee not in a position to pay the balance amount	Refund under process.
2.	Commercial	D-19	108	IMT Manesar	3,02,00,000/-	Financial problems	Refunded.
3.	Commercial	D-02	75.625	IMT Bawal	32,21,960/-	Loses in business & Health Problem	Refund under process.
4.	Commercial	D-30	75.625	IMT Bawal	81,95,000/-	Not able to make payment of installment due to Financial problem	Refund under process.
5.	Commercial	D-31	75.625	IMT Bawal	81,95,000/-	Not able to make payment of installment due to Financial problem	Refund under process.
6.	Commercial	Deptt. Store-18	563.75	IMT Bawal	2,97,00,000/-	Poor customer base and lack of proper intra	Refund. under process.
7.	Commercial	89	22.85	IE Kundli	26,00,000/-	Personal problem	Refunded.
8.	Commercial	02	48	Old IDC Rohtak	26,00,000/-	Not able to make payment of installment due to domestic problem	Refunded.

Annexure-II

HARYANA STATE INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPN. LIMITED LIST OF SURRENDER OF PLOTS FROM 31.10.2014 TO 31.12.2015

Sr. No.	Name of Applicant	Estate/ Sector/Phase	Plot No.	Rate Of (Allotment In Rs. Per SQM)	Reason For Surrender	Net Amount (In Rs.)
1	Amit Singhal	Bahadurgarh-16	P-184	2000	Not Able To Continue Due To Some Personal Problem.	809708
2	Sikka Overseas Pvt. Ltd.	Bahadurgarh-17	P-160	2000 Rate of Allotment	Not Interested	810249
3	Prime Banox	Bahadurgarh-4b	P-31	5500	Not Interested To Retain The Bigger Size Plot.	21716138
4	M/S. Emergence Engineers Pvt. Ltd.	Bawal Sector 14, Phase-II A IV,IMT	59	5000	General Economy Downtrend.	6949349
5	M/S. Mushashi Paint India Pvt. Ltd.	Bawal Sector 14, Phase-II,IMT	56,57, 58	5000	No reason mentloneded.	56255905
6	M/S. Verdant Energy Pvt. Ltd.	Bawal Sector 14, Phase-IV Ltd., IMT	62	5500	Size not suitable for unit as per requirement.	7853826
7	Smt. Manju Sharma	Bawal Sector 15, Phase- II,IMT	5-A	5500	Not Interested for setting up the project.	1378867
8	Smt. Manisha Suri	Bawal Sector 15, Phase-II, IMT	6-A	5500	No reason mentloneded.	1392194
9	M/S. Enexco Teknologles India Ltd.	Bawal Sector 15, Phase-IV,IMT	76-77	5000	Slow down adverse economic and market conditions.	107192015
10	Sh. Ramesh Kumar	Bawal Sector 3, Phase-I, IMT	252	6137	Not Interested as per future plans.	3023172
11	M/S. Multi Kenzai Steel Pvt. Ltd.	Bawal sector 3, Phase- IV, IMT	369	5000	Economic crises In the country/ market slow down	7397357
12	M/S. International Coil Limited	Bawal Sector 5, Phase-IV, IMT	18	4000	General economy downtrend .	76590494
13	Sh. Mahesh	Bawal Sector 9, Phase-III, IMT	35	5500	Not Interested for setting up the project.	392500

14	Sh. Jaibir Rathl	Bawal Sector 9, Phase-III, IMT	76	5500	Size not suitable for unit as per requirement.	618750
15	Sadhu Forging Ltd.	Faridabad·68IMT	P·32	9000	Due to overallindustrtal recession, especially In automobile	50544061
16	Technofab Engineering Ltd.	Faridabad·68 IMT	P-38	11400	Not mentioned	30685038
17	Associated Lighting Company	Faridabad·68 IMT	P-59	11400	Due to cancellaayion of expenion planq	11070703
18	M.M. Exports (India)	Faridabad·68 IMT	P·97	11400	Change of business trend and high the minimun wages in haryana	20797067
19	Skl Industries Pvt.Ltd.	Faridabad-68 IMT	P·101	9000	due to some unforeseen circumstances	2099565
20	Star manufacturing GA Impex pvt.	Faridabad·68 IMT	P·108	11600	Due to Personal problem	3166933
21	Pee Cee Casting Pvt.Ltd.	Faridabad·68 IMT	P·156	11400	Due to un avoidable circumstances	5125719
22	DS Auto	Faridabad·68 IMT	P·157	11400	financeial crises due to slowdown in automobile	2908828
23	Suresh Kumar Singla	Faridabad·68 IMT	P·158	11400	due to financial problem	3133659
24	K.P. Tools Pvt.Ltd.	Faridabad·68 IMT	P·159	11400	Due to financial constraints	3724272
25	Mahender Kumar	Faridabad·68 IMT	P·168	11400	due to non arragement of payments for remaining Instalments	5050217
26	Anil Mahajan	Faridabad·68 IMT	P·174	11400	allottee suffering from cancer	5892735
27	Deepak Enterprises	Faridabad·68 IMT	P·177	11400	Partners of firm not Interested to continue	3833317
28	Hi-Tech Disposable Syringes	Faridabad·68 IMT	P·180	11400	major recession In the market	7050114
29	Ajay Engineering Works	Faridabad·68 IMT	P·182	11400	Due to unavoidable circumstances	2912418

30	Sai Extrumech Pvt.Ltd.	Faridabad·68imt	P·18184	11600	Not able to continue due to some problem	2936250
31	Precision Automotive Industries	Faridabad-68 IMT	P·188	11400	Due to recession In industries	5044500
32	V.M. Auto Products	Faridabad-68 IMT	P-201	11400	Due to some cirses in business	497250
33	Rachna Jindal	Faridabad·68 IMT	P·207	11400	Due to Personal problem	5110476
34	Shree Ganpati Boxmaker Pvt.Ltd	Faridabad·68 IMT	P·213	11400	There is continous fall in the market and business of company is going down	2885625
35	Dioptres Unlimited	Faridabad-68IMT	P-219	11400	factors impacting In the business senerlos	2885625
36	Rbm Industries	Faridabad·68 IMT	P·224	11400	Not mentioned	7359052
37	Techno Engineering	Faridabad·68 IMT	P·263	11400	Due to deterolted health	4762394
38	Sahil Overseas	Faridabad-68 IMT	P-285	11400	Not mentioned	2883993
39	Kiran Dhingra	Faridabad·68 IMT	P·290	11400	Due to financial problem	3970073
40	Mannu Khanna	Faridabad-68 IMT	P·292	11400	Due to unavoidable circumstances	3900859
41	Asv Engineers (P) Ltd.	Faridabad-68 IMT	P-299	11400	Due to recession in Industries	5585915
42	J.D. Industries	Faridabad-68 IMT	P·302	11400	due to lack of sufficient business /order	5723273
43	Vikas Metalloys And Steels L.L.P	Faridabad-68 IMT	P·619	9000	Due to recession in market	81426835
44	Deepak Kansal	Faridabad-68 IMT	P·716	11400	difficult to run the IT project at given location	4914529
45	Newsun Plastic Industries	Faridabad-68 IMT	P-864	11400	Could not continue the project due to other projects	514169
46	Pooja Metal Processors (P) Ltd.	Faridabad-68 IMT	P-762A	11400	due to financial problem	68065
47	Ishwar C. Saini	Faridabad-68 IMT	P·128	11400	Due to non-adequate basic infrastructure	3406347
48	Rajesh Jhamb	Faridabad-69 IMT	P· 242	11400	Due to recession In market	4527741
49	R.V. Wire Technologies Technologies	Faridabad-69 IMT	P· 624	11400	Due to flnancail problem	2885625
50	Sanjay Wadhawan	Faridabad-69 IMT	P-631	11400	Not mentioned	4298914
51	Sgs Engineering Work	Faridabad-69 IMT	P·632	11400	Not mentioned	96 47378

52	Kamla Devi Mangla	Faridabad-69 IMT	P-676	11400	the allottee is suffering from cancer	5032340
53	Ultimate Fashion Maker Ltd.	Faridabad·69 IMT	P· 684	11400	Present Market Position Is not good for export business	2882361
54	SOI Engineering Corporation	Faridabad-69 IMT	P· 685	10400	Due to some unavoidable circumstances	2715418
55	Nidhi Metal Auto Components Pv	Faridabad-69 IMT	P-692	11400	Due to financial Problem	7359052
56	Gurpreet Bindra	Faridabad-69 IMT	P-705	11400	Due to perpetual recession In Automobile industries	4500000
57	Light Lift India Pvt. Ltd	Faridabad-69 IMT	P· 729	11400	Due to unavoidable circumstances	5036802
58	Promptech Industrial Products	Faridabad-69 IMT	P-732	11400	Due to unavctdabte circumstances	7631576
59	Rajender Kumar Chawla	Faridabad-69 IMT	P-748	11400	Due to unavoidable circumstances	7057036
60	Micro Machines	Faridabad-69 IMT	P-750	11400	Due to non-adequate basic Infrastructure	2963541
61	Novapax Venus Polymers Pvt.Lt	Faridabad-69 IMT	P-799	11400	Due to unavoidable circumstances	6769941
62	Super Seals India Ltd.	Faridabad-69 IMT	P-826	11400	Due to financial Problem	2660727

63	Medelac Systems Pvt.Ltd.	Faridabad-69 IMT	P·829	11600	Adverse economic conditions	7228395
64	Pawan Engineering Works	Faridabad-69 IMT	P·862	11400	Due to Personal problem	2718628
65	Natraj Industries	Faridabad-69 IMT	P-863	11400	Not mentioned	3967734
66	Presto Stantest Pvt.Ltd.	Faridabad-69 IMT	P-870	11400	Not mentioned	7352978
67	Shri B.R. Castings (P) Ltd.	Faridabad-69 IMT	P-871	11400	due to slowdown in automobile sector	2910799
68	Metafab Engineers India Pvt.Lto	Faridabad-69 IMT	P-878	11400	Due to some personal reason	3830356
69	Emdet Jamshedpur Pvt.Ltd.	Faridabad-69 IMT	P-880	11400	Due to economic slow- down	17436023
70	Neumann Engineering Works	Faridabad-69 IMT	P-908	11400	due to financial problem	6117952
71	Tcv Enterprises	Faridabad-69 IMT	P-739	11400	Slow down In business.	6601117
72	Orchid It Solutions (P) Ltd.	IMT-6/1 Manesar	P-1B	9000	Market scenario, tight liquidity position.	24736443
73	Indian Express News Papers (M) Ltd.	IMT-8/IV Manesar	P-446 G 8	5500& 9000	Market conditions In general & specifically in the Print Media Industry.	123353506
74	Ritu Goel	Kundli/IV	P-76-A·	6500	Another lesser size plot allotted in Kundli	2339694
75	Gts Exports (P) Ltd.	Kundli-53/V	P·116	5500	Infrastructure Incomplete	15834063
76	T.C. Industries	Manakpur	P·229	5000	Another plot allotted In Faridabad IMT	5384482
77	Sahil Aggarwal (Death Case)	Manakpur	P·319	5000	Death of allotted	2250200
78	Love Goyal A Kush Goyal	Manakpur-II	P·26	5000	Financial problem	1732928
79	Jiya Lal	Narwana/IE	40	3500	Financial problems	1218164
80	Sanjay Kumar	Narwana/IE	50	3500	Financial problems	896913
81	Balwaan Singh	Narwana/IE	45	3500	Due to financial problems	1218349
82	Manoj Kumar	Panipat/IE	171	6500	Non-developed area	292500
83	Gurdyal Singh	Panipat/IE	177	6500	Due to family problem	731250
84	Garima Taneja	Panipat/IE	169	6500	Recession in market	731250
85	Shivaji Sindhu	Panipat/IE	260	6000	Personal reason	1293876
86	Monika	Panipat/IE	144	6000	Recession in the market	3189374
87	Hindustan Products	Panipat/IE	193	6500	Unavoidable circumstances	1008989
88	Sudhir Gujela	Panipat/IE	227	6000	Personal reason	1299375
89	Sandeep Godara	Panipat/IE	77	6500	Recession In the market	2262305

90	Kanchan Sagar Bhatia	Panipat/IE	218	6000	Unavoidable circumstances	1270556
91	Tilak Raj	Panipat/IE	267	6000	Due to financial problems	1913175
92	Shashi Mittal	Panipat/IE	248	6000	Financial problems	750480
93	Paliwal Home Furniture	Panipat/IE	107	6000	Financial problems	2202192
94	Jasbir Singh	Panipat/IE	271	6000	Due to financial problems	1923750
95	Hari ram	Panipat/IE	145	6000	Not mentioned	2327283
96	Seema Rani	Panipat/IE	184	6500	Financial problems	731250
97	Kiran Mohan Verma	Panipat/IE	236	6000	Due to financial problems	2146780
98	Vijay Kumar	Panipat/IE	334	6000	Unstable and inflation in the market	7145000
99	Unique Auto Rubber Udyog Pvt. Ltd.	Panipat/IE	150	6000	Due to financial problems	4830600
100	Pushpinder Kumar Gupta	Panipat/IE	284	6000	Financial problems	2126546
101	Monika Nada	PanIpat/IE	116	6000	Due to unfavorable market scenario and addditonal enhancement cost	5510483
102	Karan Jindal	Panipat/IE	220	6000	Financial problems	2425562
103	Parmod Khanna	Panipat/IE	86	6000	Financial Problems	6542088

104	Ankita	Panipat/IE	111	6000	Unavoidable circusmstances	5461389
105	Himanshu Kubba	Panipat/IE	192	6500	Plan to set up another Industrial unit in Panipat	2094453
106	Rashim Bhardwaj	Panipat/IE	75	6500	due to recession In the market	3126500
107	Nisha	Panipat/IE	166	6500	Due to recession In the market	1946778
108	Prabha Aggarwal	Panipat/IE	173	6500	Due to non-developed area and location of plot	1310713
109	Vikram Mittal	Panipat/IE	224	6000	Recession In the market	2438800
110	Amar Ujala Publications Limited	Panipat/IE	303	6500	Due to change of business policy	10255345
111	Anil Sharma	Panipat/IE	231	6000	Due to High cost of land	2425062
112	Ess Emm Komposit Works Pvt. Ltd. ,	Panipat/IE	103	6000	Not mentioneded	2220568
113	Parmod Bansal	Panlpat/IE	266	6000	Personal reason	2438085
114	Rohit Kumar Goel	Panipat/IE	222	6000	Recession In the market	2575589
115	Roshni Devi	Rai Food Park	2240-A	9000	Unavoidable circumstances.	1012500
116	Oevi Singh	Rai Food Park	2236	9000	Not mentloneded	607500
117	Rita Singhal	Rai Food Park	2241-B	9000	Family circumstances	1012500
118	Satwinder Pal Singh	Rai/IE	2122	9000	Due to infrastructure problems/ Not Interested In changed plot	1112311
119	Rockman Industries Ltd.	Rohtak-30 B IMT	P·3	4000	Unable to Implement.	130653602

120	Gaurav Verma	Rohtak-31B IMT	P·22	5000	unavoioabte circumstances	20008957
121	Moonshine Enterprises Pvt.Ltd.	Rohtak-31B IMT	P·32	5000	Unable to tie-up with the companies to hom the Product was to be supplied	5069212
122	Ankit Industries	Rohtak-31B IMT	P·24	5000	unable to tie-up with the ompanies to whom the product was to be supplied	5069212
123	Deepak Mehal, Rohit Mehal &	Saha	P·42	4000	Unavoidable circumstances	2102188
124	Bharat Rattan,	Saha-I	P·97	4000	Another unit Implemented at Barwala	4170662
125	Dhiraj Gupta	Saha-1/1	P·350B	4000	Unavoidable circumstances	2192708
126	Aryan Enterprises*	Saha-1/1	P·117	4000	Unavoidable circumstances	270000
127	Sushil Indora	Sirsa IIDC	72-E	5100	Uneven shape	6433803
128	Gaurav Garg	Tohana/IE	66	3000	Due to non-devetoped'area	450000
129	Rosy Pandey	Tohana/IE	10	3000	Due to financial problems	359100

*Refund under process

विधान कार्य

(i) दि हरियाणा बैकवर्ड क्लासिज (रिजर्वेशन-इन सर्विसेज एंड एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीच्यूशंज) बिल, 2016

11.00 बजे **श्री अध्यक्ष** : अब मुख्यमंत्री हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) विधेयक, 2016 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस पर तुरन्त विचार किया जाए।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) विधेयक, 2016 प्रस्तुत करता हूँ। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ -

> कि हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

> कि हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अभय सिंह चौटाला (ऐलनाबाद) : अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है इसके पैरा नं0 13 में लिखा हुआ है कि "सरकार इस अधिनियम के लागू होने से दस वर्ष की समाप्ति पर तथा तत्पश्चात् दस वर्ष की प्रत्येक उत्तरवर्ती अवधि पर अनुसूची का पुनरीक्षण करेगी।" इसमें पुनरीक्षण करने के लिए सरकार का नाम लिखा गया है। इस बारे में मेरा कहना है कि इसमें जो सरकार शब्द लिखा हुआ है इसकी जगह पर विधान सभा लिखा जाना चाहिए। केन्द्र में भी लोकसभा में जो भी विधेयक ला कर आरक्षण दिया गया है उसमें पुनरीक्षण के लिए लोकसभा को अथॉराइज किया गया है तथा लोकसभा ही उस पर पुनर्विचार कर सकती है। वहाँ पर सरकार उस पर पुनर्विचार नहीं कर सकती। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सदन के नेता को यह सुझाव है कि इस पर सरकार की बजाय विधान सभा को पुनर्विचार का अधिकार दिया जाये। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस पर अवश्य ध्यान देगी।

श्री रवीन्द्र कुमार (समालखा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार ने जो हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) विधेयक, 2016 पेश करके ऐतिहासिक फैसला किया है मैं उसका समर्थन करता हूँ और इसके लिए सरकार का धन्यवाद करता हूँ। 31 मार्च, 2016 तक आरक्षण देने का सरकार ने जो वायदा किया था उसको पूरा करते हुये इसी सत्र में विधेयक ला कर जाट तथा अन्य 5 जातियों को आरक्षण का लाभ देने का वायदा पूरा किया है उसके लिए मैं बार-बार आभार व्यक्त करता हूँ। आपने यह आरक्षण विधेयक ला कर सभी जातियों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, उसमें चाहे बी.सी.-ए हो, चाहे बी.सी.-बी. हो या बी.सी.-सी हो या सामान्य कैटेगरी हो सबको आरक्षण का लाभ दिया गया है। अब यह कानूनी तौर पर भी पक्का काम हो गया है इसके लिए मैं फिर से सरकार और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, पिछले काफी समय से मीडिया में और जनमानस में एक विषय बार-बार आ रहा था कि आरक्षण दिया जाये। खास तौर से जाटों को और उसके साथ-साथ 5 अन्य जातियों के लिए आरक्षण की मांग उठती रही है। इसके लिए पिछले दिनों एक आंदोलन भी चला था और हमने उस समय भी काफी बातचीत भी की थी और उसी दौरान मैंने आश्वस्त भी किया था कि हम आने वाले सत्र में यह विधेयक अवश्य लायेंगे और इस एक्ट को बनाने के बारे में जो भी बादल छाए हुये थे, उन सबको दूर करके इसको हम पारित करवायेंगे। उस वायदे को पूरा करने के लिए आज हम यह विधेयक लेकर आये हैं। अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में पहले से जो प्रावधान थे उनमें केवल बैकवर्ड क्लास के जो BC-A और BC-B के प्रावधान थे न केवल उनको बनाए रखा बल्कि उसमें कुछ न कुछ सुविधाएं और भी दी हैं विशेष तौर पर BC-A और BC-B क्लास-I और क्लास-II उसमें जहां 10 प्रतिशत और 5 प्रतिशत का प्रावधान था उसको हमने एक-एक प्रतिशत बढ़ा दिया है। अब हमने उसको 11 प्रतिशत और 6 प्रतिशत किया है। इसके साथ ही पिछली सरकार ने जो 6 जातियों का आरक्षण स्पेशल बैकवर्ड क्लास के नाम से किया हुआ था और उसमें 10 प्रतिशत और 5 प्रतिशत का प्रावधान था यानि क्लास-I और क्लास-II का 5 प्रतिशत किया हुआ था उसको भी बढ़ाकर हमने 6 प्रतिशत कर दिया है जिसमें एक प्रतिशत और बढ़ाकर दिया है। ऐसे ही इकॉनोमिक बैकवर्ड का प्रश्न है उस नाते से जो पहले का आरक्षण है वह क्लास-III और IV में 10 प्रतिशत है और क्लास-I और क्लास-II में 5 प्रतिशत है उस 5 प्रतिशत को भी हमने 7 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है जिसको सरकारी अधिसूचना के अन्दर जारी किया जाएगा। इसी प्रकार नौकरियों के साथ-साथ दाखिलों में भी जिस प्रकार का पहले आरक्षण दिया हुआ था उसी प्रकार से उस आरक्षण को बरकरार रखा है। अब जो हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में से सुप्रीम कोर्ट तो केन्द्र के नाते से था और हाई कोर्ट में जो 6 जातियों के स्पेशल आरक्षण पर एक प्रकार से जो रोक लगी थी, जो स्टे हुआ था वह भी अपने आप खत्म हो जाएगा क्योंकि अब उस नोटिफिकेशन का तो कोई अर्थ रहेगा ही नहीं, वह स्टे भी अपने आप खत्म हो जाएगा और जैसे ही राज्यपाल महोदय इस बिल पर हस्ताक्षर कर देंगे तब से ही यह लागू हो जाएगा। इस आरक्षण के अन्दर जो क्रीमीलेयर पहले से चली आ रही है जो एक विधान बना हुआ है उसको भी नोटिफिकेशन के द्वारा तय करेंगे जिसमें सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि हर तीन वर्ष के बाद इस क्रीमीलेयर का पुनर्सर्वे करके दोबारा से इसका निर्धारण किया जाएगा कि उसमें क्रीमीलेयर की रेखा क्या रखी जाए। जहां तक 10 साल के बाद सर्वे करने का सवाल है उसका अधिकार पहले भी सरकार के पास ही था कि कौन सी जातियां किस श्रेणी में रखी जाएंगी और अभी भी हम इस बिल के पारित होने के बाद एक नया बिल लाने वाले है जिसमें बैकवर्ड क्लास कमीशन का गठन किया जाएगा और बैकवर्ड क्लास कमीशन के सर्वे के बाद उसकी रिकमैंडेशन के बाद ही उसमें कोई निर्णय हो सकेगा। बिना बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिकमैंडेशन के सरकार कोई निर्णय नहीं कर पाएगी। इस प्रकार का प्रावधान इसमें किया गया है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष महोदय अब मैं आपसे निवेदन करता हूं और प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

क्लॉजिज- 2 से 15

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि क्लॉजिज- 2 से 15 बिल का पार्ट हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

शिड्यूल-1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि शिड्यूल-1 बिल का पार्ट हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

शिड्यूल-2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि शिड्यूल-2 बिल का पार्ट हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

शिड्यूल-3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि शिड्यूल-3 बिल का पार्ट हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज-1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि क्लॉज-1 बिल का पार्ट हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि इनैक्टिंग फार्मूला बिल का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव पेश करेंगे कि बिल पास किया जाए।

श्री मनोहर लाल : मैं प्रस्ताव करता हूं-

कि यह बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्वसम्मति से पास हुआ

(ii) दि हरियाणा बैकवर्ड क्लासिज कमीशन बिल, 2016

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2016 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस पर तुरन्त विचार किया जाए।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2016 प्रस्तुत करता हूँ तथा यह भी प्रस्ताव करता हूँ-

कि हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव पारित हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लॉज-बाई-क्लॉज विचार करेगा।

क्लॉजिज 2 से 17

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि क्लॉज 2 से 17 बिल का पार्ट हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि क्लॉज 1 बिल का पार्ट हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

इनैक्टिंग फॉर्मूला

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि इनेक्टिंग फॉर्मूला बिल का इनेक्टिंग फॉर्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

टाईटल

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्ष: अब माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव पेश करेंगे कि बिल पास किया जाये।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ -

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ -

कि बिल पास किया जाए

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि बिल पास किया जाए

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पास हुआ।

वर्ष 2016-17 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भ

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2016-2017 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भ होगा।

श्री टेक चन्द शर्मा (पृथला) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में दो बिल पास हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं इसके लिए पूरे सदन को मुबारकबाद देता हूँ और इसके साथ-साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह भी निवेदन करता हूँ कि इकोनोमिक वीकर सैक्शन से संबंधित जो विधेयक है उसको भी वर्तमान सत्र में लाकर पास करना चाहिए ताकि इकोनोमिक वीकर सैक्शन को भी संतुष्ट किया जा सके।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, टेकचन्द जी ने जो अभी इकोनोमिक वीकर सैक्शन से संबंधित विधेयक के बारे में बात की है तो मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इसके लिए नए सिरे से नोटिफिकेशन की जा रही है और इस सत्र के दौरान इस बिल को कभी भी सत्र में लाकर पास कर दिया जायेगा। हमें इस संबंध में कोई कठिनाई नहीं है।

श्री अभय सिंह चौटाला (ऐलनाबाद) : अध्यक्ष महोदय, सरकार इस बजट सत्र पर कितनी सीरियस है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कल जब आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया था तो उस वक्त माननीय वित्त मंत्री जी सदन में मौजूद नहीं थे। (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में उपस्थित था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं कल की बात कर रहा हूँ। (शोर एवं व्यवधान) कल जब मुझे बजट पर चर्चा के लिए समय दिया गया था तब मंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं थे। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु: अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में ही उपस्थित था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी हाउस में थे लेकिन अभय जी कल आप बजट पर बोलना नहीं चाहते थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: मेरी बातों का जवाब सदन के नेता देंगे या वित्त मंत्री जी जवाब देंगे या संसदीय कार्य मंत्री जी जवाब देंगे या किसी मंत्री के विभाग से जुड़ी हुई बातें होंगी तो वो इसका जवाब दे सकते हैं। प्रतिपक्ष के नेता के प्रश्नों के उत्तर तो केवल वित्त मंत्री जी ही देंगे। यह बात इतनी गंभीर थी कि तीनों मंत्रियों में से कोई भी सदन में उपस्थित नहीं था। अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बात का जिक्र आपसे भी किया था। सदन के अंदर जब बजट पर चर्चा हो रही हो तो माननीय वित्त मंत्री जी किसी की जिम्मेवारी ना लगाकर जाये तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे फिर से बजट पर चर्चा करने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष नेता ने कहा है कि वित्त मंत्री हाउस में ना हो और किसी की भी जिम्मेवारी ना लगाकर जाये यह दुर्भाग्यपूर्ण है, इस शब्द को वापस लिया जाये तो अच्छा रहेगा। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेवारी लगा रखी थी, लेकिन माननीय प्रतिपक्ष की तसल्ली नहीं हुई, वह अलग विषय है। मैं उसको दुर्भाग्यपूर्ण भी नहीं कह रहा हूँ। हमारे सभी मंत्री बड़ी जिम्मेवारी से आपकी बातों को नोट कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हों और हम हाउस में उपस्थित होते तो यह बहुत ही अच्छी बात होती। अभय जी, आपने हमारी अनुपस्थिति में बोलने के लिए समय निर्धारित किया इसके लिए भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन किसी की भी जिम्मेवारी नहीं लगाई ऐसी बात नहीं है। अभय जी, यदि आप वो शब्द वापस ले लेंगे तो हमारा मान सम्मान बढ़ा रहेगा।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी हाउस में उपस्थित नहीं थे, तो मैं अपनी बात किसके सामने रखूं।

कैप्टन अभिमन्यु: अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता की बात बिल्कुल सही है कि हम सदन में उपस्थित नहीं थे। लेकिन माननीय प्रतिपक्ष बहुत पुराने नेता हैं वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर वित्त मंत्री हाउस में उपस्थित नहीं है तो किसी ना किसी मंत्री की जिम्मेवारी स्वाभाविक तौर पर जरूर लगाकर गये होंगे। यह कोई दुर्भाग्य से नहीं बल्कि संयोग से हुआ है।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, किसी भी मंत्री ने यह आश्वासन नहीं दिया कि आप बजट पर चर्चा करें, हम सब बातों को नोट कर रहे हैं। इसलिए यह बात दुर्भाग्यपूर्ण है।

कैप्टन अभिमन्यु: अभय जी, आप बजट पर चर्चा कल करेंगे, इस बात को हमने सर्व सम्मान से स्वीकार कर लिया था। प्रतिपक्ष के नेता का बजट पर टिप्पणी करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके अनुभव और हरियाणा प्रदेश के प्रति जो समझ है उसका लाभ हमको बजट के चर्चा के दौरान मिले, इसके लिए हम तैयार हैं। इसका हम स्वागत करते हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला: अभिमन्यु जी, कल जो आपसे गलती हुई है उसे आपको स्वीकार करनी चाहिए कि हमसे कहीं ना कहीं गलती हुई है।

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, सच्ची बात तो यह है कि कल अभय जी की तैयारी कम थी और आज पूरा तैयार हो कर सदन में आए हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, कल भी मेरी तैयारी पूरी थी।

श्री अध्यक्ष: अभय जी, कल माननीय सदस्यों की संख्या भी कम थी।

कैप्टन अभिमन्यु: अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी की बात मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन जो बात माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कही है वही सच है।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी के बजट पेश करने के बाद विपक्ष के नेता को चर्चा के लिए बुलाया जाता है। माननीय वित्त मंत्री जी के बाद 2 या 3 माननीय सदस्यों को बजट पर बुलाया, तो भी मैंने उस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई। लेकिन तैयारी वाली बात तो कभी भी नहीं हो सकती है। यदि मेरी बजट पर बोलने के लिए तैयारी नहीं होती तो मैं किसी और माननीय सदस्य का नाम ले लेता।

कैप्टन अभिमन्यु: अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता को बजट पर चर्चा करने का पूरा अधिकार है। अभय जी, आपको ध्यान होगा कि आपने बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में भी कहा था कि बजट इस तरह से पेश किया जाये जिससे हमें उसे पढ़ने और उसकी तैयारी करने का समय मिले। बजट पेश होने के अगले दिन चर्चा चलती रही, बाद में समय थोड़ा सा बचा था जो आपके हिसाब से पर्याप्त नहीं था। इसलिए आपका और सदन का पूरा ध्यान रखते हुए ताकि चर्चा आरम्भ हो जाए इसलिए... (विघ्न) आपके सम्मान में और सदन की मर्यादा में हमने अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं रखी है। (विघ्न) माननीय अध्यक्ष ने भी आपके सम्मान की और सदन की मर्यादा की पूरी चिंता की है। हम आपका तहेदिल से सम्मान करते हैं। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये इस बहस को आगे न बढ़ाएं। मैंने इनसे कहा था कि आपको भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बराला साहब से पहले मुझे पहले बोलने का मौका देना चाहिए। मैंने कल भी इनसे यही कहा था। अब इस बहस को ख्वामखाह मत बढ़ाइये। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब आप इस बहस को आगे न बढ़ाकर सदन की कार्यवाही शुरू करो।

हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री डॉ० महासिंह का अभिनन्दन

श्री रामबिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस समय सदन में चौधरी महासिंह जी सदन की कार्यवाही देख रहे हैं जोकि पूर्व अध्यक्ष एवं मंत्री भी रह चुके हैं। मैं इनका सदन में उपस्थित होने पर स्वागत करता हूं।

वर्ष 2016-17 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अभय सिंह चौटाला (ऐलनाबाद) : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2016 का जो बजट पेश किया गया है यह केवल आंकड़ों पर आधारित है। इसमें आंकड़े भी इस तरह से दर्शाये गए हैं कि लोग इससे भ्रमित हो रहे हैं। सरकार ने दो नारे दिए हैं- "सबका साथ-सबका विकास" और "मिनिमम गवर्न्मैंट मैक्सिमम गवर्नैंस।" जहां तक दूसरे नारे का सवाल है इस बजट से लगता है कि यह मैक्सिमम गवर्नमैंट है और मिनिमम गवर्नैंस है। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन मैं भाजपा के माननीय साथियों से उम्मीद करूंगा कि जब मैं अपनी बात कहूं तो उस वक्त बीच में ये सदस्य टोका-टिप्पणी न करें। अगर माननीय सदस्य टोका-टिप्पणी नहीं करेंगे तो इससे हाउस का समय बचेगा। मेरी बात का जब आप जवाब दें तो उस वक्त अपनी तरफ से सारी बातें कह लें। मैं माननीय मंत्री जी से उम्मीद करूंगा कि ये प्वायंट्स को नोट भी कर लें। जहां तक सरकार द्वारा टैक्स फ्री बजट लाने की बात कही गयी थी कि हम टैक्स फ्री बजट लेकर आएंगे और उसको लेकर मेजें भी थपथपाई गई थी कि हरियाणा में भाजपा की सरकार टैक्स फ्री बजट लेकर आई है। मेरे अनुभव के अनुसार हर सरकार टैक्स फ्री बजट लेकर आती है। पहले की सरकारें भी टैक्स फ्री बजट लेकर आती रही हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2015 और वर्ष 2016 में बजट पेश किया है लेकिन इन्होंने वर्ष 2015 के बजट की अपेक्षा इस वर्ष के बजट में जनता पर टैक्स ज्यादा लगाए हैं, वैट में वृद्धि की है और बिजली दरों में कई बार वृद्धि भी की है। इस बजट से एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि सरकार ने बजट को टैक्स फ्री का नाम देकर अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश की है। माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में पैट्रोल और डीजल की वैट दर में लगभग सौ प्रतिशत की वृद्धि की है। इसी प्रकार भट्ठे और प्लाईवुड की फैक्ट्रियों में भी फ्यूल चार्जिज के नाम पर बिजली दरें बढ़ाई हैं लेकिन मैं इस विषय पर बाद में चर्चा करूंगा। हमारी पार्टी का शासनकाल 2000-2005 तक था जिसमें आपकी पार्टी भी सहयोगी रही थी। यह रिकार्ड की बात है कि हमारे शासनकाल के दौरान कभी राजस्व घाटा नहीं हुआ था। वर्ष 2014-15 में राजस्व घाटा 8300 करोड़ रुपये था जो पिछले वर्ष बढ़कर 10700 करोड़ रुपये हो गया था। इस वर्ष बजट में राजस्व घाटा लगभग 1230 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। राजस्व घाटा कम होने का मतलब केवल एक होता है कि प्रशासनिक अधिकारी कहीं न कहीं इन सब चीजों की अनदेखी कर रहे हैं। अगर राजस्व घाटा न हो तो मानकर चलो कि फिर विकास में वृद्धि होना निश्चित है। राजस्व घाटा ही नहीं बल्कि राजकोषीय घाटा भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2014 में यह घाटा 12600 करोड़ रुपये था जो वर्ष 2016-17 में 25000 करोड़ को पार कर जाएगा। अध्यक्ष महोदय, यह सब सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन का ही परिणाम है। अगर वित्तीय प्रबंधन ठीक हो तो मानकर चलो की घाटा नहीं आएगा। अध्यक्ष महोदय, जहां तक कर्जे की बात है। तो इस बारे में कई साथियों ने चर्चा की है कि जो वित्त मंत्री जी को लिखकर दे दिया गया है वह उन्होंने पढ़कर बताया है और उनके द्वारा कहा गया है कि हरियाणा में मनोहर लाल जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद किस तरह से हर ओर खुशहाली आई है। यहां इस बात की चर्चा हुई थी कि प्रति व्यक्ति आय में आज हरियाणा अग्रणीय है। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पहले सैशन में आपकी पार्टी की तरफ से एक श्वेत पत्र लाया गया था। उस श्वेत पत्र में यह कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के दौरान लगातार 10 वर्षों तक जनता को केवल गुमराह करने के लिए फरीदाबाद और गुड़गांव के आंकड़े दिखाकर यह दर्शाया जाता था कि किस तरह से हरियाणा प्रदेश पूरे हिन्दुस्तान में प्रति व्यक्ति आय में सबसे अग्रणी है। आपने श्वेत पत्र जारी किया

[श्री अभय सिंह चौटाला]

था और आज भी जो आपकी तरफ से बजट में दिखाया गया है वह भी केवल फरीदाबाद व गुड़गांव का ही है और पूरे प्रदेश का नहीं हैं। पूरे प्रदेश के हिसाब से देखेंगे तो प्रति व्यक्ति आय हमारी मामूली रह जाएगी। यह कहीं नहीं बताया गया कि इस प्रदेश के अंदर जब बच्चा जन्म लेता है तो कितना कर्जा अपने साथ लेकर पैदा होता है। इस प्रदेश में जब बच्चा पैदा होता है तो 56 हजार रुपये के करीब कर्जा साथ लेकर पैदा होता है। वर्ष 2014-15 में राज्य के कर्जे की राशि 82.305 करोड़ रुपये थी जो 2016 में बढ़कर लगभग 141 करोड़ हो जाएगी। यह कर्जे की राशि पंजाब के कर्जे की राशि से भी अधिक है। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार का पहला और दूसरा सैशन था तो उनमें कहा गया था कि हम फिजूलखर्ची कम करेंगे। यह भी कहा गया था कि यह जो कर्जा लेने की प्रथा रही है इसमें हम कमी लाने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इस कर्जे को कम करने की बजाय बढ़ाने का काम किया गया है। इस सरकार के पहले साल 17 हजार करोड़ रुपये का कर्जा था और अगले साल यह बढ़कर 40 हजार करोड़ के पार चला जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हमारी प्रति व्यक्ति आय एक लाख 86 हजार रुपये दिखाई गई है लेकिन जो गांव में खेती करने वाले किसान हैं या कोई और काम करके अपना गुजारा कर रहे हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत कम हैं। लगभग 50 परसैंट परिवार ऐसे हैं जिनकी एक लाख से भी कम आय है। जहां इन्कम एक लाख से भी कम हो अगर वहां आंकड़ों में दिखाया जाए कि हमारी प्रति व्यक्ति आय इतनी ज्यादा है तो यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। इस तरह से बजट के आंकड़ों के साथ प्रदेश के लोगों को गुमराह करना नहीं चाहिए। बजट के आंकड़ों के अनुसार सरकार 2016-17 में जी.डी.पी. के अनुपात में मात्र 1.5 प्रतिशत पूंजीगत खर्च करने जा रही है और इससे जाहिर है कि सरकार की प्रदेश के विकास में कोई रूचि दिखाई नहीं देती। जनता को विकास के नाम पर भ्रमित किया जा रहा है जिसके कारण जनता प्रदेश में परेशान है। आप यह मानकर चलें जब आप जी.डी.पी. के अंदर 1.5 प्रतिशत राशि खर्च करोगे तो 100 प्रतिशत विकास की दर में कमी आ जायेगी। इसी तरह से कृषि क्षेत्र के लिए अनेक बातें कही गई हैं लेकिन हकीकत अलग है। कहा तो यहां तक गया है कि अगले 5-6 साल में किसान की फसल का रेट दोगुना कर दिया जायेगा। यह रेट दोगुना किस प्रकार से होगा इस बारे में बजट में एक शब्द भी नहीं लिखा गया है। अगर यह रेट दोगुना करने की बात है फिर तो सीधे-सीधे जो आपने अपने मैनीफैस्टो में वायदा किया था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की जायेगी उसको तुरंत लागू किया जाए। अगर इस रिपोर्ट को लागू किया जाता है तो हम कह सकते हैं कि किसान को कहीं न कहीं उसकी लागत मुल्य से दोगुना पैसा मिल जायेगा। उसके लागू होने से किसान की आय बढ़ सकती है। लेकिन केवल यह दिखाने और दर्शाने से कि किसान की आय अगले 5-6 साल में दोगुनी कर दी जायेगी इससे काम नहीं चलेगा और यह किस प्रकार से करेंगे इसका कहीं जिक्र नहीं है। आज तो किसान को उसका लागत मूल्य भी नहीं मिलता क्योंकि किसान को मिनिमम स्पोर्ट प्राईस भी नहीं मिल रहा है। अगर किसान को मिनिमम स्पोर्ट प्राईस भी नहीं मिलेगा तो उसकी आमदनी दोगुनी कहां से हो जायेगी। इसी तरह से प्राकृतिक आपदा पड़ने पर किसानों की सहायता के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनीफैस्टो में यह कहा था कि किसान राहत अथोरिटी बनायेंगे लेकिन किसान राहत अथॉरिटी बनाना तो दूर की बात है जो मुआवजे की राशि थी उस पर भी कैप चढ़ा दिया। ऐसा करने से आप यह मानकर चलो कि किसान का विश्वास सरकार पर से कहीं न कहीं जरूर उठेगा कि किस तरह से आपने उनको बरगला करके वोट लिया और अब आप इस पर कैप लगाने का काम कर रहे हैं। ग्वार और बाजरा गरीब आदमी बोता है जिसके पास ट्यूबवैल या नहरी पानी

सिंचाई के लिए नहीं होता। यानि जो साधनहीन है वह ग्वार और बाजरा किसी से साधन मांगकर बोता है। उन गरीब किसानों की फसल को तेले ने पिछले साल खत्म कर दिया था। उन किसानों को सरकार ने मुआवजे से वंचित कर दिया था। यदि गरीब किसान को मुआवजा नहीं मिलेगा तो सरकार यह मानकर चले कि वह अपनी जमीन बेचने पर मजबूर हो जायेगा। इसी तरीके से ग्रामीण विकास के बारे में भी बजट में जिक्र किया गया है और बहुत बड़ी-बड़ी बातें सदन में भी कही गई हैं। यहां तक कहा गया है कि बहुत पढ़ी लिखी पंचायते इस बार हरियाणा में बनी हैं। इस तरह की बात बारी-बारी से सदस्यों से कहलवाई गई और सरकार की पीठ थप-थपाई गई कि सरकार का यह निर्णय बहुत अच्छा था। जिसकी वजह से पढ़ी लिखी पंचायतें आई हैं। (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। मैं बजट अभिभाषण पर अभी कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। माननीय साथी ने यह बात कही है कि माननीय विधायकों से कहलवाया गया। यहां सभी माननीय विधायक अपने-अपने विवेक से, अपनी-अपनी बुद्धि से अपनी क्षमताओं के अनुरूप अपनी बात कहते हैं। यह अच्छा नहीं लगेगा कि हम विपक्ष के साथियों को कहें कि उन्होंने वही बातें कहीं हैं जो नेता प्रतिपक्ष ने चाहा है। मेरा निवेदन है कि सभी सम्मानित सदस्यों के प्रति हम सम्मान रखें क्योंकि उन्होंने अपने-अपने विवेक से अपनी बातें कहीं हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ठीक है, उन्होंने अपने विवेक से कहा होगा।

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों का अभिनन्दन

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज स्पीकर गैलरी में इस सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री मामू राम और श्री रमेश खटक जी सदन की कार्यवाही देखने के लिए बैठे हैं। मैं पूरे सदन की तरफ से उनका यहां पर आने के लिए अभिनंदन करता हूं और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं।

वर्ष 2016-17 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, जैसा कि कैप्टन साहब ने बताया मैं भी यह मान लेता हूं कि सभी विधायकों ने यहां पर सभी बातें अपने विवेक से कही होंगी। सरकार द्वारा बजट में ग्रामीण विकास के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण विकास के ऊपर भी सरकार द्वारा यह कहा गया है कि हमारे प्रदेश में सभी पंचायतें पढ़ी-लिखी बन गई और जिला परिषदों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों ने आस्था व्यक्त करके उनकी पार्टी के व्यक्तियों को चेयरमैन बना दिया। मैं उन सभी बातों का जिक्र न करके केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि सरकार द्वारा आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए ग्रामीण विकास हेतु केवल मात्र 23 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इस 23 करोड़ रुपये की राशि को अगर हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक गांव के हिस्से में बांटा जाये तो यह राशि मुश्किल से कुछ हज़ार में ही आयेगी। इसलिए अगर किसी गांव के विकास के लिए आप हज़ार रुपये राशि देंगे तो उससे उस गांव का कैसे विकास हो पायेगा और गांव कैसे आगे बढ़ पायेगा। यह अनुपात के हिसाब से 4 प्रतिशत से भी कम है। इतना ही नहीं अपितु 2015-16 के बजट से भी इस बार के बजट में 12 करोड़ रुपये की राशि कम रखी गई है। जो 23 करोड़ रुपये की राशि की बढ़ोतरी की गई है यह तो वार्षिक योजना में की गई है। पिछले बजट से इसमें 12 करोड़ रुपये की राशि कम है इसलिए मैं फिर से अपनी इस बात को दोहरा देना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थितियों में गांवों का विकास कैसे होगा ? जब विकास के लिए राशि कम रखी जायेगी

[श्री अभय सिंह चौटाला]

तो फिर विकास कहां से और कैसे होगा? माननीय वित्त मंत्री जी जब बजट पर अपना रिप्लाई दें तो इस बात को उस समय अवश्य स्पष्ट कर दें कि किस ढंग से आप ग्रामीण क्षेत्र का विकास करेंगे और उसके लिए कहां से पैसा आयेगा ताकि सदन में बैठे हुए माननीय सदस्यों और प्रदेश के लोगों को इसकी जानकारी उपलब्ध हो सके। सभी को यह पता चल सके कि किस प्रकार का बजट यहां पर प्रस्तुत किया गया है और किस प्रकार से बजट को आंकड़ों के माध्यम से दर्शाकर सभी को गुमराह करने का प्रयास किया गया है। इसी तरह से विकास कार्यों पर खर्च करने की बात कही गई है। जहां तक विकास कार्यों का सम्बन्ध है, विकास कार्यों का अंदाज़ा प्लॉन बजट से ही लगाया जा सकता है कि आपका प्लॉन बजट क्या है और प्लॉन बजट के अंदर आप कितना रूपया खर्च करने जा रहे हैं। यह विकास का पैरामीटर है और इससे पता चल सकता है कि प्रदेश में कितना विकास होगा। सरकार का जो पिछले वर्ष का प्लॉन बजट था वह लगभग 43 हज़ार करोड़ रुपये का था जहां इसको इस बार बढ़ाया जाना चाहिए था वहीं इसके विपरीत इसको कम करके 40 हज़ार करोड़ रुपये कर दिया गया है। अगर हमारा प्लॉन बजट बढ़ता है तो फिर हम मान सकते हैं कि हमारा विकास भी बढ़ेगा। अगर हमारा प्लॉन बजट घट जाता है तो फिर 100 फीसदी हमारी विकास दर भी कम ही होगी। इसके लिए जो बजट का पेज़ नम्बर 3 है उसको देख लेना उससे आपको ये सारी बातें स्पष्ट हो जायेंगी। अब मैं सरकार द्वारा इस वर्ष लिये जाने वाले कर्ज़ के बारे में बताना चाहूंगा। इससे पिछले वर्ष सरकार द्वारा 17 हज़ार करोड़ रुपये का कर्ज़ लिया गया था लेकिन इस बार सरकार 28 हज़ार करोड़ रुपये का कर्ज़ लेने जा रही है। इस 28 हज़ार करोड़ रुपये की राशि में से 20 हज़ार करोड़ रुपये की राशि केवल मात्र ब्याज की राशि वापिस करने में खर्च होगी। पिछले वर्ष 2015-16 में बिजली विभाग के संशोधित वार्षिक प्लॉन में बजट में लगभग 18 हज़ार 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। **(इस समय उपाध्यक्ष महोदया आसीन हुई)** सरकार कहती है कि हम पूरे हरियाणा प्रदेश को जगमग करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि हम प्रदेश के किसान को 24 घंटे बिजली देना चाहते हैं, डोमैस्टिक सैक्टर और इण्डस्ट्री को भी आप पूरी बिजली देना चाहते हैं। आप यह भी कहते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा बिजली पैदा होगी तो बाहर की दूसरी कम्पनियां भी हरियाणा में उद्योग स्थापित करने के लिए आकर्षित होंगी लेकिन इस सबके बावजूद भी हैरानी की बात यह है कि आपने इसके लिए वर्ष 2016-17 के लिए लगभग 10 हज़ार 19 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। पिछले बजट के मुकाबले लगभग 8 हजार करोड़ रूपया कम रखा गया है। जब 8 हजार करोड़ रुपये कम होगा तो आप यह मान कर चलिये कि बिजली में बढ़ोतरी कैसे होगी ? प्रदेश में बिजली के कारखाने बंद हो रहे हैं, आज आपकी बिजली उत्पादक यूनिट्स बंद हो रही हैं। आप कहते हैं कि हम नई इंडस्ट्रीज लेकर आयेंगे तथा उनको सस्ते रेट पर बिजली देंगे। इसी तरह से आपके कम्पनियों के साथ जो बिजली के परचेज एग्रीमैंट्स हैं वहाँ से आपको सस्ती बिजली मिलती है और आप उपभोक्ताओं को महंगी बिजली देते हैं। महंगी बिजली के साथ-साथ संडरी चार्जिज भी लगाये जाते हैं। मेरे खयाल से यहाँ पर जितने भी विधायक बैठे हैं उनमें से शायद किसी को पता नहीं होगा कि ये संडरी चार्जिज क्या होते हैं। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं और हमारे सभी विधायक तथा हमारी पार्टी के कुछ अन्य वरिष्ठ नेता इस मुद्दे पर जब मुख्यमंत्री जी से मिलने गये थे तो हमने मुख्यमंत्री जी से भी पूछ लिया कि ये संडरी चार्जिज क्या होते हैं इसका क्या मतलब है? उस समय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी इन चार्जिज के बारे में नहीं जानते थे और उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव (बिजली) श्री राजन गुप्ता जी से बुला कर पूछा था।

इस प्रकार के बहुत से लोग हैं जिनको इन सुंडरी चार्जिज का पता नहीं है। सण्डरी चार्जिज का मतलब केवल और केवल इतना है कि अगर किसी आदमी का बिजली का बिल गलत आ गया चाहे वह अधिक आ गया या कम आ गया और वह आदमी उसको ठीक करवाने के लिए जाता है तो उसको ठीक करने के लिए भी 2.67 रुपये चार्जिज लिए जाते हैं जबकि सही बिल मुहैया करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। यह बहुत हैरानी की बात है कि इस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के लोगों की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। उनके बिजली के बिल बढ़ा कर, फ्यूअल सरचार्ज बढ़ा कर, सरचार्ज बढ़ा कर उन लोगों की जेबें काटी जा रही हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार की 'उदय' स्कीम के तहत आपको केन्द्र की तरफ से 25 हजार करोड़ रुपये की राहत मिल रही है तो आपको तुरन्त प्रभाव से उपभोक्ताओं के बिजली के रेट कम कर देने चाहिएं। (विघ्न)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं इसमें थोड़ा सा संशोधन करना चाहता हूँ। 'उदय' स्कीम को कैबिनेट ने इसलिए मंजूरी दी है कि जो यूटीलीटीज का कर्जा था वह बढ़ता चला जा रहा था तथा उनको ब्याज ज्यादा देना पड़ रहा था इसलिए बिजली विभाग के घाटे बढ़ते चले जा रहे थे। इसलिए केन्द्र सरकार ने 'उदय' के तहत एक स्कीम दी है कि यदि हरियाणा सरकार बिजली वितरण कम्पनियों का संचित ऋण जो 34600 करोड़ रुपये है, का 75 प्रतिशत हिस्सा (50 प्रतिशत इस वर्ष तथा 25 प्रतिशत अगले वर्ष) अपने ऊपर ले ले और बाकी 25 प्रतिशत यूटीलीटीज के पास रहे तो उनको कुछ राहत मिल जायेगी। एक तो उनके ऊपर कर्ज का बर्डन खत्म हो जायेगा और उनके ऊपर ब्याज नहीं पड़ेगा और जो ब्याज लगेगा वह यदि सरकार भी कहीं से कर्ज लेगी या बॉण्ड खरीदेगी तो सरकार को वह साढ़े 8 प्रतिशत पर मिल जायेगा जबकि यूटीलिटीज पर साढ़े 12 प्रतिशत की दर से ब्याज लगता है। उसमें 4 प्रतिशत का सीधा फायदा है। इसमें इतना ही है कि वह पैसा जो आज तक यूटीलिटीज पर था उसमें अगर सरकार पर एक लाख करोड़ रुपये कर्ज था तो उसमें से 35 हजार करोड़ रूपया यूटीलिटीज का था। इस प्रकार से वह कुल मिला कर 1,35,000/- करोड़ रुपये हो ही जाता है। अब यदि उसमें से 25 हजार करोड़ इधर शिफ्ट हो जायेगा तो उधर से कर्ज कम हो जायेगा। उपाध्यक्ष महोदया, और जब कंपनियाँ राहत महसूस करेंगी तो उनके ऊपर ब्याज भी कम पड़ेगा। इसके लिए हमने यह आश्वासन दिया है कि आगे बिजली का कोई भी बिल बढ़ाया नहीं जाएगा। जहां तक बिल को कम करने की बात है तो जब घाटे कम होंगे, कुछ खर्चे कम होंगे तब यह बिल कम करने की बात आगे सोची जा सकती हैं लेकिन हम ये आश्वासन देते हैं कि अगले तीन सालों में बिजली का बिल बढ़ाया नहीं जाएगा।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, मुख्य मंत्री जी ने 'उदय' योजना की चर्चा की है जिसमें 'उदय' योजना के अन्तर्गत बिजली की वितरण कंपनियों का तीन चौथाई कर्जा राज्य सरकारों को ट्रांसफर किया जा रहा है जिससे बिजली कंपनियों पर मात्र एक चौथाई कर्जा रह जाएगा। जब बिल बढ़ाए जाते हैं तब यह नहीं कहा जाता कि यह निर्णय सरकार का है तब तो यह कहा जाता है कि यह कंपनियों का निर्णय है और यह रेट कंपनियां तय करती हैं क्योंकि कंपनियों पर लगातार कर्जा बढ़ता जा रहा है। जब कंपनियों का तीन चौथाई कर्जा राज्य सरकार के पास आ जाएगा तो फिर कंपनी का कर्जा तो कम हो गया है। जब कंपनियों का तीन चौथाई कर्जा राज्य सरकार के पास आ गया तो कंपनियों को 100 फिसदी बिजली के रेट कम करने चाहिए क्योंकि उनके सिर पर जो कर्ज था वह कम हो गया है। उपाध्यक्ष महोदया, यह केवल

[श्री अभय सिंह चौटाला]
बिजली के रेट बढ़ने की बात नहीं है, 'उदय' योजना की बात है। आज तो ऐसी हालत है कि अगर किसान ट्यूबवैल का कनैक्शन लेने के लिए जाता है तो उसको सरकार को तीन लाख रुपये के करीब पैसा देना पड़ता है। आज किसान की फसलें खराब हुई हैं चाहे वह कीड़े से हुई, चाहे वह बारिश से हुई, चाहे वह कोई और कारण से हुई हैं उनको कोई इन्सैंटिव देने की बजाए आज उनसे ट्यूबवैल कनैक्शन के नाम पर सरकार एक तरह की वसूली कर रही है तो इसको भी आपके द्वारा एक दम से कम करना चाहिए और ट्यूबवैल के कनैक्शन पर भी आपको कोई सब्सिडी देनी चाहिए। जो ये 'तत्काल' स्कीम है उससे भी आम आदमी प्रभावित होता है। इस 'तत्काल' स्कीम के तहत वह किसान तो बिजली का कनैक्शन ले लेता है जिसके पास जमीन ज्यादा है और जिसकी इन्कम ज्यादा है। जिसकी कोई इन्कम नहीं है और जमीन भी कम है तो वह फिर वहां जाकर लाईन में खड़ा हो जाता है और उसको बिजली का कनैक्शन नहीं मिलता। उस किसान को इस बात के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि चाहे वह छोटा जमींदार है चाहे वह बड़ा जमींदार है उसके लिए ऐसी स्कीमों की बजाए ज्यादा ट्यूबवैल के कनैक्शन दिये जाएं जिससे उसको लाभ मिल सके। इसके लिए आप अपने विभाग में कोई भी किसी भी तरह की स्कीम लागू करके इन्कम में बढ़ोतरी करें।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यू) :उपाध्यक्ष महोदया, क्योंकि 'उदय' का विषय था जिसका प्रस्ताव बजट में आया था। जिसका नेता प्रतिपक्ष ने भी व सदन के नेता ने भी जवाब दिया है। मैं इस संबंध में बताना चाहूंगा कि जो साढ़े पैंतीस हजार करोड़ रुपये का कर्जा बिजली कंपनियों पर पहले से है जिसमें भारत सरकार ने भी एक सुझाव दिया है और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि बिजली के खर्चे को कम किया जाए। इस संबंध में एक प्रस्ताव दिया है कि इस 'उदय' स्कीम में स्टेट की रिस्ट्रक्चिरंग कीजिए ताकि बिजली कंपनियों का घाटा कुछ कम किया जा सके और उन पर कर्जे का अतिरिक्त बोझ न पड़े लेकिन यह स्कीम ऐच्छिक थी कोई राज्य इसमें हिस्सेदारी करे या न करे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें एक महत्वपूर्ण और बड़ी बहादुरी वाला फैसला लिया है कि जो यह 35 हजार करोड़ रुपये का कर्जा है वह बिजली कंपनियों से लेकर सरकार अपने ऊपर ले रही है। यह बहुत बोल्ड फैसला है और भारत सरकार ने दो साल के लिए हमको तमाम जितनी मर्यादाएं हैं फाईनैंस कमीशन से रिलेटिड हैं व एफ.आर.बी.एम. से रिलेटिड उन सबसे मुक्त करते हुए कहा है कि आप यह अतिरिक्त कर्जा ले सकते हैं। आपने जो बात कही है वह बिल्कुल सही है कि बिजली कंपनियों पर ब्याज का जो बोझ है वह हजार करोड़ रुपये सालाना कम होता है तो उसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए और आपने ये भी कहा कि अंततोगत्वा जो बिल है उसकी दर तय करने का काम बिजली विभाग का है। आपने यह बिल्कुल ठीक कहा कि अंततोगत्वा जो बिजली बिल हैं उसकी दर तय करने का अधिकार बिजली कंपनियों और रेगुलेटरी कमीशन को है। जब ये मिल बैठती हैं तो बिजली कम्पनियों पर पड़ने वाले खर्चे व कर्जे के बोझ का संज्ञान लेकर बिजली के बिल की दरें तय करती हैं। स्वाभाविक है कि बिजली कम्पनियों पर पड़ने वाले कम बोझ का संज्ञान लेकर अंततोगत्वा जो परिणाम आयेगा उससे निश्चित रूप से बिजली की दरों पर असर जरूर पड़ेगा।

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदया, मैंने एक और बात माननीय वित्त मंत्री जी से कही थी। उन्होंने इसको शायद नोट किया या नहीं किया गया यह तो मुझे पता नहीं है। सण्डरी चार्जिज जो लगा रखे हैं आपको उसे विद्ड्रा करना चाहिए ताकि 2.67 रुपये का जो बर्डन लोगों के ऊपर जबरदस्ती थोपा गया है वह खत्म होना चाहिए। (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु: उपाध्यक्ष महोदया, जब अगली बार एच.ई.आर.सी. बिजली की दरें तय करें तो उस वक्त आप यह सुझाव दे सकते हैं। यदि आप वहां पर इस बारे रिप्रेजेंटेशन देंगे तो मैं समझता हूँ कि उन बातों पर रेगुलेट्री कमीशन निश्चित रूप से विचार करेगा। इस विषय पर बजट पर चर्चा के दौरान बात करना ठीक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदया, यह बजट पर चर्चा का ही विषय है।

कैप्टन अभिमन्यु: उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य की बात का जवाब तो जरूर दूंगा लेकिन बजट से अलग विषय पर अगर कोई चर्चा है तो उस पर इस समय बात करना ठीक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदया, चण्डीगढ़ प्रशासन की तरफ से पहले इस तरह के चार्जिज लगाये जाते थे। परन्तु कोर्ट की दखल की वजह से इनको खत्म कर दिया गया। जब चण्डीगढ़ में सण्डरी चार्जिज को खत्म कर दिया गया है तो फिर हरियाणा में भी इन चार्जिज को खत्म कर देना चाहिए। जो पैसा सण्डरी चार्जिज के लिए दिया जाता है उससे उपभोक्ता को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है और न ही उसके बदले उसको कोई बिजली मिलती है। मेरा मकसद केवल यही है कि बिल में से इस सण्डरी चार्जिज को निकाल दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार से अनुसूचित जातियों व पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए भी बजट में चर्चा की गई है। बड़े जोर-शोर से यह कहा गया कि आने वाले समय में अनुसूचित जातियों व पिछड़ी जातियों के लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाने का कार्य किया जायेगा। वार्षिक योजना 2016-2017 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों व पिछड़ी जातियों तथा कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए लगभग 515 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2015-2016 के बजट में इसी कार्य के लिए 507 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। यदि पिछले साल और इस साल का अंतर देखें तो केवल मात्र 8 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है। 8 करोड़ रुपये में गरीब आदमी की क्या मदद की जा सकती है। हरियाणा प्रदेश में आज भी 50 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो खाद्य सुरक्षा चक्र के नीचे आते हैं और 20 से 25 प्रतिशत लोग हरियाणा प्रदेश में ऐसे हैं जिनके पास बी.पी.एल. कार्ड हैं, अगर आप उनके उत्थान के लिए 8 करोड़ रुपये का प्रावधान अपने बजट में रखोगे तो मानकर चलो कि आप गरीब लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं बल्कि सरकार द्वारा केवल मात्र बजट में खाना-पूर्ति की जा रही है। 50 प्रतिशत वह लोग जो खाद्य सुरक्षा चक्र के अधीन आते हैं तथा 20 से 25 प्रतिशत वे लोग जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, इतने लोगों के लिए यदि 8 करोड़ रूपया ही बढ़ाया जायेगा तो सरकार फिर ऐसे लोगों के प्रति उदासीनता दिखाने का ही काम कर रही है न की उनकी मदद करने की बात कर रही है। स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी बड़ी-बड़ी बातें कही गई हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी अभी सदन में मौजूद नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि नये-नये इंस्टीट्यूट्स खोले जायेंगे तथा हरियाणा प्रदेश के हर जिले में एक-एक मैडीकल कॉलेज बनाने का काम किया जायेगा। बारी-बारी यह कहा गया कि स्वास्थ्य सेवाओं में हम बहुत कुछ सुधार करेंगे। जहां तक सुधार की बात है, स्वास्थ्य मंत्री जी अभी सदन में मौजूद नहीं है, यदि मौजूद होते तो मैं उनसे पूछता कि मेरी भाभी जी ने उनसे निवेदन किया था कि हमारे डबवाली के हॉस्पिटल की हालत बहुत खराब है उसको ठीक किया जाये तथा इसका विस्तार भी किया जाए। माननीय मंत्री जी ने एक मिनट में खड़े होकर कह दिया कि वहां पर 100 बैड का एक हॉस्पिटल बनाया जायेगा और उसमें हर तरह की सुविधायें प्रदान करवाई जायेंगी। सदन के कई अन्य सदस्यों ने भी हॉस्पिटल

[श्री अभय सिंह चौटाला]

के संबंध में चर्चा की थी और मंत्री जी ने खड़े होकर बड़े-बड़े दावे किए थे कि हम हॉस्पिटल्ज के लिए नई-नई मशीनरीज लेकर आयेंगे और बैड से लेकर बैड शीट्स तक हर चीज को बदलने का काम किया जायेगा। लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजट में केवल 13 करोड़ रुपये का प्रावधान है। अगर 13 करोड़ रुपये ही बढ़ाए हैं तो माननीय मंत्री जी द्वारा हाउस में किए गए वायदे कैसे पूरे होंगे? उपाध्यक्ष महोदया, मेडिकल कॉलेज के लिए बजट में 760 करोड़ रुपये रखे हैं।

कैप्टन अभिमन्यु: अभय जी, आप आंकड़ें कहां से लाए हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला: अभिमन्यु जी, एक स्वास्थ्य सेवा के बारे में है और एक मेडिकल कॉलेज के बारे में है। शायद आपने बजट को अच्छी तरह से नहीं बनाया है। मैं कभी भी आधारहीन बात नहीं कहता हूँ।

कैप्टन अभिमन्यु: उपाध्यक्ष महोदया, मैं बजट पर एक-एक बात पर जवाब देने के लिए वचनबद्ध हूँ और बीच में जवाब नहीं देने के लिए भी वचनबद्ध हूँ।

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदया, यह बहुत अच्छी बात है।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू: उपाध्यक्ष महोदया, यह बहुत अच्छी परम्परा है।

श्री अभय सिंह चौटाला: वर्ष 2015-16 के मुकाबले 760 करोड़ रुपये की राशि केवल मेडिकल कॉलेजों के लिए रखी है जबकि 5 नये मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कही गई है। उपाध्यक्ष महोदया, करनाल जिले के कुटेल गांव में स्वास्थ्य विश्वविद्यालय, पंचकुला, भिवानी और जींद में नये चिकित्सा महाविद्यालय और गांव मानेठी, जिला रेवाड़ी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्थापित करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में तीन मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त प्रस्तावित स्वास्थ्य विश्वविद्यालय तथा मेडिकल कॉलेज के लिए बजट का प्रावधान बहुत कम है। 760 करोड़ रुपये में ये पांचों चीजें नहीं बन सकती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आज कहीं पर एक सरकारी कमरा बनता है तो उसमें भी अढ़ाई से तीन लाख रुपये का खर्चा आता है। इस प्रकार से मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए 760 करोड़ रुपये में नहीं हो सकता है। आजकल तो कोई भी टैंडर होता है तो उसमें हमेशा इस बात पर जोर दिया जाता है कि वह काम समय पर हो। इसके लिए सौ फीसदी बनाने वाले ठेकेदार को इस बात के लिए बाध्य किया जाता है कि यदि आपने समय अवधि के दौरान कार्य पूरा नहीं किया तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। मेरे ख्याल से जब टैंडर हो जायेंगे तो ज्यादा से ज्यादा एक साल का समय निर्माण कार्य में लग जायेगा। इस प्रकार महँगाई और बढ़ने से 760 करोड़ रुपये में यह कार्य नहीं हो सकता, ठेकेदार अपनी जेब से कैसे पैसे लगा सकता है? उपाध्यक्ष महोदया, कांग्रेस के शासनकाल में नलहड़ में मेडिकल कॉलेज बना था। उस मेडिकल कॉलेज की खस्ता हालत आप फोटो देखकर ही लगा सकते हैं। इस मेडिकल कॉलेज का इतना बुरा हाल है कि यदि कोई भी व्यक्ति दवाई लेने जाता है तो बदबू के कारण मुहँ को ढककर जाना पड़ता है। अस्पताल में डॉक्टर्ज और नर्सें नहीं हैं। अस्पताल के ऑपरेशन थियेटर की इतनी बुरी हालत है कि हमारे विधायक की पत्नी को दिल की बीमारी की दिक्कत हो गई थी और उन्हें एमरजैंसी में एडमिट करवाया गया था। जिस बैड पर उन्हें एडमिट किया गया था वह खून से सटी हुई थी। उपाध्यक्ष महोदया, इस मेडिकल कॉलेज की यह स्थिति बनी हुई है तो हम स्वास्थ्य की सेवाओं में आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं ? उपाध्यक्ष महोदया, मैं तो यह कहता हूँ कि सरकार को पहले तो इस तरह के मेडिकल कॉलेजों की स्थिति को सुधारना चाहिए।

कैप्टन अभिमन्यु: उपाध्यक्ष महोदया, मुझे जरूरी विषय के लिए जाना पड़ रहा है, इसलिए माननीय संसदीय मंत्री जी सदन में उपस्थित रहेंगे। जिस समय बजट पेश हो रहा था, उस समय माननीय प्रतिपक्ष नेता काम की व्यस्तता के कारण सदन में उपस्थित नहीं थे लेकिन जब माननीय प्रतिपक्ष नेता अपना जवाब देंगे तो मैं जरूर सदन में उपस्थित रहूँगा।

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदया, मैंने अध्यक्ष महोदय से रिकवैस्ट कर ली थी कि मैं बजट के दौरान दिल्ली में हूँ, इसलिए सदन में उपस्थित नहीं हो सकता।

कैप्टन अभिमन्यु: अभय जी, निश्चित तौर पर आपको जरूरी काम रहा होगा।

12.00 बजे **श्री अभय सिंह चौटाला** : उपाध्यक्ष महोदया, फरीदाबाद में वर्ष 2011 में एक मेडिकल कॉलेज बना था। (विघ्न) सीमा त्रिखा जी, आप यह बात ध्यान से सुनिये। आप जब बजट पर बोलें तो आप भी इस बात को उजागर करना। वर्ष 2011 में फरीदाबाद में गोल्ड फील्ड इंस्टीच्यूट के नाम से साइंस एंड रिसर्च इंस्टीच्यूट बनाया गया और हर साल सौ बच्चों का एडमिशन किया गया। इस तरह उसके अंदर 400 से ज्यादा बच्चों का एडमिशन हुआ। 4 वर्ष तक मेडिकल कॉलेज ने उनसे फीस ली और फीस के साथ-साथ एडमिशन के लिए डोनेशन भी लिया। अब 4 वर्ष के बाद उस मेडिकल कॉलेज की हालत यह हो गई है कि मैनेजमैंट ने उस कॉलेज को ताला लगा दिया है। वे कॉलेज चलाने में सक्षम नहीं रहे। यह पिछली सरकार की गलती का नतीजा है। सरकार को उस मेडिकल कॉलेज को एन.ओ.सी. नहीं देनी चाहिए थी। पिछली सरकार जितने भी निर्णय करती थी वे ऐसे होते थे जिससे लोगों को तंगी, असुविधा और परेशानी होती थी। भाजपा सरकार कहती है कि हम हैल्थ को बढ़ावा देना चाहते हैं और हैल्थ की कमी को पूरा करना चाहते हैं। सदन में बार-बार डॉक्टरों की कमी की बात उठी है। ये 400 बच्चे अब फाइनल ईयर में हैं और इन्होंने केंद्रीय हैल्थ मिनिस्टर नड्डा साहब, प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी और अनेक प्रभावी लोगों के पास जाकर यह बात कही कि हमारा भविष्य खराब हो रहा है और हमें हरियाणा प्रदेश या देश में किसी भी मेडिकल कॉलेज में टैस्ट लेकर अपनी पढ़ाई को पूरा करने दिया जाए ताकि हमने 4 वर्ष में जो पैसा खर्च किया है और अपने जीवन के 4 वर्ष मेडिकल की पढ़ाई पर लगाए हैं वे बेकार न जाएं। बड़ी हैरानी की बात है कि मुख्यमंत्री जी ने इन बच्चों को उनके भविष्य के प्रति आश्वस्त नहीं किया और न ही हैल्थ मिनिस्टर ने उनके साथ हुए खिलवाड़ पर उनकी मदद करने का आश्वासन दिया। एक तरफ तो सरकार हैल्थ को बढ़ावा देने की बात करती है, दूसरी तरफ उनके साथ हो रहे खिलवाड़ पर चुप है। उन बच्चों को अगर सरकार चाहे तो अपने इंस्टीच्यूट्स में ऐडजस्ट करके डिग्रियां पूरी करवा सकती है। प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से आग्रह कर सकती है कि इन 400 बच्चों का भविष्य खराब न हो इसके लिए आप इनको अलग-अलग मेडिकल इंस्टीच्यूट्स में एक-एक सीट पर दाखिला दिलवाकर शिक्षा पूरी करवाए ताकि उनकी 4 वर्ष की मेहनत सफल हो सके। मैं उम्मीद करूंगा कि जब माननीय वित्त मंत्री जी अपने बजट भाषण का जवाब देंगे तो इस विषय पर सदन को जरूर बताएंगे कि प्रदेश सरकार क्या निर्णय लेने जा रही है ?

श्री राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला जो बात कह रहे हैं वह बिल्कुल सही है। पिछली सरकार ने फरीदाबाद में इंडियन मेडिकल काउंसिल की इजाजत के बिना ही मेडिकल कॉलेज खोलने की इजाजत दे दी थी। पिछली सरकार ने ऐसे कई

[श्री राम बिलास शर्मा]
गलत निर्णय किये थे। उस मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे 4 वर्ष से पढ़ रहे थे उनकी आगे की शिक्षा की व्यवस्था पी.जी.आई. रोहतक और अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में करने की कोशिश की जा रही है। सरकार उनकी 4 वर्ष की मेहनत का पूरा ध्यान रख रही है और उनके लिए व्यवस्था करने का प्रयास कर रही है।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में कानून एवं व्यवस्था की बात करना चाहूंगा। आज प्रदेश की कानून-व्यवस्था की हालत ऐसी है कि आपने जो आंकड़े दिए हैं अगर कोई उनको ध्यान से देख ले तो स्वयं उसका अंदाजा लगा सकता है कि हमारे प्रदेश की कानून-व्यवस्था की हालत कैसी है। आज प्रदेश का हर व्यक्ति अपराधियों से परेशान है। प्रदेश में अपराधियों की सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं हो रही हैं। महिलाओं के साथ-साथ दलित वर्ग भी अपराधियों का शिकार हो रहा है। कमजोर वर्ग के लोगों और व्यापारी वर्ग के लोगों के साथ आए दिन कहीं न कहीं इस किस्म की घटनाएं होती हैं। अगर आंकड़ों पर जाएं तो कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन दो से तीन बलात्कार की घटनाएं और दो से तीन अगवा की घटनाएं न होती हों। कोई दिन ऐसा नहीं है कि जब तीन से ज्यादा हत्याएं न होती हों। ये इस तरह की हत्याएं होती हैं जिनका किसी को पता नहीं चलता कि यह हत्या कौन कर गया और किस लिए कर गया। मंत्री जी, आप नोट कर रहे हैं इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मानकर चलें कि कानून व्यवस्था में तब तक सुधार नही हो सकता जब तक कि मंत्रीगण किसी अपराधी को संरक्षण देना बंद नहीं कर देते। मंत्रीगण अगर अपराधियों को सजा नहीं देंगे तो 100 फीसदी अपराध बढ़ेंगे। उपाध्यक्ष महोदया, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की पंचायतों के चुनावों की बात यहां बताना चाहता हूं। कृषि मंत्री श्री ओमप्रकाश धनखड़ जी यहां बैठे नहीं हैं, वे एक गांव में गए थे और गांव के उस व्यक्ति के घर चाय पीकर आए थे जिस व्यक्ति के खिलाफ एक दलित महिला ने 376 का मुकदमा दर्ज करवाया हुआ है। उपाध्यक्ष महोदया, मंत्री जी उस व्यक्ति के घर चाय पीकर उसको बढ़ावा देने का काम करके आए थे। उस दलित महिला ने जिस व्यक्ति के खिलाफ 376 का पर्चा दर्ज करवाया हुआ है, उसको अरैस्ट करना तो दूर उसके खिलाफ इन्कवायरी तक नहीं करवाई गई। उपाध्यक्ष महोदया, केवल यही नहीं बल्कि उसके दो दिन बाद जब जिला परिषद के लिए पंचायतों के वोट डल रहे थे तो 4 लोग ऐसे आए जिनके खिलाफ धारा 307 का मुकदमा था। वे चारों भगोड़े थे। पुलिस ने उन चारों को अरैस्ट कर लिया। मैंने सिरसा के एस.पी. से पूछा कि आपने उन चारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है तो उसने बताया कि वे चारों भगोड़े थे और उनको पकड़ लिया गया है लेकिन उन चारों लोगों को थाने में ले जाकर छोड़ दिया गया। उपाध्यक्ष महोदया, अगर ऐसे व्यक्ति को संरक्षण दिया जाता है तो मानकर चला जाए कि इससे अपराध बढ़ेंगे न कि घटेंगे। उपाध्यक्ष महोदया, यही नहीं, मुख्यमंत्री जी भी यहां बैठे नहीं है, यदि वे बैठे होते तो मैं उनसे भी पूछता कि जब पहला सैशन था तो मैंने कहा था कि मेरे क्षेत्र ऐलनाबाद के गांव रंधावा में एक नर्स जिस अस्पताल में लगी हुई थी, उस अस्पताल के डॉक्टर ने उस लड़की के साथ बदतमीजी की। उपाध्यक्ष महोदया, यह कांग्रेस राज के दौरान की बात थी। यह बात मैंने विधानसभा में पहले भी उठाई थी। उस समय कांग्रेस के लोग भी यहां बैठे थे। मैंने उनसे कहा था कि आपने उस डॉक्टर को बचाने का काम किया था। उस डॉक्टर को इस लिए बचाने का काम किया गया था क्योंकि उस डाक्टर के पिता उस वक्त के मुख्यमंत्री के ओ.एस.डी. डा. के.वी.सिंह के दोस्त थे और उन्होंने उसको बचाया था। उपाध्यक्ष महोदया, मुझे उम्मीद थी कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी लेकिन

इस सरकार को बने हुए सवा साल निकल गया है लेकिन अब तक भी उस डाक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर कार्रवाई नहीं करनी थी तो कम से कम उस नर्स और डाक्टर दोनों में से किसी न किसी को ट्रांसफर ही कर दिया जाता ताकि दोबारा इस तरह की बात न हो जाए लेकिन अभी तक उस डाक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पिछले सदन में मुझे आश्वासन दिया गया था कि इस केस में कार्रवाई होगी लेकिन आज तक उस केस में कार्रवाई नहीं हुई। उपाध्यक्ष महोदया, इससे पता चलता है कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था का दिवालिया पिट गया है। उपाध्यक्ष महोदया, पिछले दिनों जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जो घटना हुई उसके बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है। बहन संतोष सारवान जी यहां बैठी नहीं है। उन्होंने काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान खुलकर बताया था कि यह एक दिन का मामला नहीं था बल्कि इसके लिए तो तीन महीने पहले से षडयंत्र रचा जा रहा था। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि 3 महीने पहले एम्बूलैंस के अंदर पैट्रोल के ड्रम्ज रखकर अलग अलग जगहों पर रखवाए गए। अपनी बात में उन्होंने यह भी कहा कि अलग अलग जगहों को चिन्हित किया गया कि किस किस जगह आगजनी फैलानी है। उन्होंने यह भी कहा था कि स्प्रे की जो टंकी होती है उसमें पैट्रोल भरकर छिड़काव करके दुकानों और सरकारी सम्पत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। अगर उनको जानकारी तीन महीने पहले थी तो आपका प्रशासन कहां सोया हुआ था। यदि उनको जानकारी थी तो वह जानकारी तीन महीने पहले सरकार के नोटिस में क्यों नहीं लेकर आई। उनके नोटिस में यह जानकारी कहां से आई इस बारे में उनको जवाब देना चाहिए और सरकार को भी जवाब देना चाहिए। यदि तीन महीने पहले जानकारी थी तो हरियाणा को आग के हवाले क्यों किया गया। इसमें केवल कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेवार नहीं है बल्कि सरकार भी जिम्मेवार है। इसका मतलब यह है कि सरकार 100 प्रतिशत फेल हो चुकी थी। आज सरकार महिलाओं की बात कर रही है और 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान की चर्चा होती है लेकिन हैरानी की बात है कि हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या 10 प्रतिशत से भी कम है। हमारी सरकार के समय में तय हुआ था कि पुलिस विभाग में 20 प्रतिशत महिलाओं की भर्ती की जायेगी ताकि उनकी पोस्टिंग थानों में की जा सके और महिलाओं को सुरक्षा दी जा सके। इसके अतिरिक्त हमने यह भी तय किया था कि जो औद्योगिक सुरक्षा बल हमने बनाया था उसमें भी महिलाओं को लगाया जाये ताकि जहां पर इण्डस्ट्रीज में महिलाएं काम कर रही हैं वहां पर उनकी पोस्टिंग करके महिलाओं को सुरक्षा दी जा सके। लेकिन शर्मा जी बड़ी कमाल की बात है कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर पुलिस में जहा 20 प्रतिशत महिलाओं की भर्ती करने की बात थी उसकी जगह केवल 6 प्रतिशत महिलाएं ही हैं। केन्द्र सरकार ने कहा है कि पुलिस में 10 प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिंए लेकिन यहां उससे भी कम हैं। यदि पुलिस में 6 प्रतिशत से भी कम महिलाएं होंगी तो मानकर चलिये कि महिलाओं की सुरक्षा में कहीं न कहीं कमी आई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसको तुरंत प्रभाव से पूरा करना चाहिए ताकि प्रदेश में महिलाओं को पूरी सुरक्षा मिल सके।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार उसी अनुपात में पुलिस विभाग में महिलाओं की भर्ती करने जा रही है।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, वन और पर्यावरण का जिक्र बजट में आया। आज वन और पर्यावरण दोनों का सही होना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य के लिए भी स्वच्छ हवा और स्वच्छ वातावरण का होना बहुत जरूरी है। आपके प्रधान मंत्री जी का भी सपना है कि वे देश को

[श्री अभय सिंह चौटाला]

स्वच्छ, साफ सुधरा और पोल्यूशन फ्री देखना चाहते हैं और प्रधान मंत्री जी ने इसकी शुरूआत हरियाणा के करनाल से की थी। जब हमारे प्रदेश से इसकी शुरूआत हुई है तो सबसे ज्यादा लाभ हमारे प्रदेश को मिलना चाहिए। इसका सबसे ज्यादा लाभ हमें इसलिए भी मिलना चाहिए क्योंकि हम एन.सी.आर. में आते हैं। पोल्यूशन की सबसे ज्यादा दिक्कत हमें आती है क्योंकि हम दिल्ली के नजदीक हैं। हमारा गुड़गांव, फरीदाबाद और सोनीपत का एरिया दिल्ली से लगता है जो पोल्यूशन से बहुत प्रभावित होते हैं। इनके अतिरिक्त दूसरे एरियाज भी प्रभावित होते हैं। दिल्ली को सबसे ज्यादा पोल्यूटिड सिटी माना गया है। हमें उम्मीद थी कि हरियाणा को साफ सुधरा रखने के लिए बजट में अलग से हैवी अमाउंट निर्धारित की जायेगी लेकिन बजट को पढ़ा तो पता लगता है कि 2015-16 में लगभग 2004 करोड़ रुपये का प्रावधान इसके लिए किया गया था और 2016-17 के बजट में इसको कम करके 1084 करोड़ रुपये कर दिया गया जो कि 2015-16 के मुकाबले लगभग 20 करोड़ रुपये कम है। इस तरह से पैसा कम करके कहां से प्रदेश को साफ सुधरा किया जायेगा ? उपाध्यक्ष महोदया, दिखाया और दर्शाया यह जाता है कि हम पूरे देश को स्वच्छ बनाने का काम कर रहे हैं लेकिन जब स्वच्छता की बात आती है तो वहां बजट कम हो जाता है। जहां तक बेरोजगारी की बात है भारतीय जनता पार्टी के मैनीफैस्टो में लिखा था कि जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराये जायेंगे। उसके लिए सरकार ने 'हैपनिंग हरियाणा' किया और कुछ भी किया तथा कहा गया कि बेराजगारों को नौकरियां मिलेंगी। हमें तो पता नहीं उनको नौकरियाँ कब मिलेंगी ? उसके साथ-साथ मैनीफैस्टो में यह भी लिखा था कि जो 12वीं पास युवा हैं जिनको नौकरी नहीं मिली उनको 6 हजार रुपये प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। आपने यह भी कहा था कि जो बेरोजगार ग्रेजुएट्स हैं उनको आप 9000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से भत्ता देने का काम करेंगे। मैं यह बात दावे के साथ कह रहा हूं कि पूरे हरियाणा प्रदेश में एक भी 12वीं और ग्रेजुएट्स को एक नया पैसा भी सरकार की तरफ से बेरोजगारी भत्ते के रूप में नहीं दिया गया है। जबकि यह सरकार का अपना वायदा था। यह वायदा कब पूरा होगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं है लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूं कि इसकी शुरूआत भी नहीं हो पाई है। हम तो यह उम्मीद करते थे कि जो वायदा आपने किया है उसको आप आज से ही लागू कर दें लेकिन ऐसा नहीं किया गया और केवल सब्जबाग दिखाने का ही काम किया गया है। अभी इस प्रकार की बातें भी यहां पर कही गई हैं कि ये जो 'हैपनिंग हरियाणा' हुआ इससे हरियाणा प्रदेश के लोगों को पांच लाख नौकरियां मिल जायेंगी। मैंने वित्तमंत्री जी को कहा था कि हम 'हैपनिंग हरियाणा' के बारे में आपसे एक साल बाद बात करेंगे कि 'हैपनिंग हरियाणा' के मामले में आप कितने आगे बढ़े हो और 'हैपनिंग हरियाणा' के तहत कितना काम हरियाणा प्रदेश के अंदर हुआ है। जिस प्रकार के प्रदेश के वर्तमान हालात हैं मुझे नहीं लगता कि कोई एक भी कारखाना हरियाणा प्रदेश में स्थापित हो जायेगा। ऐसे ही सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पैंशन पर पहले कुल बजट का 43 प्रतिशत खर्च होता था लेकिन पिछले वर्ष यह घटकर 38 प्रतिशत रह गया। इसका मतलब यह हुआ कि हरियाणा सरकार द्वारा कोई नई भर्ती नहीं की गई है और जो लोग रिटायर हो गये उनकी जगह भी नई नियुक्तियां नहीं की गई हैं। अगर प्रदेश में सभी विभागों में नई भर्तियां नहीं होती हैं तो फिर हमें यह भी मानना पड़ेगा कि विकास के कार्यों में भी कहीं न कहीं परेशानी खड़ी हो जायेगी। अगर एक अधिकारी रिटायर हो जाता है तो उसके बाद एक अधिकारी को चार जगह का चार्ज़ दे दिया जाता है लेकिन वह अपने कार्य को चार जगह सही तरीके से सम्भाल नहीं पायेगा। इसलिए सरकारी भर्तियां भी साथ ही साथ होनी बहुत ज़रूरी हैं। अबकी बार यह खर्च

40 प्रतिशत रह गया है। जब-जब भी विकास की बात होती है तो जिन-जिन डिपार्टमैंट्स के अंदर पद खाली होते हैं सबसे पहले उनको भरा जाता है। अधिकारियों और कर्मचारियों से काम लेकर प्रदेश को तरक्की और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया जाता है। मैं यह बात भी बार-बार कहना चाहता हूं कि प्रदेश के बेरोजगारों के प्रति भी हरियाणा सरकार की पूर्ण रूप से बेरूखी है। इसी प्रकार से यहां पर शिक्षा के ऊपर भी चर्चा की गई। हम भी सरकार से बार-बार यही निवेदन करते रहे कि शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा हो। यहां यह भी कहा गया कि जो पिछली सरकार द्वारा 5वीं और 8वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को समाप्त किया गया था उनको दोबारा से चालू किया गया है। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र के लिए आबंटित किये गये बजट को देखें तो हम पायेंगे कि वर्ष 2015-16 में बजट का 16.20 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च हुआ है। माननीय मंत्री जी को इसकी पूर्ण रूप से जानकारी होगी लेकिन अब की बार का जो बजट है, होना तो यह चाहिए था कि इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिए था लेकिन इस बजट में इस राशि को बढ़ाने की बजाय इस राशि को कम कर दिया है और इस बार के बजट में यह राशि 13.34 प्रतिशत रह गई है। यहां पर शिक्षा को बढ़ावा देने की बात बार-बार की जा रही थी लेकिन अगर हम शिक्षा के निर्धारित बजट की राशि को कम कर देंगे तो फिर उस परिस्थिति में प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा कैसे मिलेगा और कैसे नये स्कूल-कॉलेज हरियाणा प्रदेश में खोले जायेंगे, कैसे टीचर्ज़ की भर्ती होगी और कहां से उनकी तनख्वाहें आयेंगी ? फिर तो हमें यही मानकर चलना पड़ेगा कि जो यहां पर शिक्षा बेहतरी के लिए बात की जा रही हे वह केवल भाषण ही है और भाषण के सिवाय इसमें कुछ भी नहीं है। हरियाणा प्रदेश के अंदर शिक्षा का सुधार कैसे होगा जब हमारे हरियाणा प्रदेश में शिक्षकों के 40 हज़ार पद खाली पड़े हों, इसी प्रकार से प्राथमिक स्कूलों के टीचर्ज़ के 2433 पद हरियाणा प्रदेश में खाली पड़े हैं। जो सीनियर सैकेण्डरी स्कूल के प्रिंसीपल हैं उनके भी हरियाणा प्रदेश में 647 पद खाली पड़े हैं। अगर इन लोगों की भर्ती नहीं होगी तो उस स्कूल का कौन जिम्मेदार होगा और उस स्कूल में पढ़ाई कैसे होगी ? मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि इस सब का ही यह परिणाम हुआ है कि हरियाणा प्रदेश में 10वीं और 12वीं कक्षाओं के परिणामों पर नज़र डाले तो फिर कोई भी मां-बाप यह नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा सरकारी स्कूल में जाकर पढ़े। आज रेवाड़ी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, झज्जर, मेवात और पलवल के आठ स्कूल ऐसे हैं जिनमें 12वीं की परीक्षा का परिणाम शून्य अर्थात ज़ीरो रहा है। आप यह मान कर चलिये कि सरकारी स्कूलों के प्रति हर आदमी के मन में एक चिन्ता होगी कि यदि मैंने गलती से अपने बच्चे को यहाँ पर भेज दिया तो मैं उससे क्या उम्मीद करूँगा। आप आंकड़े देखेंगे तो पायेंगे कि दसवीं कक्षा के 199 सरकारी और प्राईवेट स्कूलों के नतीजे शून्य आये हैं। जब इस प्रकार के नतीजे सरकारी स्कूलों के आयेंगे तो शिक्षा का उदारीकरण कैसे होगा, शिक्षा को बढ़ावा कैसे मिलेगा ? जब आप शिक्षा का बजट ही कम कर देंगे तो अच्छे नतीजे कैसे आयेंगे। मैं कहना चाहूँगा कि भिवानी और यमुनानगर दो जिले ऐसे हैं जहाँ 14-14 सरकारी स्कूलों में एक भी बच्चा पास नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदया, इसके अलावा मैं बी.एड कॉलेज के बारे में भी अपने विचार रखना चाहता हूँ। आज हरियाणा प्रदेश में 491 बी.एड कॉलेज हैं जिनमें 60762 सीट स्वीकृत हैं। उन 60762 सीटों में से 32811 सीटें ही भरी हुई हैं जबकि 27951 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। इस बारे में मेरा कहना है कि सरकार ने पॉलिसी में ढील दे कर उन लोगों को एन.ओ.सी. जारी किये हुये हैं, इस तरह के कॉलेजिज को चैक करवाया जाये। ऐसे-ऐसे लोगों को एन.ओ.सी. जारी कर दी गई जिनके पास जगह के नाम पर एक कमरा भी नहीं है और टीचर भी नहीं हैं। मैं खुद संगरिया में ग्रामोत्थान विद्यापीठ नामक बी.एड कॉलेज चलाता हूँ। हमारे पास कई बार ऐसे हालात होते हैं कि बच्चों की

[श्री अभय सिंह चौटाला]

संख्या ज्यादा हो जाती है और हमें सरकार से अनुरोध करना पड़ता है कि हमें 10-20 सीटें और दे दी जायें ताकि हम उन बच्चों को बी.एङ करवा सकें और उनका साल बर्बाद न हो। इसी प्रकार से जो बी.एङ कॉलेज हैं उनमें लैक्चरर्स की संख्या भी कम है। संख्या कम ही नहीं है बल्कि इस तरह के बी.एङ कॉलेज भी हरियाणा प्रदेश में चल रहे हैं जिनमें प्रिंसिपल भी नहीं है और लैक्चरर्स भी नहीं है लेकिन उन्होंने दूसरे कॉलेजिज के साथ एग्रीमैंट कर रखे हैं कि आप हमारे कॉलेज में भी सप्ताह में 2-3 दिन आ जाया करो ताकि हम सरकार को यह दिखा सकें कि हमारे पास स्टाफ पूरा है। आप इसकी भी जांच करवाईये क्योंकि जिस प्रदेश की ऐसी हालत होगी उसमें शिक्षा को बढ़ावा कैसे मिल सकता है। इसी तरह से 'हैपनिंग हरियाणा' के लिए बड़े-बड़े दावे किये गये लेकिन आज भी जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजिज हैं उनमें सीटें खाली पड़ी हुई हैं। जब हरियाणा प्रदेश में इंजीनियरिंग की सीटें ही पूरी नहीं भरी जायेंगी तो आपको 'हैपनिंग हरियाणा' के लिए इंजीनियर कहाँ से मिलेंगे ? (शोर एवं व्यवधान)

मुख्य संसदीय सचिव (श्री श्याम सिंह राणा) : उपाध्यक्ष महोदया, मेरी एक बात बीच में ही रह गई थी। यहाँ पर ओलम्पिक संघ की बात कही गई थी। उस समय एक बात अनसुनी हो गई थी जिसमें चौधरी अभय सिंह चौटाला भी पूरा इन्ट्रस्ट लेते हैं। उस समय विज साहब ने कहा था कि हम तो यही चाहते हैं कि खिलाड़ियों का ज्यादा नुकसान न हो इसलिए इस मसले पर सहमति बननी चाहिए। हम विज साहब की इस बात से सहमत हैं कि प्रदेश में ओलम्पिक के खेल होने चाहिएं। उसमें विपक्ष के नेताओं का भी सहयोग चाहिए। सभी दल मिलकर यदि कोई फैसला करें तो उसमें सहमति जतानी चाहिए। हम सभी को प्रदेश और प्रदेश के खिलाड़ियों के हित में कार्य करना चाहिए। इस बारे में मेरा नेता प्रतिपक्ष श्री अभय सिंह चौटाला जी से अनुरोध है कि वे अपना कोर्ट केस वापिस ले कर इस मामले में सर्वसम्मति बना लें। इससे खिलाड़ियों को भी फायदा होगा। इस मामले में भी सर्वसम्मति होनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य श्री श्याम सिंह राणा जी अपना सुझाव श्री धर्मबीर जी को दे दें जो फर्जी बना हुआ है मुझे इनके सुझाव की जरूरत नहीं है। आप राणा साहब से पूछिये कि ये कौन सा इलैक्शन जीत कर आये थे। ऐसे ही फोटो खिंचवा लिया और कह दिया कि मैं भी ओलम्पिक संघ हरियाणा का अध्यक्ष हूँ। मुझे पहले बजट पर अपनी बात कहने दो। उपाध्यक्ष महोदया, मैं 'हैपनिंग हरियाणा' की बात कर रहा था। बजट में भी 'हैपनिंग हरियाणा' के बारे में बहुत कुछ दिखाया गया है और हम भी यही चाहते हैं कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आये और यह प्रदेश टैक्स फ्री बने। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि प्रदेश में बिजली के बढ़े हुये बिल वापस हों ताकि लोगों को दिक्कत न हो और प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा विकास के काम हों। उपाध्यक्ष महोदया, जिस ढ़ग से एम.ओ.यूज. साईन हुए हैं और जिन कंपनियों के साथ एम.ओ.यूज. साईन हुए हैं आप उनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि उनकी वजह से सरकार को कोई पैसा आ जाएगा। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि एक एम.थ्री.एम. कंपनी है वह कंपनी बैंक की डिफॉल्टर है जिसके मालिक ने एक फ्लैट पर कब्जा कर रखा है जो किराया देने में भी सक्षम नहीं है उस कंपनी के साथ सरकार ने 45 हजार करोड़ रुपये का एम.ओ.यू. साईन किया है जो केवल और केवल अखबारों में दिखाया गया है कि हमने 45 हजार करोड़ रुपये के एम.ओ.यूज. साईन किये हैं। इसी तरह से मैं एक कंपनी के बारे में और आपके सामने बताना चाहूंगा वैसे कंपनियों तो बहुत सारी हैं।

श्री नरबीर सिंह : इन कंपनियों से तो आपका भी बहुत पुराना रिश्ता है।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, मेरा इनके साथ कोई रिश्ता नहीं है मेरा तो डी.एल.एफ. वाले से रिश्ता है मेरा तो राज सिंह से रिश्ता है जो आज भी है लेकिन आप कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से भी पूछना कि इनसे उनके रिश्ते हैं या नहीं ? इसमें एक डी.एम.आई.एफ.सी. की बात आयी थी जो दिल्ली से मुम्बई इण्डस्ट्रियल डेडिकेटिड फ्रेट कौरीडोर जो बनाया जा रहा है। उसमें 1 लाख 31 हजार करोड़ रुपये के निवेश का एम.ओ.यू. साईन किया गया है लेकिन यह प्रौजेक्ट तो आज का नहीं है। जबकि इसका एम.ओ.यू. आपने आज साईन किया है इस तरह केवल ये दिखाने के लिए कि हम इसके साथ एक एम.ओ.यू. साईन करके 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपये का निवेश हरियाणा प्रदेश में लेकर आ रहे हैं, लेकिन यह सात वर्ष पुराना प्रौजेक्ट है। सात साल पहले इसको मंजूरी मिली थी और अब तक भी इसके लिए जमीन ऐक्वायर नहीं हुई है। जब जमीन ही ऐक्वायर नहीं हुई तो आप मानकर चलो कि यह बनेगा कैसे ? आप सात साल पुरानी चीज को उठाकर कहते हो कि यह हम करने जा रहे हैं। इसी तरह से जो के.एम.पी. अर्थात कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस हाई-वे बन रहा है, वह हमारी सरकार के समय में मंजूर हुआ था और उसकी आधारशिला भी जब चौधरी ओमप्रकाश चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे, उस समय रखी थी लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 10 साल तक इसको इसलिए आगे नहीं बढ़ाया था क्योंकि जिस आदमी को कांग्रेस पार्टी ने इसको बनाने का टैंडर दिया था, उसी के पास गुडगांव और दिल्ली रोड़ के बॉर्डर पर जो टॉल टैक्स है, उसका टैंडर भी उसी आदमी के पास था। केवल इसलिए उसको नहीं बनाया क्योंकि अगर उस टॉल टैक्स से गुजरने वाले वाहन दूसरी साईड से जाने लग जाएंगे तो उसको वहां पर टैक्स वसूली नहीं होगी इसलिए उसको आगे नहीं बढ़ाया गया।

श्री राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, नेता प्रतिपक्ष आज बहुत तैयारी के साथ बोल रहे हैं मैं उनका अभिनन्दन करता हूं। इतिहास इस बात का गवाह है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में 70 हजार करोड़ रुपये चतुर्भज योजना, स्वर्णिम सड़क योजना तथा प्रधानमंत्री सड़क योजना पर खर्च किए गए थे और जैसाकि अभय सिंह चौटाला जी अभी कह रहे थे कि कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रैस हाईवे का कार्य इनकी सरकार के समय मंजूर हुआ था, तो उस परिपेक्ष्य में मैं सदन में यह भी बताना उचित समझता हूँ कि यद्यपि हरियाणा में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी सत्तासीन थे लेकिन केन्द्र में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। कहने का मतलब यह है कि जो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रैस हाईवे मंजूर हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र सरकार का रोल किसी भी सूरत में नकारा नहीं जा सकता है। कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रैस हाईवे का जिस कम्पनी को ठेका दिया गया था वह कम्पनी इसलिए काम छोड़ गई, it is written in the record कि 'मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है' और वह कम्पनी 100-200 करोड़ रुपये का जुर्माना भरकर चली गई।

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदया, यह कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रैस हाईवे हमारी सरकार के समय में मंजूर हुआ था लेकिन अब उस पर एक नया पत्थर लगा दिया गया है। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि किसी चीज की रिनोवेशन होती है तो उसके लिए भी नया पत्थर लगया जाता है। नई चीज बनाओ और उस पर पत्थर लगाओ तो ज्यादा अच्छा रहता है। (शोर एवं व्यवधान)

खनन एवं भू-विज्ञान राज्य मंत्री (श्री नायब सैनी): उपाध्यक्ष महोदया, मैं नेता प्रतिपक्ष के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जब यह कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रैस हाईवे इनकी सरकार में मंजूर हुआ था तो उस समय इस पर कोई भी काम नहीं हुआ था। उस समय इस कार्य पर 10 रुपये भी खर्च नहीं हुए थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदया, नायब जी को बताना चाहूँगा कि जब कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रैस हाईवे हमारी सरकार के समय मंजूर हुआ तो बाकायदा उसके लिए फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। किसी के फाउंडेशन स्टोन को दबाना अच्छी बात तो नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नायब सैनी: उपायक्ष महोदया, अभय जी को इस बात की भी भलीभांति जानकारी है कि केवल पत्थर लगाने से काम पूरे नहीं होते हैं। कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रैस हाईवे इनके समय में मंजूर हुआ था लेकिन बावजूद इसके इस पर काम तो कुछ भी नहीं करवाया गया था। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ पवन सैनी: उपाध्यक्ष महोदया, ऐसे तो हमारी पंचायतें पता नहीं कितने रिजोल्यूशन पास करती है सिरे तो एक-आध ही चढ़ता है। पत्थर लगाने से कुछ नहीं होता है, काम करके दिखाना पड़ता है और उसमें हमारी सरकार पूरी तरह सीरियस है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदया, यह पवन सैनी मेरे को फिर इंट्रप्ट कर रहा है। इसको मामले की जानकारी तक तो है नहीं। (शोर एवं व्यवधान) यह अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है। (शोर एवं व्यवधान) इसको बिठाओ। (शोर एवं व्यवधान) मैं आपकी परमिशन से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यदि पवन सैनी इसी तरह की हरकत करता रहा तो सदन का समय जाया होगा। (शोर एवं व्यवधान) मैं किसी भी कीमत पर सदन का समय जाया नहीं करना चाहता। (शोर एवं व्यवधान) क्या मेरे सवाल का जवाब पवन सैनी देगा? मैं कुछ कड़वी बात कहूँगा तो फिर किसी न किसी को तकलीफ होगी। (शोर एवं व्यवधान) यह ऐसे ही बेवजह बीच में खड़ा हो जाता है। यह कोई उचित बात नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा: उपाध्यक्ष महोदया, माननीय अभय जी को गुस्सा न करके मीठा-मीठा बोलना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदया, मैं तो हर वक्त मीठी-मीठी बातें करता हूँ। (शोर एवं व्यवधान) मैंने ऐसी कौन सी बात कही है जिसकी वजह से किसी को छोटी-मोटी भी तकलीफ हुई हो लेकिन बावजूद इसके फिर पवन सैनी जैसा व्यक्ति बीच में खड़ा होकर इंट्रप्ट करने लग जाता है। (शोर एवं व्यवधान) मैं तो केवल मात्र बजट पर ही बात कर रहा हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री (श्री कर्ण देव कंबोज) : उपाध्यक्ष महोदया, अभय जी मीठी बातें कर रहे हैं तो ऐसी बातों को कहकर बताने की जरूरत नहीं। ऐसी बातों का तो अपने आप ही अहसास हो जाता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा: उपाध्यक्ष महोदया, अभय जी ने जो अपने हाथ में मोटे-मोटे टाईप किए हुए कागज पत्र लिए हुए हैं, उन्हें हमें दे दें हम उनको आश्वास्त करते हैं कि निश्चित रूप से इनको सदन की कार्यवाही में छपवा दिया जायेगा।

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदया, राम बिलास जी केवल छापने का ही काम करेंगे या फिर असलियत में भी कुछ कर दिखायेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा: उपाध्यक्ष महोदया, हम अभय जी की बात रिकॉर्ड में छपवा भी देंगे और कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रैस हाईवे को भी पूरा करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री तेजपाल सिंह तंवर (सोहना) : उपाध्यक्ष महोदया, अभय जी मीठा और कड़वा दोनों का इकट्ठा कैसे प्रयोग कर लेते हैं ? (हंसी) (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदया, अभी कुछ दिन पहले सरकार की तरफ से 'हैपनिंग हरियाणा' कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मैं आज सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि 'हैपनिंग हरियाणा' के तहत ऐसी कम्पनियों के साथ भी एग्रीमैंट हुए हैं जिनकी हालात बहुत जर्जर है। यूनीटेक नाम की कम्पनी हरियाणा में काम करती रही है। पिछले दिनों लोगों ने इस यूनीटेक कम्पनी के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवाई थी तथा इसके ऑफिस के आगे धरने दिये थे और सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर अपनी व्यथा बताई थी कि हमने इस कम्पनी के साथ मिलकर फ्लैट बुक करवाये थे। हमने इनको पैसा दिया और इन्होंने जो हमें तारीखें दी उसके मुताबिक इस कम्पनी ने कुछ नहीं बनाया। अत: या तो हमारा पैसा वापस दिलाया जाये या फिर हमें फ्लैट दिये जायें। जब सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई तो लोग कोर्ट में चले गये। कोर्ट ने यूनीटेक के चेयरमैन को टाईमबाउंड करते हुए कहा कि इतने दिन में लोगों के पैसे दो। जब चेयरमैन ने पैसे नहीं दिये तो फिर उसको जेल भेजने का काम किया गया। यह आदमी जेल से जमानत पर आया और आकर सरकार के साथ एम.ओ.यू. साईन कर लिया। जिसके पास 46 करोड़ रुपये देने को नहीं था उसका भी एम.ओ.यू. सरकार के साथ साईन हुआ है। जब ऐसी कम्पनियों के साथ एम.ओ.यू. साईन किए जायेंगे तो फिर ऐसे लोगों से क्या बेहतर करने की आशा की जा सकती है। कहां से यह कम्पनी पैसा लायेगी, कैसे इंवेस्ट करेगी तथा किस तरह से किसी प्रोजैक्ट को खड़ा करने का काम करेंगी ?

श्री अभय सिंह यादव (नांगल चौधरी): उपाध्यक्ष महोदया, अभय जी को इस तरह की बातें एक साल बाद पूछनी चाहिए। पहले काम तो होने दीजिए। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदया, मैं यादव जी को बताना चाहूँगा कि मैं इसके बारे में एक साल के बाद ही पूछूंगा। आज तो मैंने इन सभी बातों का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि 'हैपनिंग हरियाणा' पर चर्चा हो रही थी। उपाध्यक्ष महोदया, ऐसा ही एक और एम.ओ.यू. टैक्सी चलाने वाली कम्पनी 'उबर' के साथ भी साईन हुआ। जब टैक्सी चलाने वाली कम्पनीज के साथ भी एम.ओ.यू. साईन किए जायेंगे तो फिर आप यह मानकर चलो कि यह सब कुछ दिवालिया होने की ही निशानी हैं। 'उबर' कम्पनी यह काम करती है, जैसे मान लो मेरी खुद की गाड़ी है और मैं ही उसे चलाता हूँ। कम्पनी ने मेरे साथ एक एग्रीमैंट किया हुआ है कि जिस इलाके में मैं रहता हूँ उस इलाके के आसपास से यदि किसी आदमी का टेलीफोन आयेगा तो मुझे उस आदमी को लेकर

[श्री अभय सिंह चौटाला]

वह जहां जाना चाहे उस जगह पर छोड़कर आना पड़ेगा। इस तरह से कम्पनी के पास अपनी कोई भी गाड़ी नहीं है बल्कि सारी गाड़ियां इस तरह के लोगों से इक्ट्ठी की हुई है। उपाध्यक्ष महोदया, जिस कम्पनी के पास अपना पैसा और साधन नहीं है, उस कम्पनी पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। 'हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मिट' में इस तरह के एम.ओ.यू. साईन करके लोगों को गुमराह करके भ्रम पैदा किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं उम्मीद करूँगा की ऐसी बातें ना करके उसकी तरफ आगे बढ़ो जिससे प्रदेश का विकास हो सके। मैं उम्मीद करूँगा कि जब माननीय मंत्री जी इसके ऊपर सदन में विस्तार से बताएंगे और मैंने आपके माध्यम से जो-जो बातें पूछी हैं उन सबका भी जवाब देने का काम करेंगे। उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे वर्ष 2016-17 बजट अनुमानों पर बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राम बिलास शर्मा: उपाध्यक्ष महोदया, माननीय प्रतिपक्ष नेता ने बजट को लेकर के हर पहलू पर चर्चा की है। यह ठीक है कि बहुत सारी सही बातें सरकार की मदद करने वाली है। परंतु आपके जवाब में संदेह ज्यादा दिखाई देता है। उपाध्यक्ष महोदया, आप शिक्षा से जुड़ी हुई हैं अगर हम शिक्षा के बारे में बात करें तो पिछले साल कई जिलों में एक भी विद्यार्थी पास नहीं हुआ था, इस बात को आप अच्छी तरह से जानती है। एक साल की पढ़ाई का परिणाम मार्च में आता है। पिछली बार जो परिणाम आया वो कांग्रेस सरकार में जो कुछ हुआ है उसका आया है। उपाध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार को बने अभी 16 महीने ही हुए हैं, इसलिए इस बार जो परिणाम आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के समय में आएंगे। माननीय प्रतिपक्ष नेता ने 'हैपनिंग हरियाणा-ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मिट' के बारे में बातें कही हैं, उपाध्यक्ष महोदया आप जानती हैं कि 'हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मिट' किन हालातों में हुआ है, यह बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। जिस बात को लेकर आंदोलन हुआ उससे हरियाणा का मान सम्मान मिट्टी में मिल गया और हरियाणा का खजाना भी लूट लिया गया, आज वही बिल इस सदन में सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से पास किया है। परंतु आज आरक्षण के बिल के ऊपर भी कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को सदन में आने पर शर्म महसूस हुई है। उपाध्यक्ष महोदया, 'हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मिट' चारों तरफ से दबाव होने पर आयोजन किया गया था, इसके लिए मैं चाईना की वाडा ग्रुप की कम्पनी के चेयरमैन को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने 2 मार्च, 2016 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास टेलीफोन किया था। चाईना मैं भी गया था, इसलिए मेरे पास भी टेलीफोन आया था, कम्पनी के चेयरमैन कहने लगे कि हम आपकी हिम्मत की दाद देते हैं। उपाध्यक्ष महोदया, विषम परिस्थितियों में दिनांक 7-8 मार्च, 2016 को 'हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मिट' का आयोजन गुड़गांव में हुआ था। उपाध्यक्ष महोदया, इस सम्मिट का आयोजन चौधरी अभय सिंह चौटाला के प्रिय मित्र श्री राज सिंह गहलोत के लीला होटल में हुआ था। इस आयोजन में 5 लाख 84 हजार करोड़ रुपये के निवेश के साथ 359 एम.ओ.यूज. साईन हुए थे। चाईना की वाडा ग्रुप की एक कम्पनी है, उसने सोनीपत में 30 हजार करोड़ रुपये का एम.ओ.यू. साईन किया था। उपाध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से माननीय प्रतिपक्ष के नेता से कहना चाहता हूँ कि थोड़ी सी उम्मीद जरूर रखें, हर बात पर संदेह ना करें।

श्रीमती संतोष चौहान सारवान (मुलाना) (अनुसूचित जाति): उपाध्यक्ष महोदया, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने मेरे नाम का उल्लेख करके यह घटना बताई है कि मुझे 3 महीने पहले जाट आंदोलन की सारी जानकारी थी तो मैंने सरकार को क्यों नहीं बताई ?

उपाध्यक्ष महोदया, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटती हैं, जिनके बारे में जानकारी हमेशा बाद में ही उपलब्ध होती है, पहले नहीं मिलती है। तीन महीने से पहले यह योजना बन रही थी इस बात की जानकारी भी मुझे इस घटना के घटने के बाद मिली थी। जो जानकारी मुझे मिली है उसे मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ हाउस में बता रही हूं। जैसे ही मुझे जानकारी मिली मैने उससे माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कर दिया था लेकिन पहले मुझे भी यह जानकारी नहीं थी। इस तरह की बातें कोई चौक पर बैठकर या रैली करके नहीं करता है या फिर पंचायत करके नहीं करता है। उन लोगों ने ये योजनाएं बहुत ही गोपनीय तरीके से बनाकर घटना को अंजाम दिया था। मैं ये बात खुले तौर पर कहना चाहूंगी क्योंकि इसमें न तो कुछ गलत है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। अगर कोई कांग्रेस का साथी एतराज करता है तो वह मुझसे मिल ले मैं उन्हें तथ्य दे दूंगी क्योंकि मैं सत्य के आधार पर बोल रही हूं। इस महान सदन में सामने लिखा हुआ है कि- 'या तो सदन में प्रवेश न करें और प्रवेश करें तो सत्य बोलें, असत्य न बोले।' मैंने किसी को गुमराह करने वाली घटना यहां नहीं बताई है। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी यह बात बता चुके हैं। यह दृश्य सी.सी.टी.वी. कैमरे में भी कैद है कि किस तरह से एम्बूलैंस में पैट्रोल और डीजल के टैंक्स रखकर लाए गए और वह घटना भी सी.सी.टी.वी. कैमरे में कैद है जब सप्रे करने वाली मशीन से पैट्रोल और डीजल का सप्रे किया गया और चुन-चुनकर लोगों के घरों, दुकानों और व्यापारिक संस्थानों को लक्ष्य करके जलाया गया। यह सब सी.सी.टी.वी. कैमरे में कैद है। नेता प्रतिपक्ष इस बात की पूरी तरह से तसल्ली कर लें कि मैंने झूठ या गलत बात नहीं कही है। जैसे ही मुझे तथ्यों की जानकारी मिली ... (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्या ने सदन में कहा कि उन्हें यह जानकारी तीन महीने पहले ही थी। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इनको यह जानकारी कहां से मिली है ? (विघ्न)

श्रीमती संतोष चौहान सारवान : उपाध्यक्ष महोदया, मैं अभी भी अपनी बात पर अडिग हूं। मुझे इस घटना की जानकारी घटना होने के बाद मिली है। मैंने जानकारी प्राप्त होते ही माननीय मुख्यमंत्री जी को अलग से जाकर इसके बारे में सूचित कर दिया था। (विघ्न)

श्री नसीम अहमद : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्या ने तो कांग्रेसियों को अपना फ्लैट भी दे रखा है। पूर्व विधायक श्री सम्पत सिंह इनके फ्लैट में रह रहे हैं। (विघ्न)

श्रीमती संतोष चौहान सारवान : उपाध्यक्ष महोदया, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। मुझे जब फ्लैट अलॉट हुआ था मुझे उसकी पोजेशन कभी नहीं मिली और.. (विघ्न) आप एक मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए। (विघ्न) मैंने वह फ्लैट श्री सम्पत सिंह को रहने के लिए नहीं दिया है। माननीय सदस्य इस गलतफहमी में न रहें कि मैंने उनको वह फ्लैट रहने के लिए दिया था। मैं माननीय सदस्य की गलतफहमी दूर कर दूंगी चूंकि मुझे उसका पोजेशन आज तक नहीं मिला है। वे उस फ्लैट में पिछले दस साल से रह रहे थे और उन्होंने मुझे फ्लैट खाली करके नहीं दिया। वह फ्लैट उनके कब्जे में है। मैं एक बात और क्लीयर कर दूं। (शोर एवं व्यवधान) मैं उनके साथ लाठी या गोली चलाकर फ्लैट पर कब्जा नहीं ले सकती। मैंने उनको दो बार लिखकर दिया है कि मेरे फ्लैट को खाली कराकर मुझे दिया जाए। मैं इस बारे में स्पीकर साहब से दर्जन बार मिल चुकी हूं। मेरे फ्लैट पर वे धक्के से कब्जा करके बैठे हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, किसी सदस्य का फ्लैट कोई पूर्व विधायक कब्जा करके बैठा है और वह विधान सभा का वर्तमान सदस्य होने के साथ-साथ महिला भी है तो यह उनके साथ अन्याय है। (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया: चौटाला जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि माननीय सदस्या का मेरे पास ...(विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, अगर कोई सदस्य फ्लैट खाली नहीं करता तो उसको पहले तो उसे फ्लैट खाली करने के लिए नोटिस दिया जाता है। उसके बाद भी वह फ्लैट खाली नहीं करता तो फ्लैट के बिजली और पानी के कनैक्शन काट दिये जाते हैं। अगर वह फिर भी खाली नहीं करता है तो पुलिस द्वारा उसे उठाकर बाहर फैंक दिया जाता है। आपकी सरकार 16 महीने से क्या कर रही है जब एक महिला सदस्या का एक फ्लैट खाली नहीं करवा सकी। (विघ्न) फिर हम आपसे क्या उम्मीद कर सकते हैं ? (विघ्न) आप इसे टाइम बाउंड करिये कि कितने दिन में वे फ्लैट खाली कर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदया: संतोष सारवान जी का जो मसला है इस बारे में उनकी स्पीकर साहब से बात हुई है और यह बात मेरे नोटिस में नहीं आई है इसलिए हम बात करके इस मसले को सुलझा देंगे।

श्री राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, नसीम अहमद जी ने अपने सवाल में संतोष जी के बारे में जो कहा है, मैं उसके लिए नसीम जी को बताना चाहता हूं कि इस बार हरियाणा सरकार के इतने ज्यादा फ्लैट्स का निर्माण हो रहा है कि कोई विधायक बिना निवास के नहीं रह जाएगा। सम्पत सिंह जी, क्योंकि इस पंथ में से निकले हुए आदमी हैं। हम तो अपने पंथ पर ज्यों के त्यों हैं। केवल इस महान सदन में एक गरीब आदमी ऐसा है जिसने कभी अपना पंथ नहीं बदला। 1991 में भी हम यहां पर थे और हमको अपने पिछले पंथ का लिहाज है। प्रोफैसर सम्पत सिंह जी इस पंथ से निकले हुए हैं अन्यथा हमें संतोष जी का फ्लैट खाली करवाना आता है। (विघ्न)

डॉ० अभय सिंह यादव (नांगल चौधरी): उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं यहां पर बजट के समर्थन में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी यहां बैठे नहीं है लेकिन वे जहां भी बैठे हैं जरूर सुन रहे होंगे। मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो यह बजट प्रस्तुत किया है, बहुत अच्छा बजट है और उसके लिए मैं उनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने भविष्योन्मुखी बजट पेश किया है। राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण था उसमें सरकार की पोलिसी स्टेटमैंट थी। उसको कार्यान्वित करने के लिए कि किस तरह की सरकार की स्कीमें चलेंगी, कहां से पैसा आएगा और किस तरह से पैसा खर्च होगा, यह सारा विवरण इस बजट में दिया गया है। मैं एक बार फिर उनको इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि यह बहुत अच्छा बजट है। जहां तक बजट के उद्देश्यों की बात है तो बहुत अच्छी बात बजट के शुरू में लिखी गई है- वृहत् आर्थिक परिपेक्ष्य। उसमें सरकार का ब्रोड विजन दिया गया है कि सरकार किस तरह से सबका साथ और सबका विकास यानी डिवैल्पमैंट फॉर ऑल का प्रिंसिपल लेकर चल रही है। मैं बजट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं आंकड़ों का विवरण न देकर एक दो बातें सुझाव की शक्ल में जोड़ना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि माननीय वित्त मंत्री जी जहां भी बैठे हैं सुन रहे होंगे और ध्यान से नोट करेंगे। पहली बात

औद्योगिक विकास की मैं करना चाहूंगा। हरियाणा में औद्योगिक विकास का जो ट्रैंड अब तक हम लोगों ने देखा है उसमें यह है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत चाहत के क्षेत्र हैं और वहां इन्वैस्टर्स भी जाना चाहते हैं। सरकार की तरफ से भी उनकी मार्किटिंग हो रही है। हरियाणा लगभग 3 तरफ से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को छूता है यानी ऐसी उसकी लोकेशन है। राष्ट्रीय राजधानी के नजदीक के जो इलाके हैं उन इलाकों में विकास ज्यादा हुआ है और इंडस्ट्रियल विकास भी ज्यादा हुआ है। उसका परिणाम अब यह हुआ है कि वहां जमीन की उपलब्धता अपने आप में एक समस्या बन गई है। बड़ी-बड़ी योजनाएं उन इलाकों के लिए पिछली सरकारें भी बनाती रही हैं। हमारी सरकार ने भी इन्वैस्टर्स सम्मिट का आयोजन वहां किया है। हमारे वित्त मंत्री, उद्योग मंत्री जो पढ़कर बता रहे थे उससे लगता है कि इन्वैस्टर्स की रुचि और ट्रैंड भी उन इलाकों की ही तरफ है। लेकिन अभी भी महेन्द्रगढ़ और भिवानी जैसे कुछेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां विकास वांछित है। जब हम पढ़ते थे उस समय जियोग्राफी सब्जैक्ट में एक 'ओयसीज' ट्रम आती थी जिसको 'मरूउद्यान' कहते थे। (मरूउद्यान) जो होता था वह उद्यान के बीच में एक उपजाऊ पैच होता था। इसी तरह से हमारे दोनों जिले एंटी ओयसीज हैं। ये दोनों जिले एक संकुचित आईलैंड की तरह लगते हैं जहां विकास हर दृष्टि से वांछित है। वहां अभी बहुत काम होने बाकी हैं। उपाध्यक्ष महोदया, मैं अपने महेन्द्रगढ़ जिले की बात करता हूं कि यदि वहां की एक-एक चीज को देखा जाए तो वह इण्डस्ट्रियल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी जगह है। इस जिले को सबसे बड़ा लाभ कनैक्टिविटी का है। आज की तारीख में हमारे जिले की कनैक्टिविटी सबसे अच्छी है। हम एक्सटैंडिड एन.सी.आर. का हिस्सा हैं और दिल्ली से मात्र 110-120 कि.मी. की दूरी पर हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जिले से 3 नैशनल हाईवे निकलते हैं। हमारी सरकार आने के बाद तीन नैशनल हाई वे वहां डिक्लेयर हुए हैं। एक तो सतनाल-महेन्द्रगढ़-कनीना-रेवाड़ी रोड को भी अभी दस दिन पहले नैशनल हाई वे डिक्लेर किया है। मैंने इस बारे में अखबार में पढ़ा था। इससे पहले कोटपुतली-नारनौल-भिवानी वाला रोड भी नैशनल हाई-वे डिक्लेयर हो चुका है। इसी तरह से दिल्ली-नारनौल-सिंघाना-बिकानेर रोड भी नैशनल हाई-वे डिक्लेयर हो चुका है। इस तरह से तीन नैशनल हाई वे महेन्द्रगढ़ जिले के बीचों बीच जाते हैं और जो चौथा नैशनल हाई-वे नं० 8 है वे केवल 15-20 कि.मी. की दूरी पर है। इसी तरह से जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि रेलवे का जो डैडिकेटिड फ्रेट कोरीडोर दिल्ली-बाम्बे को जोड़ने वाला है, जो अभी निर्माणाधीन है, वह हमारे जिले के बीचों बीच निकलता है। इस तरह से कनैक्टिविटी के हिसाब से हरियाणा में इससे बैस्ट जगह बहुत कम हैं। दूसरी बात जहां तक लैंड की अवेलेबलिटी की बात है हमारा जो न्यू लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट आया है वह भी यह कहता है कि जहां तक हो सके उस लैंड को लिया जाये, जो कम उपजाऊ है। मैं यह तो नहीं कहता कि हमारी जमीन कम उपजाऊ है लेकिन दुर्भाग्यवश हम पानी के प्यासे हैं हमारी बहुत सी जमीन ऐसी है जो पानी के न मिलने के कारण बगैर जोते रह जाती है। जिसके कारण वहां के किसानों के पास आमदनी का कोई साधन नहीं है। मजदूरी करने के लिए भी वहां कोई इण्डस्ट्री नहीं है। इसलिए हमारे वहां जमीन भी सस्ती है और जमीन की उपलब्धता भी हमारे से ज्यादा दूसरी किसी जगह हरियाणा में नहीं है। इस तरह से हमारे जिले की जमीन इण्डस्ट्रिज के लिए उपयुक्त है। तीसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा जिसके बारे में वित्तमंत्री जी ने बजट में भी जिक्र किया है, जो प्रमुख चुनौतियों में से पहली चुनौती लिखी है, वह सिक्योरिटी के आसपैक्ट के बारे में है और दंगो के बारे में है। हमारे जिले के लोग तो गरीब और शांत से लोग हैं। वहां के लोगों ने दंगा-फसाद करना कभी सीखा नहीं है। हमारे जिले जैसा शांत

[डॉ० अभय सिंह यादव]

और सुरक्षित इलाका हरियाणा में कम ही मिलेगा। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि महेन्द्रगढ़ जिले को औद्योगीकरण के लिए अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखे। एक ट्रैंड है और आदमी का स्वभाव भी है, ब्यूरोक्रेट्स मेरे पुराने साथी हैं, इनका भी एक ट्रेंड है कि हमेशा सुरक्षित जगह पर काम करने की हर आदमी सोचता है। हमारा माइंड सैट यह बन गया कि जब भी भिवानी या महेन्द्रगढ़ का जिक्र आता है तो उसकी तरफ ध्यान देने की बजाय दूसरे जिलों की तरफ ध्यान चला जाता है। मैं यहां यही कहना चाहता हूं कि हमें अपनी माईंड की स्थिति को बदलने की जरूरत है। जब यह मनो-स्थिति बदलेगी तो उसके बाद बहुत बड़े साधन के रूप में हमारा जिला निकल कर आयेगा। इसमें मात्र एक काम करना है बाकी सभी चीजें वहां पहले से ही अवेलेबल हैं। इसमें सरकार का कोई लम्बा चौड़ा खर्चा नहीं होना है। माननीय उपाध्यक्ष महोदया जी, सिर्फ बात पानी की है और पानी के बारे में मैं यह बताना चाहूंगा कि हमें पानी के बारे में हमेशा यह कहकर चुप करवा दिया जाता है कि आपके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए पानी नहीं है। आप गुड़गांव का एरिया ले लीजिए। गुड़गांव व मानेसर का इण्डस्ट्रियल ज़ोन है वहां पर एन.सी.आर. चैनल के माध्यम से वैस्टर्न यमुना कैनाल का पानी जा रहा है। अभी सरकार नया बावल इण्डस्ट्रियल एरिया बनाने की बात कर रही है उसमें भी जे.एन.एल. कैनाल से पानी ले जाने का प्रस्ताव दिया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम भी उसी नहर के ऊपर स्थित हैं। हां, यह बात अलग है कि हम टेल पर हैं और लोग बीच में से पानी ले जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमारे इलाके में पानी की व्यवस्था ठीक प्रकार से कर दी जाये तो हमारा क्षेत्र हरियाणा प्रदेश के बहुत ही विकसित क्षेत्रों में से एक क्षेत्र हो सकता है। मैंने पहले भी यह कहा था कि अगर यूरोप वाले सारे के सारे यही सोच लेते कि सिर्फ यूरोप में ही इण्डस्ट्रियलाईजेशन करना है तो अमेरिका की खोज कभी भी न हो पाती। कोलम्बस ने अमेरिका की खोज की थी। इसलिए सिर्फ उन्हीं को ही याद किया जाता है किसी और को याद नहीं किया जाता। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार के रहनुमा कोलम्बस बन जायें। जो हमारा क्षेत्र है वह वर्जिन लैंड है इसके अंदर उपलब्ध सम्भावनाओं को तलाश किया जाये और इस क्षेत्र में विकास करवाया जाये। (विघ्न)

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : डिप्टी स्पीकर महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य डॉ. अभय सिंह यादव जी को यह बताना चाहूंगा कि उनके क्षेत्र की मुख्य नहर के पुनर्निर्माण के लिए हमारी सरकार ने सबसे पहली किस्त 143 करोड़ रुपये की जारी कर दी है ताकि इस क्षेत्र के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी उपलब्ध हो सके और पानी की एक भी बूंद बर्बाद न हो। सारे के सारे पम्पों को बदला जायेगा, सारी की सारी मोटरों को बदला जायेगा और पूरी की पूरी नहर को इस तरह का बनाया जायेगा जिससे वहां के सभी क्षेत्रों को अधिक से अधिक पानी पहुंचाया जा सके। मैं डॉ० अभय सिंह जी को यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि हम इनके इलाके नांगल चौधरी को अधिक से अधिक पानी दे चुके हैं। हम इस परियोजना का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी को साथ लेकर इनकी उपस्थिति में करके आ चुके हैं।

डॉ० अभय सिंह यादव : डिप्टी स्पीकर मैडम, हमारे इलाके में इण्डस्ट्रियल सैक्टर के लिए लॉजिस्टिक हब बनाया गया है जिसके लिए मैं माननीय उद्योग मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा। पानी की बात माननीय मंत्री श्री धनखड़ साहब ने शुरू कर दी है इसलिए मैं पानी की समस्या के बारे में बात करना चाहता हूं।

श्री राम बिलास शर्मा : डिप्टी स्पीकर मैडम, मैं डॉ० साहब को यह बताना चाहूंगा कि रिचार्जिंग के 390 करोड़ रुपये की लागत के प्राईम प्रोजैक्ट के माध्यम से माननीय मंत्री ओम प्रकाश जी धनखड़ इसी सत्र में उस प्यासी धरती को सिंचित करेंगे। अभी तक तो सिर्फ लॉजिस्टिक हब की ही बात हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी 09 अप्रैल, 2016 को महेन्द्रगढ़ जा रहे हैं उस समय वहां पर इस प्रकार की बहुत सी घोषणायें होंगी ऐसी हमें उम्मीद है। डॉ० अभय सिंह जी ने इस बारे में बहुत मेहनत की है। महेन्द्रगढ़ जिले में बहुत से ऐसे गांव हैं जो डार्क ज़ोन घोषित हो चुके हैं। जहां पर न बिजली है और न ही बिजली का कनैक्शन है। बिजली का कनैक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि डॉर्क ज़ोन घोषित होने के कारण कनैक्शन कटवा दिया गया है। वहां पर भूमिगत जल का लैवल हज़ार फुट से भी नीचे चला गया है। इसके लिए जो डॉ० अभय सिंह जी ने एक प्रोजैक्ट बनाकर दिया उसके ऊपर माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी द्वारा 09 अप्रैल, 2016 को एक विशेष घोषणा की जानी है ऐसी हमें उम्मीद है।

डॉ० अभय सिंह यादव : डिप्टी स्पीकर मैडम, माननीय मंत्री श्री राम बिलास जी ने इस बात का जिक्र कर दिया जिसके बारे में मैं बोलने ही जा रहा था। जैसा श्री राम बिलास शर्मा जी ने बताया अगर ऐसी बात है तो मैं उसके लिए माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। (विघ्न) मैं आदरणीय राम बिलास जी का भी धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने जिस बात को मैं कहने ही जा रहा था उसको मेरे कहने से पहले ही कह दिया। यह एक बहुत अच्छी बात है। माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश जी धनखड़ यहां पर बैठे हैं मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मैं तो यह सोच रहा था कि बजट पर बोलने के लिए मेरा नम्बर आने वाला है अगर यहां पर वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी और श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी में से कोई माननीय मंत्री यहां नहीं होगा तो मैं किसको अपनी बात सुनाऊंगा। (विघ्न) जहां तक पानी की समस्या का संबंध है यह हमारे इलाके की एक बहुत ही गम्भीर समस्या है। हमारी सरकार से पहले की किसी भी सरकार ने हमारी इस समस्या की तरफ कभी भी कोई ध्यान नहीं दिया। जो माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश जी धनखड़ ने हमारे क्षेत्र में लिफ्ट इरीगेशन के नवीनीकरण के लिए 143 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। जहां तक मुझे नॉलेज है तो अप्रैल, 2017 तक इस सिस्टम की सारी की सारी मोटरें बदल दी जायेंगी।

उपाध्यक्ष महोदया : डॉ० अभय सिंह जी, सरकार द्वारा उस क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं 13.00 बजे के लिए 390 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। जो बात श्री रामबिलास शर्मा जी ने बताई थी मैं उसको विस्तारपूर्वक बताना चाहता हूँ। यमुना नदी में बरसात के दिनों में पानी की उपलब्धता बहुत होती है हालाँकि लीन सीजन में कम पानी उपलब्ध होता है। हमारे इलाके में लिफ्ट इरीगेशन के माध्यम से पानी जाता है। **(इस समय श्री अध्यक्ष चेयर पर आसीन हुए)** अध्यक्ष महोदय, रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़ और भिवानी जिले की बाढड़ा, दादरी और लोहारू तहसीलों में लिफ्ट इरीगेशन से ही पानी पहुंचता है लेकिन पिछले 38 साल से लिफ्ट इरीगेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले पम्प नहीं बदले गये थे। इस बारे में मैंने आदरणीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया था और हम कई बार इनसे मिले भी थे तथा इन्होंने हमारी बात को मानते हुये इस काम के लिए ऐस्टीमेट मंजूर कर लिये हैं तथा उसके टैंडर भी हो रहे हैं। इस प्रकार से उसका एक फेज कम्पलीट हो जायेगा यानि पानी को लाने की व्यवस्था दुरूस्त हो जायेगी। उसके बाद बात आती है पानी की क्योंकि बाल्टी का बाल्टी होना ही काफी नहीं है बल्कि जब बाल्टी भर कर मिलेगी तब बात बनेगी। इसमें घर की बही और काका लिखणिया वाली बात नहीं है, नारनौल और दादरी में

[डॉ० अभय सिंह यादव]

ज्यादा फर्क नहीं है। इस बारे में मैं धनखड़ साहब से भी कई बार बात कर चुका हूँ कि बरसात के दिनों में यमुना नदी में पानी की बहुत ज्यादा मात्रा होती है उस समय अगर यमुना में से पानी उठा कर उस पानी से रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़ और भिवानी जिले के सूखे जोहड़ों को भर दिया जाये तो सूखे के समय उस पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। महेन्द्रगढ़ और रेवाड़ी में तो उस पानी को खपाने के लिए दो साधन-कृष्णावती और दोहान नदियों के बैड बिल्कुल सूखे पड़े हैं। उनमें कुछ रिचार्जिंग बोर लगे हुये हैं तथा कुछ और लगा कर उस पानी को वहाँ पर डाला जा सकता है। इसी प्रकार से रेवाड़ी के पास साहिबी नदी का बैड खाली पड़ा हुआ है तथा नहर की कनैक्टिविटी के लिए भी सरकार को बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सौभाग्य से इन नदियों के बहुत नजदीक से नहर गुजरती है और उनकी कनैक्टिविटी बहुत आसान है। अपने विधान सभा क्षेत्र की तरफ से भी और व्यक्तिगत तौर पर भी धनखड़ साहब से मेरी प्रार्थना है कि उस रूखे-सूखे इलाके पर दया कर दो, आप भागीरथ बन जाओगे। अब तक तो यही हो रहा है कि जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र में एक बूंद के लिए आदमी तरसता है उसी प्रकार हम भी बूंद-बूंद के लिए तरसते हैं।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदया, डॉ. अभय सिंह यादव बहुत प्रयास करते रहते हैं और जिस प्रकार से रामबिलास जी ने कहा कि हम पहले ही उस इलाके में टेल्स पर इन्जैक्शन बोर बना रहे हैं। हमारे पास जिस दिन भी पानी फालतू होगा वह चाहे बरसात का सीजन हो चाहे बिना बरसात का सीजन हो हम इन्जैक्शन बोर में पानी भरेंगे। मान लीजिए बिना बरसात के सीजन में बरसात आ गई और हमें नहरी पानी की सिंचाई के लिए आवश्यकता नहीं है और हमारे पास पानी उपलब्ध है तो वह पानी हम उन इन्जैक्शन बोर में भरेंगे। पहले हम पशुओं के पीने के लिए 2800 जोहड़ भरते थे लेकिन अब उसी स्कीम के तहत हमने 1450 जोहड़ और छांटे हैं और वे ज्यादातर सूखे इलाके के हैं। उन जोहड़ों तक पानी पहुंचाने के लिए 65 करोड़ रुपये खर्च करके पानी ले जाने का रास्ता बनाया जा रहा है। जिस दिन भी हमें अतिरिक्त पानी मिलेगा उस दिन हम उन जोहड़ों को भर लेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरी तीसरी बात यह है जिसके लिये हमारे नेता प्रतिपक्ष और बहुत सारे विधायकों ने यह सिफारिश की थी कि जो वेस्ट यमुना कैनाल से लेकर जहां तक सारे रास्ते में हमारा पानी बेकार जाता है जो लगभग 30 प्रतिशत पानी बेकार चला जाता है उसको किस तरह से बचा कर और इस पूरे सिस्टम का पुनर्निर्माण करके नांगल चौधरी के व महेन्द्रगढ़ क्षेत्र के सारे प्यासे खेतों में पहुंचाया जाए ये सरकार की बहुत अधिक प्रॉयरिटी है। मैं सुबह एक अच्छी घोषणा करना चाहता था लेकिन बहन नैना चौटाला जी का सवाल ही नहीं आया। मैं बताना चाहता हूं कि नैना जी के क्षेत्र में नहर टूट गई थी जिससे लगभग 81 एकड़ जमीन पानी से भर गई थी। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं एक ऐतिहासिक बात कर रहा हूँ कि पहले जब नहर टूटती थी तो नहर विभाग किसानों से पानी के पैसे लेता था कि तुम्हारे खेत में सिंचाई हुई है इसलिए आप विभाग को उस पानी का टैक्स जमा कीजिए लेकिन पहली बार नहर विभाग ने नहरों के टूटने से जो नुकसान हुआ है उसके लिए साढ़े बाईस लाख 65 हजार रुपये का प्रावधान किया है जिसमें से वहां जो ट्यूबवैल खराब हुए, फसल खराब हुई और जो ढ़ाणी में पानी दिया गया है, उसका मुआवजा दिया जाएगा और यह व्यवस्था नहरी विभाग ने परमानैन्ट बनाई है। अगर कहीं भी नहर टूटने से खेतों को नुकसान होगा उसके लिए हमने 5 करोड़ रुपये का अलग से बजट में प्रोविजन किया है कि जहां भी हमारी नहरों से किसानों को नुकसान होगा हम उसकी भरपाई करेंगे। यह इस सदन में हरियाणा बनने के बाद पहली बार हो रहा जिसको हमने लागू किया है।

डॉ. अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने किसानों को पानी देने के लिए आश्वासन दिया है और नहरों के टूटने से जमींदारों को कंपनसेट किया है। जहां तक धनखड़ साहब मुआवजे की बात कह रहे थे उस पर मुझे एक बात याद आ गई। मैं कहता हूं कि हर किसान को मुआवजा मिलना चाहिए चाहे वह कहीं का भी किसान हो, नुकसान जहां भी हुआ है उन सब किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। इसमें सरकार की बहुत अच्छी सोच है लेकिन अभी पीछे जो कपास और सफेद मक्खी का मुआवजा दिया गया है मैं उसकी एक घटना सुनाता हूं। एक दिन मेरे पास गांव का एक जमींदार मिलने के लिए आ गया और वह मुझे कहने लगा कि तुम्हारी सरकार ने क्या कोई ऐसे औजार भी बना लिये जिससे तुम मक्खियों के पंख बांध सको। मैंने कहा क्यों क्या बात हुई ? उसने कहा कि भिवानी जिला तीन तरफ से महेन्द्रगढ़ जिले को टच करता है और महेन्द्रगढ़ जिले में हजारों एकड़ कपास बोई जाती है। सरकार ने पांच जिलों को कम्पनसेशन देने की घोषणा तो कर दी है और हमारे महेन्द्रगढ़ जिले के किसी अकेले एक गांव में भी कम्पनसेशन देने की घोषणा नहीं की। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भिवानी जिले में तो सफेद मक्खी ने नुकसान कर दिया और महेन्द्रगढ़ जिले में आते-आते उस सफेद मक्खी के पंख बांध दिये गये हों जिससे वह महेन्द्रगढ़ जिले में नुकसान कर ही नहीं सकती। सर, बड़ा अजीब सा लगता है नुकसान हुआ है और सभी जिलों में हुआ है लेकिन मुझे नहीं पता कि किस लैवल पर कहां क्या हुआ है लेकिन ऑफिसर्ज ने वहां की रिपोर्ट नहीं दी तो क्यों नहीं दी ? सफेद मक्खी से जो नुकसान हुआ है वह पूरे जिले में हुआ है और उस नुकसान की भरपाई होनी चाहिए थी लेकिन उसमें महेन्द्रगढ़ जिले का उल्लेख नहीं किया गया तो इसके लिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस क्षेत्र को भी देखें। दूसरी जहां तक पानी की बात है सिंचाई मंत्री जी यहां बैठे हैं यह उनके संज्ञान में है कि हमारी जो पिछली खरीफ की फसल थी उसमें मेरे हल्के में सूखा पड़ा था और वहां नहर का पानी नहीं जा पाया इसमें मैं अपने नांगल चौधरी हल्के की बात कह रहा हूं। हमारे वहां उस समय बाजरा सिरटा की स्टेज पर आया हुआ था जो खड़ा-खड़ा सफेद हो गया। मैंने मंत्री जी से कहा था हमारे क्षेत्र में सूखा पड़ा है आप उसका सर्वे करवा कर उसका किसानों को मुआवजा दिलवा दीजिए लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसी तरह से रबी की क्रौप में दो बार नहर फेल हुई है जिसके कारण वहां पर दो बार लगातार पानी नहीं गया जिसको मैंने मंत्री जी के संज्ञान में लाया था और समय-समय पर इनके ऑफिसर्ज के नोटिस में भी लाता रहा हूं। अब हालत यह है कि नांगल चौधरी के लगभग 20 गांव ऐसे हैं जिनमें गेहूं बाल की स्टेज पर आया हुआ था वह खड़ा-खड़ा सूख गया। यह ठीक है कि जो पिछली तीसरी फसल थी उस समय हमारी सरकार के आने के बाद धनखड़ साहब ने हमारे इलाके को बहुत पानी दिया था जिसके लिए हमने इनका बहुत धन्यवाद किया है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है लेकिन इस बार वहां पानी का जितना बुरा हाल हुआ है मेरे ख्याल से इतना बुरा हाल पिछले कई सालों में भी नहीं हुआ जितना इस साल हुआ है जिससे वहां के किसानों की फसल सूख गई। मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वह हमारे इलाके का सर्वे करवा लें और सूखे के कारण वहां के किसानों की जितनी मदद हो सकती है वह कर दें क्योंकि दो फसलों की तबाही किसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वैसे ही उस क्षेत्र में तो लिमिटेड-सी खेती होती है क्योंकि वहां पानी नहीं है तो मेरा निवेदन है कि इस विषय में सरकार कुछ संवेदनशीलता दिखाए। इसके साथ मैं तीसरी और अंतिम बात कहना चाहूंगा क्योंकि पावर का महकमा माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है सरकार ने एक लैटर जारी किया हुआ है कि दो एकड़ से कम वाले जमींदार को ट्यूबवैल का कनैक्शन नहीं दिया जा

[डॉ. अभय सिंह यादव]

सकता। उस लैटर का आशय जहां तक मैं समझ पाया हूं वह यह हो सकता है कि छोटी होल्डिंग पर ट्यूबवैल का कनैक्शन देने पर उसका मिसयूज हो सकता है लेकिन दो एकड़ का मतलब है कि एक होल्डिंग दो एकड़ की होनी चाहिए। लेकिन विभाग के ऑफिसर्ज ने उसकी क्या इन्टरप्रिटेशन कर रखी है कि अगर मान लो तीन भाई इकठ्टे खेती कर रहे हैं। और तीनों के पास पांच एकड़ जमीन है और सांझी खेती कर रहे हैं तो अधिकारी कहते हैं तीनों के हिस्से में दो-दो एकड़ जमीन आनी चाहिए। यह पूर्णतया गलत है। मैंने इस संबंध में बिजली बोर्ड के अतिरिक्त मुख्य सचिव जी से भी इस बारे में बात की थी। वह भी मेरी बात से सहमत थे और मैंने इस संबंध में उनको एक चिट्ठी भी दी थी। उन्होंने मुझे लिखकर देने के लिए कहा था और मैंने बाकायदा उनको लिखकर दिया था लेकिन अभी तक कोई फैसला सरकार के स्तर पर नहीं लिया गया है। मैं समझता हूँ कि जमींदारों को बिना किसी बात के परेशान नहीं किया जाना चाहिए। यह ठीक है कि ट्यूबवैल का कनैक्शन दो एकड़ से कम की होल्डिंग पर नहीं दिया जायेगा लेकिन यदि लैंड होल्डिंग मान लो 20 एकड़ की है और छह भाई हैं तो 20 एकड़ पर ट्यूबवैल का कनैक्शन तो दिया ही जायेगा। इस तरह से मैं समझता हूँ कि जमींदारों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। यही मेरा निवेदन है। बहुत-बहुत मेहरबानी।

श्री विपुल गोयल (फरीदाबाद): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ। माननीय मनोहर लाल जी की सरकार का यह जो मनोहारी तथा "सबका साथ-सबका विकास" वाला बजट है। इस बजट में गरीब, किसान, मजदूर, उद्योग, नारी सम्मान तथा युवाओं आदि सभी दृष्टिकोणों को ध्यान में रखकर यह बजट तैयार किया गया है। इस बजट की मैं बहुत-बहुत प्रशंसा करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, किसान और गरीब आदमी कभी भी कोई चीज मुफ्त में नहीं मांगना चाहता है। यह लोग भी सम्मान के साथ जीना चाहते हैं। सम्मान से जीने के लिए उसे रोजगार के अवसर चाहिए होते हैं। किसान और गरीब को जब रोजगार का अवसर मिलता है तो वह पूरी मेहनत से मिट्टी को भी सोना बनाने का काम करता है। इस बजट में उस गरीब और किसान के सम्मान को कायम रखने के लिए जो अवसर प्रदान करने का काम किया गया है, वह बहुत ही सराहनीय है। आज देश और प्रदेश जिस वित्तीय हालत के दौर से गुजर रहा है उसके अन्दर इतना अच्छा बजट देना कोई आसान बात नहीं है। वर्ष 2016-2017 के इस बजट को 28.4 प्रतिशत बढ़ाकर 88782 करोड़ रुपये किया गया है वह भी एक बहुत बड़ी बात है। आज प्रदेश की जिस प्रकार वित्तीय हालत बनी है उन हालातों में भी 3 प्रतिशत का डेफिसिट कंट्रोल करके जो बजट पेश किया गया है वह भी बहुत सराहनीय कदम है। अध्यक्ष महोदय, मैं अब बजट के कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सदन का ध्यान दिलाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं कृषि को लेता हूँ। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। हरियाणा प्रदेश हरित क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने वाला प्रदेश है। कृषि के अन्दर भी चाहे वह बागबानी हो या और कोई चीजें हों सबको बढ़ाकर 13494 करोड़ रुपये का जो बजट पेश किया गया है वह भी बहुत सराहनीय कदम है। बजट में डिमांड जनरेशन का पूरा ध्यान रखा गया है। जब रोजगार के अवसर पैदा होंगे तो हमारे किसान तथा मजदूर मजबूत होंगे। किसानों का विकास होगा तथा गांवों का विकास होगा और उनकी खर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी। जब खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी तो निश्चित तौर से डिमांड जनरेशन की नीति पर चलते हुए अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इस बजट में जो डिमांड जनरेशन का काम किया गया है वह भी एक सराहनीय कार्य है।

आज से पहले कोई भी सरकार रही, उसने कभी भी इस तरीके का काम करने की सोच कभी नहीं रखी। उन्होंने किसानों और नौजवानों को बरगलाने का कार्य किया और ऐसा काम किया कि यह वर्ग कभी तरक्की ही न कर सके सिर्फ राजनीतिक तौर पर उनका पिछलग्गू बनकर रहे। इस तरीके से यह बजट लाकर जो संदेश देने का हमारी सरकार ने काम किया है यह बहुत ही सराहनीय है। इसके अलावा कोई भी नया टैक्स न लगाकर Icing on the Cake का जो काम किया है वह भी बहुत सराहनीय है। इसके अलावा 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान के तहत बेटियों को पढ़ाने का जो बजट में प्रावधान किया गया है और इसको 23 प्रतिशत बढ़ाकर 1207 करोड़ रुपये करने का जो काम किया गया है वह भी प्रशंसनीय है। अभी कई वक्ताओं ने जैंडर रेशो पर बात की थी और कहा था कि और प्रदेशों की तुलना में हरियाणा में जैंडर रेशो बहुत ज्यादा खराब हुआ है लेकिन हमारी सरकार के कार्यकाल में इस रेशों में वृद्धि देखने को मिली है। हमारी सरकार ने इस जैंडर रेशो को 9 प्रतिशत से ज्यादा के आंकड़े पर लाकर खड़ा कर दिया है। यह भी एक सराहनीय कदम है। अध्यक्ष महोदय, यह जो वर्ष 2016-2017 का बजट है इसमें हर क्षेत्र को चाहे किसान के विकास की बात हो, चाहे उद्योगों के विकास की बात हो, चाहे सड़कों को बनाने की बात हो और चाहे सिंचाई की सुविधा की बात हो पूरे बजट में 4 प्रतिशत से लेकर 28 प्रतिशत तक की वृद्धि करके जो बजट बनाया गया है, वाकई में यह बहुत ही सराहनीय काम है। हरियाणा ने विषम परिस्थितियों में भी 'हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मिट' का सफल आयोजन करके 5 लाख 84 हजार करोड़ रुपये के निवेश के साथ 359 एम.ओ.यू. साईन किए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रतिपक्ष के नेता से यह जरूर पूछना चाहूँगा कि उन्होंने बजट के बारे में बहुत कुछ बोला है, पर बजट में जिन अच्छी-अच्छी बातों का जिक्र हुआ है, उनके बारे में भी उल्लेख जरूर करना चाहिए। हरियाणा सरकार ने विषम परिस्थिति में भी 'हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मिट' आयोजन के माध्यम से इतना बड़ा निवेश ला कर दिखा दिया है जिससे देश और विदेश को हरियाणा की जनता पर पूर्ण विश्वास हो गया है और हरियाणा सरकार को एक प्रगतिशील सरकार समझती है। बाहर की कम्पनियां निवेश के लिए हरियाणा को बहुत अच्छा स्थान समझती है, इसलिए इतना बड़ा निवेश इस आयोजन में सफल हुआ है। ऐसी विषम परिस्थितियों में कुछ लोगों ने प्रदेश में भाईचारे को बिगाड़ने का काम किया, प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया और यहां तक कि ऐसी घिनौनी और ओछी राजनीति करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पाकिस्तानी और शरणार्थी कहने तक का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में एक बात कहना चाहता हूँ कि ये लोग पाकिस्तानी नहीं ये तो अखंड भारत में रहने वाले लोग थे, जो अखंड भारत में रहते थे। देश के विभाजन के बाद छोटी मानसिकता की राजनीति ने उस स्थान को पाकिस्तान के रूप में बांट दिया था और उस स्थान पर रहने वाले लोगों को पाकिस्तानी नाम दिया गया था। इन लोगों ने उस स्थान पर रहना मंजूर नहीं किया और ना ही अपना धर्म परिवर्तन किया। अध्यक्ष महोदय, हम हर रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि छोटे-छोटे लालचों में पड़ कर लोग अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। इन्होंने ऐसा घिनौना काम भी नहीं किया। इन्होंने तो यह काम किया कि अपना घर-बार, खेत-खलिहान, उद्योग धंधे व पशुधन को छोड़कर केवल दो कपड़ों में हिन्दुस्तान की जमीन पर आ गये। इसलिए इन्हें पाकिस्तानी ना कह कर पुरूषार्थी कहना चाहिए। (इस समय मेजें थपथपाई गई।) माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी सिर्फ दो कपड़ों में आए थे और आज पुरुषार्थ की वजह से हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों को इन्हें सलाम करना चाहिए। लाखों

[श्री विपुल गोयल]

परिवार पाकिस्तान से आए थे, जिनमें माननीय श्री लाल कृष्ण अडवाणी जी भी थे जो अपने पुरूषार्थ से देश के बड़े नेता के रूप में उभरे हैं, श्री आई.के.गुजराल जी पुरुषार्थ के कारण देश के प्रधानमंत्री बने थे। फिल्म जगत में श्री राजकपूर व श्री सुनील दत्त अपने पुरुषार्थ से देश की महान हस्ती बने और हमारी विधान सभा के सत्ता और विपक्ष के कई माननीय सदस्य पुरूषार्थ की वजह से विधायक बने हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप एक प्रस्ताव लेकर आए और इसकी निंदा की जाये। जिन लोगों ने ऐसी घिनौनी बात कही है उन लोगों के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि इस तरह की अनर्गल बातें करके प्रदेश के भाईचारे को बिगाड़ने का काम किया है। इन लोगों ने अपने लिए ना तो रिजर्वेशन की मांग की है और ना ही कोई आर्थिक मदद की मांग की है, सिर्फ अपने बलबूते पर देश और प्रदेश को तरक्की की राह पर लेकर गए हैं। इस तरीके की बातें करने वाले लोगों को पाकिस्तानी और शरणार्थी ना कहकर केवल पुरुषार्थी कहना चाहिए।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बारे में कहा है कि एक व्यक्ति ने उनके बारे में पाकिस्तानी कहा है। जिस वक्त यह बात अखबार में आई थी उस वक्त हमारे पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ने इस बात का खंडन किया था। ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और ऐसे लोगों पर नकेल भी डालनी चाहिए। जब सदन में मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे तब उनकी आंखे नम हो गई थी तो मैंने खड़े होकर उनकी बात का समर्थन किया था और कहा था कि मैं इस बात की बहुत ही निंदा करता हूं। बहुत-से सदस्य ऐसे हैं जो पाकिस्तान से आकर यहां बसे हुए हैं। हमारे पुरखे, श्री अनिल विज और मिड्ढा साहब के पूर्वज पाकिस्तान से आकर यहां बसे थे। जब हम वहां से आए तो हम अपना व्यापार, धंधा, दुकानें, खेत, घर इत्यादि छोड़कर आए थे परंतु हमने अपने मान-सम्मान को रखने के लिए भारत को न छोड़ने का प्रण लिया था। आज सदन में आरक्षण का बिल आ गया है। मैं इस विषय पर कोई बात नहीं करना चाहता। ऐसे लोग जो किसी विधायक विशेष के बारे में भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं हमें उन पर नकेल कसने की जरूरत है। ऐसे लोगों की पूरे सदन को भर्त्सना करनी चाहिए। (विघ्न) मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक शेर सुनाना चाहता हूं -

"बदन में जितना भी खून है ईमान वाला है,
पर फिर भी कम्बख्त समझता है कि पाकिस्तान वाला है,
हम हिंदुस्तानी हैं,
हिंदुस्तान के लिए जीएंगे मरेंगे।"

हम इस बात के पक्षधर हैं। ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो अखण्ड भारत को नुकसान पहुंचाता है उसे जेल में बंद करना चाहिए।

श्री विपुल गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात का समर्थन करने के लिए माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि 19 मार्च को दिल्ली के हरियाणा भवन में मेरी और बाल्याण साहब की उपस्थिति में सभी जाट खापों के नेता मुख्यमंत्री से मिलने गये थे। उसी दिन सभी खापों के प्रतिनिधियों ने

सर्वसम्मिति से मुख्यमंत्री जी के सामने इस बात का दु:ख जताया और उस मीटिंग में एक आदमी की गलती को महसूस करते हुए उस पर सम्पूर्ण समाज ने खेद जताया था। उन्होंने कहा कि हम सर्वसम्मति से किसी व्यक्ति द्वारा मुख्यमंत्री जी को कही गई गलत बात की भर्त्सना करते हैं।

श्री विपुल गोयल : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की कुछ समय पहले स्थिति खराब हो गई थी। उसके बाद सरकार ने धैर्य रखते हुए बगैर जोर-जबरदस्ती के जिस तरीके से प्रदेश के माहौल को ठीक किया और हमारे बजट में मुआवजे का प्रावधान करके पीड़ितों को राहत दी है वह तारीफ के काबिल है। सरकार ने आंदोलन के दौरान हुए नुकसान का व्यापारियों को मुआवजा देने और उनके टैक्स माफ करने का इस बजट में प्रावधान किया इसके लिए मैं माननीय मुख्यंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इसके लिए मैं चार पंक्तियां कहना चाहूंगा -

"तुम्हें है शौक अगर बिजलियां गिराने का, हमारा काम भी है आशियां बनाना,
सुना है आप माहिर हवा चलाने में हैं, मगर हमें भी हुनर है दिया जलाने का।"

इस तरह का काम हमारी सरकार ने किया है और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इस बजट में हैल्थ, बिजली, सिंचाई और शिक्षा इत्यादि क्षेत्रों में सभी मूलभूत सुविधाओं को तवज्जो दी गई है। मैं मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी का हर क्षेत्र में बजट में बढ़ौत्तरी करने के लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही मैं फरीदाबाद की समस्याओं से वित्त मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद एक इंडस्ट्रियल सिटी है और यह एशिया का एक जाना-माना शहर है और फरीदाबाद को "भारत का मानचेस्टर" भी कहा जाता है। पिछली सरकारों ने पिछले 10-15 वर्षों में फरीदाबाद को नैगलैक्ट करके पिछड़े हुये शहर में तब्दील कर दिया है। आज फरीदाबाद को लोग एन.सी.आर. का दूसरे, तीसरे या चौथे नम्बर का शहर कहते हैं। फरीदाबाद के ज्योग्राफिकल स्टेटस में कोई कमी नहीं है और न ही फरीदाबाद के लोगों में कोई कमी है। फरीदाबाद दिल्ली के नजदीक है और इसकी चारों तरफ से एक्सैसिबिलिटी में भी कमी नहीं है। वहां के उद्योगों में भी कोई कमी नहीं है लेकिन फरीदाबाद के विकास के प्रति सरकारी मानसिकता और क्षेत्रवाद में भेदभाव अवश्य है। सरकारी ध्यान न देने की वजह से फरीदाबाद नगर निगम की वित्तीय हालत पिछले 10-15 वर्षों से बहुत खराब हो चुकी है। अभी पिछले डेढ़ वर्ष से माननीय मुख्यमंत्री जी की अच्छी सोच की वजह से किसी तरह से नगर निगम को चलाया जा रहा है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि फरीदाबाद में न तो पब्लिक हैल्थ के पास ग्रांट आती है, न पी.डब्ल्यू.डी. के पास ग्रांट आती है और न ही मार्केट कमेटी के पास ग्रांट आती है। फरीदाबाद की डिवैल्पमैंट करने की सारी जिम्मेदारी एम.सी.एफ. पर है जिसकी अपनी वित्तीय हालत ठीक नहीं है। इसके अंतर्गत 6 विधान सभा क्षेत्र आते हैं और वह फरीदाबाद की रीड़ की हड्डी है लेकिन उसकी माली हालत आज खराब है। मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि बजट के अंदर फरीदाबाद के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपये का स्पैशल प्रावधान करके फरीदाबाद को नए शहर का रूप देने के लिए और विकसित शहर कहलाने के लिए हमारी तरफ ध्यान दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद जो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी था लेकिन पिछले 15-20 सालों से कोई नया उद्योग यहां नहीं आया। सरकारी मानसिकता और सरकार की नीतियों की वजह से किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने फरीदाबाद में निवेश नहीं किया था। उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत जमीन की भी है। वहां पर जितने भी एच.एस.आई.आई.डी.सी. के प्लॉट थे या कोई और प्लॉट थे, वे पूर्व की सरकारों द्वारा अपने चेहेतों को अलॉट किए गए थे। इस बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि पूर्व की सरकारों

[श्री विपुल गोयल]

पर इसके लिए मुकदमें दर्ज हो गए हैं। उन्होनें इन जमीनों को इंडस्ट्रियलिस्टस को अलॉट न करके अपने भाई भतीजों को प्रीमियम खाने के लिए अलॉट किया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से गुहार करना चाहता हूं कि कोई अच्छी जगह उपलब्ध कराकर या बहुत से विभागों की अलग अलग जो जमीनें वहां पड़ी हैं उन जमीनों को इंडस्ट्रियल जमीन में कंवर्ट करवाकर या सब्सिडाइज्ड रेट पर जमीन उपलब्ध करवाकर फरीदाबाद में मदर यूनिट देने की कृपा करें ताकि फरीदाबाद वापिस अपनी प्रगति की ओर तथा इंडस्ट्रियल टाउन की ओर चल सके। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय का ध्यान फरीदाबाद के 'मेहंदी उद्योग' की तरफ दिलाना चाहता हूं। फरीदाबाद 'मेंहदी उद्योग' के नाम से जाना जाता है। फरीदाबाद का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी शुरूआत मेंहदी उद्योग से हुई है। लेकिन 2005 की पूर्व की सरकार ने मेंहदी पर टैक्स लगा दिया था। मेंहदी पर न राजस्थान सरकार ने टैक्स लगाया, न दिल्ली सरकार ने लगाया और न मध्य प्रदेश सरकार ने लगाया और न ही छत्तीसगढ़ सरकार ने लगाया है। अध्यक्ष महोदय, मेहंदी हमारी बहनें तीज त्यौहारों पर रचाती हैं। फरीदाबाद मेंहदी उद्योग के नाम से जाना जाता है परंतु पूर्व की सरकार ने उस पर भी टैक्स लगाने का काम किया जिसकी वजह से मेंहदी उद्योग ने फरीदाबाद से प्लायन करने का काम किया था। अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेंहदी पर लगाए गए टैक्स को हटाया जाए। इस मेंहदी के उद्योग में हमारे 10-15 हजार मजदूर या इंडिस्ट्रियल लोग काम करते थे। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जो इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर राजस्थान या दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है उसकी तरफ ध्यान देकर इस मेंहदी उद्योग को बचाने का काम किया जाए। 15 हजार मजदूरों को बसाने का काम करके मेंहदी पर लगाए गए टैक्स को हटाकर इसको जीवन दान देने का काम किया जाए। स्लम डिवैल्पमैंट की बात बजट में कही गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंततोगत्वा का सिद्धांत दिया था कि जो समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति है उसका पुनरूत्थान किया जाएगा उसको ऊपर उठाएंगे तभी समाज के अंदर सम्पन्नता आएगी और तभी समाज तरक्की कर पाएगा। मेरे फरीदाबाद विधान सभा क्षेत्र में नई कालोनियों का सर्वे हुआ उसके बावजूद भी वहां 4 स्लम ऐसे हैं जिनमें पुनर्त्थान या रैगुलेराइजेशन का काम नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उनके पुनर्वास की कोई योजना लाई जाए। उस स्लम का भी पुनर्वास किया जाएगा तभी फरीदाबाद तरक्की की ओर जा सकेगा तथा अंततोगत्वा का सपना पूरा हो सकेगा। आखिर में मैं मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को और पूरी टीम को इस बजट के लिए शुभ कामनाएं देता हूं और एक श्लोक के माध्यम से मैं अपनी बात खत्म करूंगा-

किसानों की खुशी की हो गई अब खूब तैयारी,
बढ़ेंगे उद्योग धन्धे और मिटेगी अब तो बेकारी,
विस्मय स्थिति है लेकिन जीत हमारी निश्चित है,
कैप्टन अभिमन्यु ने खेली है यह कप्तानी।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, हमारे विपुल गोयल जी ने बहुत अच्छे ढंग से बजट के समर्थन में एक बात कही है और उन्होंने एक श्लोक बोला है-

यह माना कि अंधेरा घना है, पर दिया जलाना कहां मना है।

श्रीमती बिमला चौधरी (पटौदी) (अनुसूचित जाति) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूं और वित्तमंत्री जी को बधाई देती हूं कि उन्होंने बहुत ही सराहनीय बजट पेश किया है जिससे सभी वर्गों को लाभ मिलेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और वित्तमंत्री जी का धन्यवाद करती हूं कि गुड़गांव से पटौदी होते हुए रिवाड़ी का फोर-लेनिंग का रोड़ मंजूर किया है। इसी के साथ-साथ यह भी कहना चाहूंगी कि करीबन एक साल पहले मुख्यमंत्री जी पटौदी के बाईपास की घोषणा करके आए थे। इस बारे में मैं जानकारी चाहती हूं कि उसको फोर लेनिंग के साथ जोड़ दिया गया है या वह अलग से बनाया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगी कि कल आपने मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया था मेरी छोटी सी बात थी उसको आज मैं कहना चाहूंगी कि पिछले साल जो मुआवजा दिया गया था उसमें से 26 करोड़ रुपये बचे हुए हैं। किसानों को जो चैक मिले वे बाउंस हो गये हैं। यह अमाऊंट जल्द से जल्द किसानों को दी जाये ताकि वे अपना गुजर-बसर कर सकें। इसी के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगी कि आंदोलन को लेकर यहां काफी चर्चा हुई है। आंदोलन के कारण प्रदेश का जो नुकसान हुआ यह बहुत ही दुख:द बात है। आंदोलन की आड़ में कुछ मूर्तियां भी तोड़ी गई जो हमारे शहीदों की थी। मूर्तियों ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था और मूर्तियां 36 बिरादरी की होती हैं। मैंने सुना था कि सर छोटूराम की मूर्ति तोड़ी गई जिसको रातों रात बनवा दिया गया। चौधरी देवी लाल की मूर्ति को हाथ नहीं लगाने दिया गया। कई शहीदों की मूर्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। शहीद राव तुलाराम की मूर्ति को भी तोड़ा गया। मैं सरकार से अपील करती हूं कि शहीद राव तुलाराम की मूर्ति को नये सिरे से बनवाकर लगाया जाये। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं दोबारा से आपका धन्यवाद करती हूं।

श्री जसबीर देसवाल (सफीदों) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। हमारे वित्त मंत्री जी ने बड़ी ही सूझबूझ और विवेक से बढ़िया और अच्छा बजट पेश किया है। इस बजट से हर वर्ग यानि व्यापारी, किसान, मजदूर, कर्मचारी सभी को फायदा होगा। जहां तक मैं कृषि से संबंधित क्षेत्र का जिक्र करूं इसके लिए 2015 में 11444.41 करोड़ रुपये रखे गये थे उसमें बढ़ोत्तरी करके इस साल 13494 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। इसी तरह से केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 736.66 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 984.51 करोड़ रुपये बजट का प्रोविजन 2016-17 के लिए किया है। बागवानी के क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत वर्ष 2015-16 के लिए 239.45 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2016-17 के लिए 378.44 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। ऐसे ही करनाल में बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के लिए भी सहायता अनुदान की राशि को वर्ष 2015-16 के 336.95 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2016-17 के लिए 368 करोड़ रुपये किया गया है। ये सभी बहुत ही अच्छी बातें हैं। स्पीकर सर, माननीय वित्त मंत्री जी ने इस प्रदेश के विकास के लिए एक बहुत ही अच्छा बजट यहां पर प्रस्तुत किया है। जो किसानों की रबी की फसल वर्ष 2015 में प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हो गई थी उनके मुआवज़े के लिए सरकार द्वारा 1092 करोड़ रुपये की राशि का वितरण किया गया। इसी प्रकार से सफेद मक्खी के प्रकोप से जो कपास की फसल खराब हो गई थी उन कपास उत्पादक किसानों के नुक्सान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा 2327.93 करोड़ रुपये की राशि मुआवज़े के तौर पर वितरित की गई है। सरकार द्वारा किसानों की उत्पादन लागत को कम करने के लिए और कृषि सम्बंधी गतिविधियों

[श्री जसबीर देसवाल]

को आर्थिक रूप से लाभप्रद बनाने के लिए सस्ती दरों पर बिजली आपूर्ति करने के लिए वर्ष 2015-16 के लिए 6425.90 करोड़ रुपये की राशि सब्सिडी के रूप में उपलब्ध करवाई गई है। वर्ष 2016-17 के लिए इस मद में 6800 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। प्रदेश की शूगर मिलों को वर्ष 2015-16 में जो घाटा हुआ था उसकी पूर्ति के लिए सरकार द्वारा बजट में 187 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। गन्ना उत्पादक किसानों की बेहतरी के लिए सहकारी चीनी मिलों को किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए 400 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से इसी मद के लिए प्राईवेट शुगर मिल्ज़ को 50 करोड़ रुपये की सहायता का आबंटन किया गया है। इसके साथ-साथ मैं अपने जींद जिले की समस्याओं के लिए भी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा। हमारे जींद जिले का राजनीतिक तौर पर सभी पार्टियों ने इस्तेमाल किया लेकिन विकास के तौर पर इसको सबसे पीछे छोड़ दिया। जींद जिला सबसे पुराना जिला है लेकिन आज तक भी जींद शहर के अंदर बाई-पास का भी निर्माण नहीं हो पाया है। हमारे हरियाणा प्रदेश में ही बहुत से शहर ऐसे हैं जिनमें एक नहीं बल्कि दो-दो बाई-पास बने हुए हैं लेकिन जींद शहर के अंदर अभी तक एक भी बाई-पास नहीं बन पाया है। बाई-पास के अभाव में सारी की सारी ट्रैफिक जींद शहर के अंदर से होकर गुजरती है। जींद छोटा सा शहर है लेकिन हमें जींद शहर को पार करने में एक-एक घंटा लग जाता है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार से यह निवेदन है कि जींद शहर में बाई-पास ज़रूर बनाया जाये। (विघ्न) औद्योगिक दृष्टि से भी जींद को पिछड़ा रखा गया है। जींद में सिर्फ एक आर.ओ.बी. बना है। जींद शहर में कोई इण्डस्ट्रियल सैक्टर नहीं है। मैं इस सरकार का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो उसने जींद और पानीपत की सड़क को फोर लेन बना दिया है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सरकार का बार-बार हार्दिक धन्यवाद करता हूं। अब मैं यहां पर सफीदों की बात करना चाहूंगा। सफीदों भी जींद जिले का ही हिस्सा है। जींद जिले में पांच विधान सभा क्षेत्र हैं और पांचों विधान सभा क्षेत्रों में विकास के मामले में बराबर-बराबर ही पिछड़ापन है। हमारा एक भी क्षेत्र विकास के मामले में आगे नहीं गया। चाहे आप जुलाना को लें, आज तक जुलाना में कोई भी बड़ा उद्योग स्थापित नहीं हो सका और जिस उद्योग की स्थापना हुई भी है वह भी चल नहीं पाया क्यों नहीं चल पाया, यह सरकार के स्तर पर जांच का विषय हो सकता है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि जुलाना विधान सभा क्षेत्र में उद्योग की स्थापना की जाये माननीय सदस्य श्री परमिन्दर सिंह ढुल जी ने भी इस बारे में जिक्र किया है वे मेरे रिश्तेदार भी हैं इसलिए मैं भी उनकी बात का समर्थन करता हूं। सफीदों को फोरलेन से जोड़ने की अभी सरकार ने मंजूरी दी है इसलिए वहाँ पर जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट आयेंगे उनको सुविधा होगी। मेरा सरकार से निवेदन है कि सफीदों में भी कोई इंडस्ट्रियल सैक्टर काटा जाये। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के का सबसे बड़ा गांव मुआना है और उस गांव में लगभग 2 हजार एकड़ पर कपास की फसल थी जो कि सफेद मक्खी के प्रकोप से बर्बाद हो गई थी। वे लोग कुछ दिन पहले भी मेरे पास आये थे और कहा था कि आप हाउस में इस बात को उठाना। उस 2 हजार एकड़ में से आज तक किसी को भी एक एकड़ का भी मुआवजा नहीं दिया गया है। इसलिए मेरा वित्त मंत्री तथा कृषि मंत्री जी से निवेदन है कि मुआना गांव की गिरदावरी दोबारा करवा कर जांच करवा कर उन गरीब किसानों को कपास की बर्बाद फसल का मुआवजा दिया जाये। इसी प्रकार से मेरे हल्के के लगभग 80 प्रतिशत गांवों में जोहड़ों की ओवरफ्लो की समस्या है। गांव का गंदा

पानी इन जोहड़ों में आ जाता है जिसके कारण ये ओवरफ्लो हो जाते हैं। अगर गांव में गंदा पानी जमा होगा तो बीमारियाँ फैलने की आशंका बनी रहती है। अभी 2-3 गांव ऐसे भी हैं जहाँ पर कैंसर की बीमारी के मरीज डिटैक्ट हुये हैं। वह सिर्फ इसलिए कि वह गंदा पानी ओवरफ्लो हो कर घरों में घुस जाता है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इस गंदे पानी की निकासी का भी कोई प्रावधान किया जाये। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्रीमती नैना सिंह चौटाला (डबवाली): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं महिला एवं बाल विकास के साथ-साथ बाल कुपोषण पर बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ। इस बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि वित्त मंत्री जी ने 2016-17 के लिए जो बजट पेश किया है उसमें कई अहम क्षेत्रों को नजरअंदाज किया है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा युवा वर्ग को भी इस बजट में कोई राहत नहीं दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो पिछला 2015-16 का बजट था उसकी 32 घोषणाओं में से 14 घोषणाओं पर अमल ही नहीं किया गया जिसमें कृषि से संबंधित ज्यादा हैं जैसे अटल खेती-बाड़ी योजना, प्रधानमंत्री कृषि योजना तथा गेहूं-धान फसली चक्र योजना आदि। जिस प्रकार एक गुरू अपने शिष्य को मंत्र दे देता है और वह शिष्य उस मंत्र को ही जपता रहता है उसी प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने "सबका साथ-सबका विकास" तथा "Minimum Government-Maximum Governance" का नारा दिया था और हमारे वित्त मंत्री भी उसी को जपते रहते हैं लेकिन सच्चाई यह है कि पेश बजट में न तो सबको साथ लिया गया है और न ही सबका विकास हुआ है। अध्यक्ष महोदय, बजट किसी भी सरकार की सोच और दृष्टिकोण को दर्शाता है। बजट एक अहम दस्तावेज होता है। पेश किये गये बजट से ही पता चलता है कि सरकार भविष्य में आम आदमी के लिए क्या करना चाहती है। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफैस्टो में लगभग डेढ सौ से ज्यादा वायदे किये थे जो कि खोखले साबित हुये हैं उनको पूरा नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार का जो महिलाओं के लिए बजट है वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। आज हमारे हरियाणा प्रदेश में गर्भवती महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है क्योंकि सरकारी अस्पतालों में जब गर्भवती महिलाएं चैकअप के लिए जाती हैं तो उनको दी जाने वाली मल्टी-विटामिन की गोलियाँ भी वहाँ पर उपलब्ध नहीं होती, उनको बाहर से खरीदनी पड़ती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं वित मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि उन्होंने गर्भवती महिलाओं के लिए बजट का जो प्रावधान रखा है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए क्योंकि मेरे क्षेत्र में बाल विकास और कुपोषण जैसी योजनाओं को लागू करना उस बजट में बिल्कुल भी संभव नहीं है। यह ठीक है कि आज पंचायत में हमारी महिलाएं चुनकर आई हैं जो आपकी सरकार की बहुत ज्यादा काबिलेतारिफ बात है और उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं कि आज पढ़ी-लिखी महिलाएं गांव की सरपंच बनी हैं।

वित मंत्री (कैप्टन अभिमन्यू) : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं काफी देर से देख रहा था कि बहन जी शगुन के नाम पर कुछ तो तारीफ करेंगी।

श्रीमती नैना सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी की तारीफ जरूर करूंगी क्योंकि हरियाणा सरकार ने महिलाओं से संबंधित बहुत सारी योजनाएं लागू की हैं जैसे 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ।' 'सुकन्या' योजना। इसमें बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना आपकी काबिले तारीफ है इससे लड़कियों को बहुत प्रोत्साहन मिला है। अध्यक्ष महोदय मैं मंत्री जी से एक बात और कहना चाहूंगी कि जितनी भी योजनाएं सरकार ने लागू की हैं उस पर मैं दो लाईने कहना चाहूंगी -

'वक्त मिले तो देख लेना, लागू योजनाओं की किताब खोलकर,

क्योंकि महिलाएं हर क्षेत्र में अव्वल हैं, कामयाब हैं।'

मैं महिला एवं बाल विकास से संबंधित डिमांड पर कहना चाहूंगी कि गरीब गर्भवती महिलाओं की देखभाल पर होने वाला खर्चा बहुत कम होता है गर्भवती स्त्री 9 महीने तक अपने पेट में बच्चे को रखती है तो उस पर इतना लम्बा चौड़ा खर्चा नहीं आता। मैं मंत्री जी को कहना चाहूंगी कि वह महिलाओं की ऐसी अवस्था को देखते हुए बजट में बढ़ोतरी करने का प्रयास करें तभी हम भ्रूण हत्या को रोक सकते हैं। सरकारी अस्पतालों में महिलाओं के लिए जो दवाइयां दी जाती है मैं कहती हूं कि उसको आप बिल्कुल फ्री कर दीजिए। मुझे लगता है कि जो महिलाएं यहां सदन में चुनकर आई हैं उन्होंने वह गरीबी नहीं देखी है लेकिन जो गरीब महिलाएं ईंट के भट्ठों पर काम करती हैं वह 9 महीने गर्भवती रह कर भी काम करती है क्योंकि एक महिला की स्थिति को एक महिला ही जान सकती है। वह गर्भावस्था में भी 9 के 9 महीने तक काम करती है। इसलिए आप गरीब महिलाओं की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें। अध्यक्ष महोदय, महिला के पेट में पल रहे बच्चे का पोषण तभी होगा जब हम कुपोषण को खत्म करेंगे। इस पर भी मैं दो लाइनें कहना चाहती हूं -

'ला गुलाब लगा लो , तुम अपने आंगन में ,

जीवन में खुशबू तभी मिलेगी जब एक स्वस्थ बच्चा पैदा होगा।'

अध्यक्ष महोदय, मैं इन लाइनों के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि न हो शोषण और न हो कुपोषण क्योंकि आज की स्वतंत्र भारत की धरा पर सम्मान से और बराबरी से जीना हर भारत के बच्चे का अधिकार है। आज हरियाणा में आंगनवाड़ी में मिड-डे मील परोसा जाता है और उस मिड-डे मील में कभी कीड़े निकलते हैं और कभी उसमें छिपकलियां निकलती हैं और कभी हमारे बच्चों को एक्सपायरी डेट का भोजन परोसा जाता है। ऐसी खबरें हम आए दिन अखबारों में भी पढ़ते हैं और हम अपनी आंखों से भी देखते हैं। सर, जैसे आप पंचायत में पढ़ी-लिखी महिलाएं लेकर आए हैं जो आपका बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं इसके लिए भी कहना चाहूंगी कि जब मैं गांव में महिलाओं के पास जाती हूं तो हमारे गांव की महिलाएं हो सकता है कि सिरसा जिले की बैल्ट एजुकेशन में बहुत ज्यादा आगे नहीं हैं जितने कि रोहतक और सोनीपत जिले की हैं। हमारे क्षेत्र में आज भी बहुत ज्यादा महिलाएं अनपढ़ हैं। जब मैं अपने गांव में जाती हूं तो हमारी महिलाएं मुझे मेरी बागड़ी भाषा में कहती हैं कि बिंदणी थे, म्हाने आंगनवाड़ी में लगा दो। जब मैं उनको कहती हूं कि आप तो पढ़ी-लिखी नहीं हो तो वह मुझे बागड़ी भाषा में ही कहती हैं कि- बिंदणी आंगनवाड़ी में लागन खातिर पढ़ाई की कोई जरूरत कोनी। इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि जैसे आप पढ़ी-लिखी पंचायत लेकर आए हो वैसे ही आप आंगनवाड़ी में भी पढ़ी-लिखी महिलाओं को लेकर आओ क्योंकि वहां जो महिलाएं नौकरी कर रही हैं उनको बिल्कुल नहीं पता कि वहां जो दवाइयां रखी हुई हैं वह ऐक्सपायरी हो गई हैं। इसके अलावा वह बच्चों को जो दलिया दे रहे हैं वह कितना पुराना हो चुका है उनको इसके बारे में पता नहीं है क्योंकि आंगनवाड़ी में हैफेड से जो दलिया आता है वह वैसे ही बहुत पुराना होता है। इसलिए आप आंगनवाड़ी में भी पढ़ी-लिखी महिलाओं को लेकर आईये जो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज स्वतंत्र भारत में यह सब सर्वे से पता चलता है कि भारत ने कुपोषण में अफ्रीका को भी पीछे छोड़ दिया है। सर, मैं देखती हूं कि हमारे इस स्वतंत्र भारत में कुछ गरीब बच्चों को तो एक निवाला भी नसीब नहीं हो रहा है। इसलिए कुपोषण पर

जागरूकता लानी बहुत जरूरी है और जिसके लिए गांव व छोटे-छोटे शहरों में महिलाओं को जागरुक करना भी बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, शाम को पांच बजे टी.वी. पर एक प्रोग्राम आता है जिसको मैं जरूर देखती हूँ जिसमें पशुओं के बारे में बताया जाता है कि कैसे पशुओं का दूध निकालना चाहिए, कैसे उनका पोषण करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि इस बारे में पूरी डिटेल के साथ बताया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहूँगी कि सरकार द्वारा गांव की अनपढ़ महिलाओं के लिए जानकारीप्रद प्रोग्राम्ज बनाये जाने चाहिएं ताकि गांव की अनपढ़ औरतें उन प्रोग्राम्ज को देखकर फायदा उठा सकें। उन्हें पता होना चाहिए कि जब वह गर्भवती हों तो बच्चे का पोषण कैसे करना चाहिए। जब गर्भ में पल रहे बच्चे का ही पोषण ठीक तरह से नहीं होगा तो स्वस्थ बच्चा कैसे जन्म ले सकेगा। हरियाणा प्रदेश में बच्चों में कुपोषण की समस्या बहुत ज्यादा है। आज हम जो निवाला बच्चों के मुंह में डालते हैं वह जहर से भरपूर होता है क्योंकि जो सब्जियां हम आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों को दे रहे हैं वह सब्जियां कीटनाशकों से लिप्त होती हैं। जो दलिया व दालें बच्चों को दी जाती हैं उनमें भी कीटनाशकों का जहर लिप्त है। दूसरी बात यह है कि क्योंकि गांव में महिलायें अनपढ़ होती हैं उनको यह मालूम नहीं होता है कि सब्जियों को धोकर आंगनवाडी केन्द्रों में बच्चों के लिए बनाना चाहिए। गन्दे पानी से सब्जियों को धोया जाता है। गन्दे पानी से ही खाना पकाया जाता है और गन्दे हाथों से बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्रों में खाना खिलाया जाता है तथा बच्चों के हाथ तक नहीं धुलवाये जाते हैं। यह सभी चीजें भी कुपोषणता को ही बढ़ावा देती हैं। इन सबका कारण शिक्षा का अभाव है। अत: मैं इस सदन के माध्यम से एक बात फिर से कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार से पंचायतों में पढ़ी-लिखी महिलाओं को लेकर आया गया है उसी प्रकार से आंगनवाड़ी केन्द्रों में जो बिल्कुल अनपढ़ औरतें हैं वहां पर भी शिक्षित औरतों को लगाया जाना चाहिए। मेरा यह मकसद बिल्कुल नहीं है कि अनपढ़ औरतों की रोजी-रोटी पर लात मारी जाये लेकिन यदि आंगनवाड़ी केन्द्रों में पढ़ी-लिखी औरतें काम करेगी तो हमारे बच्चे स्वस्थ बनेंगे, उनका विकास होगा और उनको कुपोषणता से भी मुक्ति मिल सकेगी। आज के दिन कुपोषणता के मामले में हम अफ्रीका से भी आगे निकल चुके हैं। अफ्रीका में कुपोषण की बहुत ज्यादा समस्या है लेकिन आज हालात यह है कि कुपोषण के मामले में हिन्दुस्तान ने अफ्रीका को भी पीछे छोड़ दिया है। 27 मार्च को ट्रिब्यून अखबार में एक खबर आई थी कि पॉलीथिन के बैग में अगर गरम खाना डाला जायेगा तो उस खाने को खाने से कैंसर का रोग हो सकता है। हरियाणा प्रदेश में स्थित पी.जी.आई. की कैंटीन में आज भी प्लास्टिक की थैलियों में खाना परोसा जा रहा है। इस तरह का कार्य भी कुपोषणता को बढ़ाने का ही कार्य करता है। इस तरह से बीमारियों को बढ़ावा मिलता है। मैं चाहती हूँ कि हरियाणा सरकार को सख्ती से पॉलीथिन पर पाबंदी लगानी चाहिए ताकि बीमारियों को फैलने से रोका जा सके। आज बिहार जैसा राज्य भी यह कहने लग गया है कि हमने कुपोषणता की समस्या को खत्म कर दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आभा मंडल इतना ओजस्वी है और उनकी बॉडी लैंग्वेज स्पष्ट बयान करती है कि जिन बातों का माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया जाता है, उन बातों के बारे में निश्चित रूप से वह जब सोने जाते होंगे तो उनका मनन जरूर करते होंगे। यह ठीक है कि आपने शादी नहीं की और आपकी कोई बेटी नही है। (विघ्न)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं नैना जी को बताना चाहूँगा कि पूरे देश और प्रदेश की सभी बेटियां मेरी अपनी बेटियां हैं।

श्रीमती नैना सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, देश और प्रदेश की सभी बेटियां हमारी अपनी बेटियां है, यह बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ठीक कही है इसलिए मैं उनसे प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते आग्रह करती हूँ कि बेटियों के उत्थान हेतु यथोचित कदम उठायें जायें। उनकी कुपोषणता की समस्या हर हाल में दूर की जानी चाहिए। मैं वित्त मंत्री जी से भी आग्रह करना चाहूँगी कि उन्हें महिला और कुपोषित बच्चों के लिए बजट में राशि बढ़ाने का प्रावधान करना चाहिए। पॉलीथिन के मामले में सख्त कानून बनाने की जरूरत है। इनकी वजह से बहुत ज्यादा बीमारियां फैलती हैं अत: इनको खत्म करने का काम किया जाना अति आवश्यक है। मैं एक महिला हूँ इसलिए अंत में मैं महिलाओं पर चंद लाईनें बोलना चाहूँगी:-

रखती है मायके का मान, बेटी बनकर

ससुराल का सम्मान, बहू बनकर

पति के अरमान, पत्नी बनकर

बच्चों का ध्यान, मां बनकर

फिर भी रहती है, खुद से अंजान

क्या यही है, एक औरत की पहचान ?

(इस समय मेजें थपथपाई गई।)

श्रीमती संतोष चौहान सारवान: अध्यक्ष महोदय, बहन नैना जी ने इतनी अच्छी बातें कहीं है। सत्ता पक्ष के सभी सदस्यों ने उसके लिए मेजें थपथपाई हैं लेकिन इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी के सदस्यों ने पूरे दिल से मेजें नहीं थपथपाई हैं।(हंसी)

श्री रणबीर गंगवा: अध्यक्ष महोदय, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी सदस्य पूरे दिल से मेजें थपथपा रहे हैं शायद संतोष जी ने इसे ठीक से नहीं देखा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सारवान जी, थोड़ी सही लेकिन अबकी बार तो इंडियन नैशनल लोकदल के सदस्यों ने मेजें थपथपाई हैं। (हंसी) (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती नैना सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। वर्तमान बजट के बारे में भी मैं थोड़ी सी अपनी बात रखना चाहूँगी। अभी 23.3.2016 को बेटियों से संबंधित एक खबर अखबार में लगी है कि बेटी के जन्म देने पर ससुराल वालों ने बहू को पीटा। यह रिवाड़ी जिले में स्थित सुभाष बस्ती की खबर है। यहां पर एक बहू जोकि राजस्थान में ब्याही हुई थी, ने बेटी को जन्म दिया था। ससुराल वालों ने उसकी बेटी को तो मार दिया और बहू को सात दिन तक एक कमरे में बंद करके रखा। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूर की जानी चाहिए। अब जबकि बेटियों की बात की जा रही है तो उस परिपेक्ष्य में मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि भ्रूण हत्या पर सरकार द्वारा लगाई गई रोक तथा 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' का अभियान, सरकार की एक बहुत सुन्दर पहल है। अध्यक्ष महोदय, रेवाड़ी में 26 तारीख को एक महिला अस्पताल में डिलीवरी करवाने के लिए गई थी, लेकिन डॉक्टरों ने उसको यह कह कर अटैंड नहीं किया कि आपकी पहली डिलीवरी है, इसलिए आप बाद में आइये। महिला अस्पताल में डॉक्टरों के पास

चक्कर काटती रही और अंत में डॉक्टर ना आने पर महिला को फर्श पर ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। महिला के बच्चे को जन्म देने के बाद लगभग तीन घंटे बाद नर्स उसके पास आई थी। शायद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कुछ संज्ञान लिया हो मगर अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में बैठी महिलाओं से यह कहती हूँ कि 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' के नारे का ढोल पीटने और मेजें थपथपाने से कुछ नहीं होगा। इन महिलाओं को माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहिए कि महिलाओं के बारे में कुछ न कुछ जरूर करें। महिलाओं के बारे में डिबेट करें। गांव में जाकर महिलाओं को जागरुक करें।

श्रीमती बिमला चौधरी: हम गांवों में जाते हैं।

श्रीमती नैना सिंह चौटाला: यह बहुत ही अच्छी बात है। मैं महिला होने के नाते सत्ता पक्ष की आप सब महिला सदस्यों से कहती हूँ कि आपकी सरकार है, इसलिए आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहे कि महिलाओं के बारे में कुछ ना कुछ जरूर करें। गांव में जाकर महिलाओं से डिबेट करें। मुझे लगता है कि आप सारी शहरी महिलाएं हैं। आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि गांव में महिलाएं कैसे रहती है? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती संतोष चौहान सारवान: अध्यक्ष महोदय, हम गांवों से ही संबंध रखते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती बिमला चौधरी: अध्यक्ष महोदय, हमने गांव की गरीबी भी देखी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती नैना सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं कोई डिबेट करने के लिए नहीं खड़ी हुई हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती संतोष चौहान सारवान: अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहती हूँ कि जब भी हमारी बहन बोलती है, बहुत अच्छा बोलती है और हम बीच में कोई भी टिप्पणी नहीं करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्रीमती नैना चौटाला जी, ये माननीय सदस्या तो आपको बोलने पर प्रोत्साहन देती हैं।

श्रीमती नैना सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं महिला होने के नाते कह रही हूँ कि आप मुझे भी शामिल करें। हमें गांव-गांव में जाकर महिलाओं को बताना चाहिए। इतने छोटे-छोटे काम हैं जैसे दरी बनाना, बालसमंद गांव में महिलाएं बीडस से काम करती हैं। हमारे सिरसा में जो छोटे-छोटे गांव हैं, मेवात में जो गांव हैं और उनका शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा होने के कारण उन गाँवों की महिलाएं कुछ नहीं जानती है। वहां पर लघु उद्योग लगवाइये, जिससे महिलाओं को रोजगार मिलें। जो काम माँ करेगी, बेटी भी वही काम सीख कर आगे करेगी क्योंकि बेटी बड़ी होकर माँ का ही रूप बनती है। बेटी को माँ से ही संस्कार मिलते हैं। इसलिए हमारी तरफ इस तरह के छोटे-छोटे लघु उद्योगों को लगा दीजिए जिससे महिलाओं को काम मिल सके। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे वर्ष 2016-17 के बजट अनुमानों पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ।

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य का अभिनन्दन

श्री अध्यक्ष: मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि श्री रामफल चिढ़ाना, पूर्व विधायक आज इस सदन की कार्यवाही देखने के लिए वी.आई.पी. दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं पूरे सदन की ओर से उनका स्वागत करता हूँ।

सदन की कार्यवाही में परिवर्तन

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, वर्ष 2016-17 के बजट अनुमानों पर अभी कई और सदस्य बोलना चाहते हैं इसलिए सभी सदस्यों को बोलने का समय देने के लिए यदि सदन की सहमति हो तो आज का शेष कार्य दिनांक 30 मार्च, 2016 को ले लिया जाये।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, आज का शेष कार्य दिनांक 30 मार्च, 2016 को ले लिया जायेगा।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: यदि सदन की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 30 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए ?

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, सदन की बैठक का समय 30 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2016-17 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

14:00 बजे **वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु)** : अध्यक्ष जी, श्रीमती नैना चौटाला ने बजट अभिभाषण पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए अपनी बात को बड़े अच्छे ढंग से महिलाओं के पक्ष में रखा है। मैं इनकी भाषण कला की दाद देता हूं। इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से सरकार की तारीफ की है इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। माननीय सदस्या को जिस विषय पर लगा कि इन्हें सरकार को सुझाव देने चाहिए वहां इन्होंने अच्छे सुझाव दिए हैं और जिस विषय पर इन्हें लगा कि सरकार के काम में कोई कमी है तो वहां इन्होंने विपक्ष के नेता के नाते सरकार की कान खिंचाई भी की है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, माननीय सदस्या श्रीमती नैना चौटाला को 'दैनिक भास्कर' अखबार ने 'स्पीकर ऑफ द डे' भी चुना था। यह अखबार प्रतिदिन सदन में सबसे अच्छा बोलने वाले एक सदस्य को 'स्पीकर ऑफ द डे' टाइटल के लिए चुनता है।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष जी, मैं भी इस बात को एप्रिशियेट करता हूं। मेरा इनके साथ एक नेग नाता भी है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, इस अखबार ने कल माननीय सदस्य श्री टेकचंद शर्मा को भी 'स्पीकर ऑफ द डे' टाइटल के लिए चुना था। (विघ्न)

श्री कर्ण देव कम्बोज : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि माननीय सदस्या श्रीमती नैना चौटाला ने कहा कि हैफेड द्वारा सप्लाई किये गए दलिये के अंदर इस प्रकार के कीड़े निकलते हैं। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि हैफेड दलिया सप्लाई नहीं करता है। हैफेड सिर्फ गेहूं, चावल इत्यादि की सप्लाई करता है। (विघ्न) अत: हैफेड के गेहूं में कोई कमी नहीं है।

श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास (रिवाड़ी) : ऑनरेबल अध्यक्ष महोदय, आज मैं वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विकासोन्मुखी और शानदार बजट प्रस्तुत करने पर वित्त मंत्री को हार्दिक बधाई देता हूं। इस बजट में गौ संवर्धन, गौ रक्षा, ग्राम पंचायतों में शिक्षित सदस्यगण की उपस्थिति, किसानों की फसल का मुआवजा, भूमि अधिग्रहण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मेक इन इंडिया अभियान, महिला थानों की स्थापना, रावी-ब्यास नदियों के पानी पर अच्छा स्टैण्ड, रिनयुअल एनर्जी के लिए भारत में अंतर्राष्ट्रीय सोलर हैडक्वार्टर, मैट्रो नैटवर्क, आरक्षण के समय हुई हिंसा पर डैमेज कंट्रोल, हैपनिंग हरियाणा सम्मिट, के.एम.पी. एक्सप्रैस-वे, नेशनल हाइवेज का जाल बिछाना इत्यादि विषयों पर ध्यान दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सोलर हैडक्वार्टर स्थापित करना सरकार का एक बड़ा और साहसिक कदम था। सरकार ने बहुत-सी उपलब्धियों के साथ बहुत-सी अच्छी-अच्छी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। इस महान सदन के सभी माननीय साथी अनेक तरीकों से बजट के बारे में बता चुके हैं। अब समय का अभाव है इसलिए मैं अपने विधान सभा क्षेत्र वीर भूमि, शहीद भूमि, रेजांगला के शहीदों की भूमि, राव तुलाराम की भूमि और पीतल नगरी के नाम से विख्यात रिवाड़ी के विषय में बोलना चाहूंगा। मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी बजट के प्रावधानों में इस क्षेत्र के लिए काफी कुछ जोड़ने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा में इस क्षेत्र के लिए एक कॉलेज के खोलना तय हुआ था। मेरे क्षेत्र की जनसंख्या को देखते हुए वहां पर शिक्षण संस्थानों का नितान्त अभाव है। वहां प्रतिवर्ष हजारों छात्र बिना किसी कॉलेज में एडमिशन लिए रह जाते हैं और उन बेचारों का जीवन असमंजस में रहता है। इस घोषणा को हुए एक साल बीत चुका है। इस कॉलेज के निर्माण का अगर इस बजट में प्रावधान कर दिया जाता तो अच्छा होता। मैं प्रार्थना करता हूं कि रिवाड़ी शहर की गर्ल्स सीनियर सैकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग का शीघ्र निर्माण किया जाए। रिवाड़ी शहर में गर्ल्स मिडल स्कूल के पास पर्याप्त भूमि है और उसमें कन्याओं की संख्या काफी ज्यादा है। अत: इस स्कूल के भवन और दर्जे को बढ़ाया जाए। हमारे क्षेत्र के विकास में एक बाधा वहां के अधिकारीगण हैं। वहां अधिकारियों के कार्य करने की गति बहुत धीमी है जोकि सरकार की गति से काफी पिछड़ी हुई है। ये दोनों परस्पर तालमेल से नहीं चल रहे। अधिकारी धीरे धीरे चलते हैं और सरकार स्पीड से चल रही है इसलिए इस गति में तालमेल होना चाहिए। तालमेल बने इसके लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या हुडा के रैजीडैंशियल और इंडस्ट्रियल सैक्टर्ज की है। हालात इतने खराब हैं कि फण्ड्स के अभाव में मूलभूत सुविधाएं वहां के लोगों को नहीं मिल रही। इंडस्ट्रियल एरिया को एच.एस.आई.आई.डी.सी. को सौंपने का प्रपोजल चल रहा है। यह प्रपोजल पिछले 3 सालों से चल रहा है इसलिए इसको गति दी जाए और यह काम शीघ्रता से करवाया जाए। अगर एच.एस.आई.आई.डी.सी. में ये सड़कें नहीं आती तो हुडा से इन सड़कों का सुधार करवाया जाए। अध्यक्ष महोदय, रिवाड़ी में भीड़ के कारण जगह जगह जाम लगे रहते हैं। बारात, दूल्हे, बीमार, सर्विसमैंन, किसान आदि लोग अक्सर भीड़ में फंसे रहते हैं। मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार एक महत्वपूर्ण बाई पास हमारे यहां बनना है जिसके लिए 2 वर्ष के समय की बात मुख्यमंत्री महोदय जी से हुई थी। अब सरकार का एक वर्ष से ज्यादा समय निकल गया है इसलिए इस महत्वपूर्ण कार्य को अब तत्परता से किया जाना बहुत जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण विषय के बारे में मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा। नगरों और शहरों की आवासीय बस्तियो के मकानों के ऊपर बिजली की लाइनें जा रही हैं जिसकी वजह से दुर्घटनाएं होती रहती हैं। मेरा अनुरोध है कि जन कल्याण हेतु इन लाइनों को सरकारी खर्चे पर हटवाया जाए।

परिवहन मंत्री (श्री कृष्णलाल पंवार) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि पहले लाल डोरे में जो बस्तियां होती थी उसमें एल.टी. लाइनें और एच.टी. लाइनें निगम के खर्चे से हटाई जाती थी। अब मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है कि चाहे अनअथोराइज्ड कालोनियां हों, चाहे अथोराइज्ड कालोनियां हों या गांव के अंदर जो भी बस्तियां हैं या स्कूल हैं जिनके ऊपर भी एच.टी. या एल.टी. लाइनें जाती हैं वे निगम के खर्चे से हटाई जाएंगी। लाल डोरे से बाहर भी जो कालोनियां हैं उनकी भी लाइनों को निगम के खर्चे से हटाया जाएगा।

श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास: अध्यक्ष महोदय, राजस्थान से बहता पानी धारूहेड़ा, सैक्टर 4 और 6 से होते हुए एन.एच.-8 को तोड़कर पार होता आ रहा है। फ्लाई ओवर बनने से सैक्टर 4 और 6 डूब जायेंगे। वर्षा का मौसम आने से पहले प्रस्तावित नाला तुरंत बनवाया जाए वरना वहां बड़ी विकट समस्या हो जाएगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है। बारिश का पानी आ जाने से ये दोनों सैक्टर्ज डूब जाएंगे क्योंकि फ्लाई ओवर को तोड़ना बहुत कठिन हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अभी समय है इसलिए राजस्थान से आने वाले पानी के लिए जो नाला कई सालों से प्रस्तावित है उसको तुरंत निकाला जाए। यह फ्लाई ओवर इसी साल ही बना है, इसलिए इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, समय बहुत कम है क्योंकि बहुत जल्दी बरसात का मौसम आ जाएगा। अध्यक्ष महोदय, एक सबसे जरूरी बात मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी यूनीवर्सिटी, मीरपुर के साथ आस पास के कुछ जिलों के कालेजिज को जोड़ने के लिए हमने मुख्यमंत्री महोदय से और सरकार से प्रार्थना की थी लेकिन वह काम अभी तक नहीं हो पाया जबकि चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय में एक साल के अंदर ही आस पास के कालेजिज जोड़ दिए गए थे। मीरपुर की यूनीवर्सिटी, यूनीवर्सिटी न बनकर केवल कॉलेज के रूप में काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पिछली बार सम्भवत: साढ़े 18 करोड़ रुपये का बजट इस यूनिवर्सिटी के लिए दिया गया था। वहां कुछ फैकल्टी भी बढ़ी हैं उसके बावजूद भी अब इस यूनीवर्सिटी के लिए मात्र 18 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। जिसमें केवल तनख्वाह और मोटे-मोटे खर्चे ही पूरे हो पाएंगे और संडरी एक्सपैंसिज भी पूरे नहीं हो पायेंगे। इसी के साथ-साथ मैं कहना चाहूंगा कि रिवाड़ी शहर में सौलिड वेस्ट की बहुत समस्या है इसलिए वहां सौलिड वेस्ट का प्लांट लगाने की नितांत आवश्यकता है। इसी तरह से गांव माजरा श्योराज में 28 एकड़ भूमि सरकार के नाम पी.पी.पी. मोड पर मैडीकल कालेज बनाने हेतू दी थी लेकिन आज तक वह नहीं बनाया गया। अब वहां पर कोई अच्छा शिक्षण संस्थान स्थापित किया जाए। इसी के साथ-साथ मैं कहना चाहूंगा कि शराब सरकार के लिए आमदनी का साधन नहीं होना चाहिए और जो पंचायतें अपने यहां दारू के ठेके नहीं खोलने देना चाहती वहां पर दारू के ठेके न खोले जाएं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्तमंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि अब वह समय आ गया है कि रावी ब्यास के पानी की लड़ाई बहुत अच्छे से लड़ी है और जाटों को आरक्षण भी मिल गया है इसके लिए बधाई देता हूं। लेकिन अब क्योंकि आरक्षण मिल गया है और ऐसी समस्या बार-बार न आये, उसके लिए मैं अपने दिल से एक सुझाव दे रहा हूं कि आरक्षण का महत्व तभी है जब पिछड़ा व्यक्ति समाज के स्ट्रीमलाईन में आ जाये, इसके लिए ही उसे आरक्षण मिले। जरूरतमंद को आरक्षण जरूर मिले। बिना जरूरतमंद को बेसक मिले लेकिन जरूरतमंदो का ध्यान रखा जाए। अब कोई समस्या नहीं है इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि फर्स्ट क्लास से लेकर फोर्थ क्लास तक की कितनी नौकरियां

हैं उनके लिए एक श्वेत पत्र तुरंत जारी कर दिया जाये ताकि भविष्य में यह एक नोटिस रहे और कोई समस्या न आये। यह जानकारी सरकार की नॉलेज में भी रहे और जनता भी समझ सके। जिसको अधिकार नहीं मिला है उसको मिले और जिनको ज्यादा मिल गया है हम जैसों को उनका बेसक कट जाये। इसी तरह से एक सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए राशि बढ़ाई गई है। इसमें मेरा मानना है कि इस व्यवस्था से हमारी परम्परा और संस्कृति घायल होती है। इस तरह का प्रोत्साहन नहीं होना चाहिए। इस तरह की शादियों से वर्ण-संकर संतान की उत्पति होगी। अत: भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि-

कुल मारकर सब धर्म बिगड़ें नार हो व्याभिचारणी,
औलाद होवे वर्ण-संकर कुल की आबरू तारणी।
जल पिंड कुल का बंद हो पित्तरों स्वर्ग से आप पड़ें,
ज्ञान मुझ को हो गया कैरों के संग में ना लड़ें।

अत: पितरों का स्वागत हो, सम्मान हो उसके लिए जरूरी है, हमारी संस्कृति की रक्षा हो और इस तरह के विवाह को रोकना चाहिए। अंत में मैं अध्यक्ष महोदय आपका दोबारा से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया और फिर दोहराना चाहता हूं कि मेरे रिवाड़ी हल्के का ध्यान रखा जाए। जय हिंद, जय भारत !

श्री सुभाष सुधा (थानेसर) : स्पीकर सर, आपने मुझे माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये गये वर्ष 2016-17 के बजट पर बोलने के लिए समय दिया सबसे पहले तो मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। यह बजट प्रदेश के विकास, हर जाति और हर नागरिक के लिए नये-नये अवसर लेकर आयेगा। वित्तमंत्री जी द्वारा ऐसी-ऐसी योजनाओं का बजट में जिक्र किया गया है जिनसे पूरे प्रदेश में सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन तेज़ी के साथ आयेगा और पूरे प्रदेश का सर्वांगीण विकास होगा। इसके लिए मैं आपको, पूरी सरकार और सभी माननीय साथियों के साथ पूरे प्रदेश को बधाई देता हूं। पिछले वर्ष के बजट से वर्ष 2016-17 के बजट में 28.4 प्रतिशत की वृद्धि करके कुल 88781.96 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। हमारी सरकार ने एजुकेशन के क्षेत्र में भी बहुत से सराहनीय कार्य किये हैं। हमारे कुरूक्षेत्र में एक राजकीय महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मेरे कुरूक्षेत्र में एक स्कूल था जिसमें 1400 लड़कियां पढ़ती थी। लड़कियों की संख्या इतनी ज्यादा होने के कारण वहां पर मॉर्निंग और इवनिंग क्लासिज़ में लड़कियों को पढ़ाया जाता था। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हमारी इस समस्या को देखते हुए सैक्टर 1 में एक नया स्कूल खोलने का भी मुझे आश्वासन दिया है। मैं इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी का बार-बार धन्यवाद करता हूं। मैं यहां पर इस बात का भी उल्लेख करना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश के किसानों की जिस प्रकार से पिछली बार गेहूं की फसल खराब हुई उसका हमारी सरकार ने प्रदेश के प्रभावित किसानों को 1092 करोड़ रुपये मुआवज़े के रूप में वितरित किया गया। ऐसे ही हमारे प्रदेश के जिन किसानों की कपास की फसल सफेद मक्खी के कारण बर्बाद हो गई थी उन पीड़ित किसानों को भी 962 करोड़ रुपये का मुआवज़ा दिया। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कुछ दिन पहले जाट आरक्षण के दौरान

[श्री सुभाष सुधा]

उपद्रवियों ने हमारे प्रदेश के व्यापारियों की दुकानों को जला दिया वह एक निंदनीय कार्य था। मैं यहां इस बात का भी उल्लेख करना चाहूंगा कि वर्ष 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय हम 10 लाख लोग जिनमें ब्राह्मण, वैश्य और पंजाबी समुदाय के लोग पाकिस्तान से यहां पर आये थे। उस समय हम सभी कुछ वहां पर छोड़कर आये थे। हम वहां से कुछ भी साथ लेकर नहीं आये थे सिर्फ इतनी सी बात थी कि वहां पर हमारा धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था जो कि हमने नहीं किया। जब हम यहां पर आये तो हमको यहां आकर शरणार्थी कैम्प्स में रहना पड़ा। शरणार्थी कैम्प्स में रहते हुए हम लोगों ने मज़दूरी की यहां तक कि पल्लेदारी का काम भी किया। चाहे हमें सब्ज़ी बेचने का काम करना पड़ा लेकिन हमने किसी के भी आगे भीख नहीं मांगी। हमने बहुत-बहुत मेहनत मज़दूरी की जिसके कारण हमने तरक्की के नये आयाम स्थापित किये। इतने संघर्ष के बाद जब हम अब वास्तव में सैटल हुए हैं तो हमें फिर से उजाड़ने का काम किया गया। यहां तक कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पाकिस्तानी कहा गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से एस.सी./एस.टी. लागू किया जाता है उसी प्रकार से इस मामले में भी कार्रवाई की जाये और एक कानून बनाया जाये। स्पीकर सर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पिछले जितने भी मुख्यमंत्री इस हरियाणा प्रदेश के हुए अगर उनके पास मुख्यमंत्री बनने से पहले तीन एकड़ ज़मीन थी तो मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने हज़ारों एकड़ ज़मीन बना ली लेकिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास तीन एकड़ ज़मीन थी। जब पिछले दिनों हमारे पंचनंद ट्रस्ट ने एक कार्यक्रम किया और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी तीन एकड़ पैतृक ज़मीन में से एक एकड़ ज़मीन पंचनंद ट्रस्ट को दान कर दी। जब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि हम 100 एकड़ में पंचनंद ट्रस्ट का विस्तार कर रहे हैं इसलिए आप कुछ फण्ड हमें देकर जायें इस पर उन्होंने कहा कि मैं हरियाणा सरकार का भी ट्रस्टी हूं और पंचनंद ट्रस्ट का भी ट्रस्टी हूं इसलिए मैं एक ट्रस्ट से दूसरे ट्रस्ट को पैसा ट्रांसफर नहीं करूंगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की ऐसी सोच है जो हरियाणा के किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री की नहीं रही होगी। जाट आरक्षण के बाद जब हमारे विधायक दल की बैठक हुई तो उस समय हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी की आंखों में तीन बार आंसू देखे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहां पर जाट आरक्षण बिल को पास करवाकर आज यह साबित कर दिया कि उनका दिल बहुत बड़ा है। ऐसे संत मुख्यमंत्री किसी भी प्रदेश को बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। मुझे सत्तापक्ष ही नहीं विपक्ष के भी बहुत से विधायक साथी मिलते हैं और खासकर विपक्षी विधायक मुझे यह कहते हैं कि 15-15 सालों के दौरान जो हमारे क्षेत्र में डवैल्पमैंट नहीं हुई थी वह माननीय मुख्यमंत्री जी ने केवल मात्र डेढ़ साल के छोटे से अंतराल में कर दी है। यह बात मुझे विपक्षी विधायकों द्वारा कही जाती है यह अलग बात है कि अपनी पार्टी से बंधे हुए होने के कारण वे इस बात का खुलासा विधान सभा में न कर पाते हों। मैं उन सभी विधायको का धन्यवाद करूंगा जो इस प्रकार का आदर भाव हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति अपने दिल में रखते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि जाट आरक्षण के हम कभी भी खिलाफ नहीं थे उन्होंने दिया यह एक बहुत अच्छी बात है लेकिन हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि जिन व्यापारियों और दूसरे हमारे साथियों का नुकसान इस जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुआ है उनको उचित मुआवज़ा तो मिले ही मिले इसके साथ ही उनके परिवार के एक सदस्य को उसकी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी भी दी जाये। इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इस आंदोलन की आड़ में उपद्रव करने वाले

उपद्रवियों के खिलाफ जितने भी केस बने हुए हैं उनको किसी भी कीमत पर वापस न लिया जाये और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाये ताकि भविष्य में कोई भी उपद्रवी इस प्रकार का साहस न कर सके। यह प्रार्थना भी मैं माननीय स्पीकर साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से करना चाहूंगा। मैं वित्त मंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी कुरूक्षेत्रवासियों की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने कृष्ण सर्किट के नाम से 90 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया है। वैसे तो कुरूक्षेत्र के लिए सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है लेकिन मैं एक मांग और करना चाहूँगा कि गीता जयन्ती समारोह पर जिस प्रकार दिल्ली और चण्डीगढ़ से स्पेशल ए.सी. बसें चलाई गई थी उसी प्रकार से हर शनिवार और रविवार को भी वे ए.सी. बसें पैकेज के आधार पर चलाई जायें। गीता जयन्ती समारोह में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम कुरुक्षेत्र को विश्व के मानचित्र पर लाना चाहते हैं इसलिए मैं मांग करता हूँ कि कुरूक्षेत्र और करनाल के बीच समाना बाहू गांव में 600 एकड़ जमीन पड़ी हुई है उस पर एक एयरपोर्ट बनवाया जाये ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहाँ पर पर्यटक पहुंच सकें। इसके लिए भी यहाँ हाउस में एक प्रस्ताव पारित किया जाये। कुरूक्षेत्र एक पर्यटक स्थल है और वहाँ पर देश-विदेश से पर्यटक आते हैं इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ हर चौंक पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाये जायें। कुरुक्षेत्र शहर के बीचों-बीच रेलवे लाईन जाती है जिससे शहर दो हिस्सों में बंटा हुआ है। रेलवे से बात करके रेलवे फाटकों को समाप्त करके वहाँ पर ऐलिवेटिड ट्रैक बनवाया जाये जिससे लोगों को असुविधा न हो। इसी प्रकार से ज्योतिसर में थीम पार्क कॉम्पलैक्स जो कि खाली पड़ा हुआ है उसको चालू करवाया जाये। इस बार गीता जयन्ती समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कुरूक्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता जयन्ती मनाई जायेगी इसलिए वहाँ पर एक सात सितारा होटल की जगह खाली पड़ी हुई उस पर सात सितारा होटल बनाया जाये। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं सड़कों के बारे में भी अपनी बात कहना चाहता हूँ। सड़कों के लिए सरकार ने बहुत पैसा दिया है और सभी सड़कों पर काम चल रहा है लेकिन मैं एक सुझाव अवश्य देना चाहूँगा कि सड़कों को बनाने से पहले सभी संबंधित विभागों से एन.ओ.सी. जरूर ली जाये ताकि बाद में सड़क को उखाड़ा न जाये। इसके अतिरिक्त मैं एक मांग और करना चाहता हूँ कि कुरूक्षेत्र में एक बाईपास का निर्माण अवश्य किया जाये क्योंकि वहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से कुरूक्षेत्र में साईकिल ट्रैक और आयुष विश्वविद्यालय खोलने की जो घोषणा वित्त मंत्री जी ने की है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। इसके अतिरिक्त ब्रह्मसरोवर का बहुत वर्षों से रूका हुआ जो पानी था जिसको निकाल कर दोबारा भरने के लिए मुख्यमंत्री जी ने 28 करोड़ रुपये सैंक्शन किये हैं तथा उसकी हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल भी मिल गई है। जल्दी ही उसके टैंडर हो जायेंगे तथा उस पानी को बदल दिया जायेगा उसके लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूँ। हम जब ब्रह्मसरोवर पर जाते थे तो उसमें नहाने से भी कतराते थे क्योंकि पानी रूका हुआ था और उसमें से स्मैल आती थी। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री परमिन्दर सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, जब संत विनोबा भावे भूदान आन्दोलन के लिए देश भ्रमण करते हुये हरियाणा में आये थे तो उस समय चौधरी देवीलाल जी ने अपने हिस्से की हजारों एकड़ जमीन दान कर दी थी। यह एक बहुत अच्छी परम्परा चली थी और मैं यह सदन के सूचनार्थ बताना चाहता हूँ।

प्रो. रविन्द्र बलियाला (रतिया) (अनुसूचित जाति): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका बार-बार धन्यवाद करता हूँ। बजट सत्र पर चर्चा करते हुये बहुत सी बातें नेता प्रतिपक्ष श्री अभय सिंह चौटाला जी ने सरकार के संज्ञान में ला दी हैं उनको न दोहराते हुये मैं केवल एक बात से चर्चा शुरू करना चाहूँगा कि बजट में जो आंकड़ों का खेल खेला गया है यह केवल मात्र आईवॉश करने का एक साधन है। बजट में केवल आंकड़ों के आधार पर ही सरकार की वाहवाही लूटने का काम किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसमें ग्रोथ और डिवैल्पमैंट जो दो कन्सैप्ट हैं उन दोनों को मिलाने का काम किया गया है और सरकार हर एक सतह पर यह कह रही है कि सबका विकास होना चाहिए अर्थात 'सबका साथ सबका विकास।' लेकिन यदि विकास करने की बात है तो उसमें यह जरूरी है कि उसमें जो रिसोर्सिज हैं पहले उनको जनरेट किया जाए, उनको पैदा किया जाए और जो रिसोर्सिज का साधन है उनको सही तरीके से एलोकेशन किया जाए और उनका बंटवारा किया जाए। उसके साथ-साथ उन रिसोर्सिज का सही तरीके से यूटिलाईजेशन भी किया जाए। सरकार का एक मुख्य नारा भी है कि 'सबका साथ सबका विकास।' जहां तक रिसोर्स जनरेशन की बात है उसके लिए सरकार ने अपने लैवल पर बहुत से प्रयास करने की बात कही है लेकिन जो अभी 'लेटैस्ट हैपनिंग हरियाणा' के नाम पर रिसोर्स जनरेट करने की बात कही है मैं उसी से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने का काम करूंगा कि आज के जो हालात हैं उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है पहले यह देखना चाहिए कि किस तरह के हालात बने हुए हैं। क्या आप उन हालात के अन्दर हरियाणा को उस स्थिति में समझ सकते हैं कि 'हैपनिंग हरियाणा' का जो प्रोग्राम है वह कामयाब हो पाएगा ? इसमें कोई शक नहीं है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवैल्पमैंट होना चाहिए। लेकिन आज जो हालात हैं क्या आप उस तरीके से इन्फ्रास्ट्रक्चर को डिवैल्प कर सकते हैं क्योंकि इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवैल्प करने का जो सबसे बड़ा साधन है वह बिजली है। आज बिजली की जो स्थिति है उस स्थिति में क्या हरियाणा में उद्योग आना चाहेंगे। मंत्री जी ने यह कह तो दिया कि 5 लाख 84 हजार करोड़ रुपये के इन्वेस्टमैंट एम.ओ.यूज. साईन किये हैं। क्या सिर्फ एम.ओ.यूज. साईन करने से ही वह सारा निवेश आ जाएगा ? क्या यह गाना गाने से ही व प्रोग्राम करने से ही वह सारा का सारा निवेश आ जाएगा ? सर, इसमें बहुत सी शंकाएं हैं जिनको विपक्ष के नेता माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने भी सदन के सामने रखी थी और मैं उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं कि एक वांडा ग्रुप के साथ एम.ओ.यूज. साईन करने की बात आई है और ऐसा ही एक एम.ओ.यू. जब मुख्यमंत्री जी चीन दौरे पर गये थे वहां भी कर के आए थे। अब इसे भी 'हैपनिंग हरियाणा' के साथ जोड़ दिया है। हरियाणा सरकार उन एम.ओ.यूज. को तीन हजार एकड़ जमीन खरखौदा सोनीपत में देने की योजना बना रही है तो मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उनके साथ किये गये एम.ओ.यूज. को सार्वजनिक किया जाए कि सरकार वह जमीन कहां से देगी और किसानों से वह जमीन किस रेट में ली जाएगी और आगे कंपनी को किस रेट में दी जाएगी और यह तीन हजार एकड़ जमीन का प्रबंध कैसे होगा ? इसी तरह से बैंकों के साथ एम.ओ.यूज. की बात आई जिसमें आई.सी.आई.सी. बैंकों के साथ एम.ओ.यूज. की बात आई जिसमें उन्होंने कहा कि हम हरियाणा में 100 नई शाखाएं खोलने का काम करेंगे। सर, मैं बताना चाहता हूं कि बैंक तो रूटिन में शाखाएं खोलते रहते हैं वह तो सर्विस सैक्टर है लेकिन हम डवैल्पमैंट उसको कहेंगे जो कोई नई बात है या कोई नये इन्वेस्टमैंट की बात है जैसे नये पुल हैं, सड़कें हैं कोई कारखाने हैं, कोई उद्योग हैं अगर कोई इस तरह की यदि बात आती है तो उसको डवैल्पमैंट कहेंगे वह तो सर्विस सैक्टर है,

बैंक तो अपनी शाखाएं खोलते रहते हैं और बैंकों की जो शर्तें होती हैं वह बहुत स्टैंडर्ड शर्तें होती हैं। यह नहीं है कि वह अपनी शर्तों में थोड़ी ढ़ील देकर उनमें एक आदमी को राहत देने का काम करेंगे। आगे समय मिलेगा तो मैं इस बात पर चर्चा करूंगा कि किस तरह से बैंकों के साथ जो वार्षिक क्रेडिट प्लान बनाया जाता है उसमें कितने प्रतिशत बैंकों ने उस पर अपना सही काम किया है और कितना प्रतिशत उस स्कीम का यूटिलाईजेशन हो पाया है उस पर आगे बात करेंगे। इसके साथ-साथ ऐसा ही विपक्ष के नेता माननीय श्री अभय सिंह चौटाला जी ने भी कहा था कि सरकार ने एक टैक्सी चलाने वाली कंपनी से एम.ओ.यूज. साईन किया है तो वह भी एक सर्विस सैक्टर की बात है उसमें हम यह नहीं कह सकते कि कोई बहुत बड़ा इन्वैस्टमैंट हो गया है। इसके साथ ही यदि हम कहें कि यह सरकार की मंशा थी कि आठ प्रकार के उद्योगों में जहां तक निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने की बात कही थी उसमें सरकार का फोकस इस बात पर था कि 'हैपनिंग हरियाणा' में ग्लोबल इन्वेस्टमैंट सम्मिट में निवेशकों को आकर्षित करके प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योगिक इकाइयों का आगमन हो और रोजगार की उपलब्धता हो।

वित मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने बड़ा मौलिक प्रश्न खड़ा किया है जिसके लिए मैं उनके बीच में हस्तक्षेप करके आपकी इजाजत से बोलना चाहता हूं। यह जो सर्विस सैक्टर है वह आज हमारी अर्थव्यवस्था को लगभग 54-55 प्रतिशत राजस्व भी देता है और हमारी जी.डी.पी. में कॉन्ट्रीब्यूट भी करता है। सर्विस सैक्टर एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है इसलिए सर्विस सैक्टर में जितना निवेश आता है उससे एम्प्लॉमैंट ज्यादा बढ़ती है, राजस्व बढ़ता है और यही अर्थव्यवस्था की मेच्योरिटी का संकेत है। प्राईमरी से सैकेंडरी की तरफ बढ़ना और सैकेंडरी से टरचरी सैक्टर की तरफ बढ़ना, सर्विसिज सैक्टर में निवेश आना यह बहुत ही सकारात्मक संकेत हैं। बाकी वांडा ग्रुप के साथ और दूसरे जो एम.ओ.यूज. हुए हैंवे भी सार्वजनिक किये जाएंगे और पूरी ट्रांसपेरेंसी से काम होगा। इसका मैं आपको पूरा भरोसा देता हूं। हमारी जो पॉलिसीज है जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने याद दिलाया है वह इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है बल्कि एन्टरप्राईज प्रमोशंज पॉलिसी है यानि उद्योगों को प्रोत्साहन देने की नीति है। जो कोई जिस प्रकार का भी उद्यम करता है, उसको प्रोत्साहन देने के लिए एन्टरप्राईज प्रमोशन पॉलिस बनाई गई है। (विघ्न)

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: यदि सदन की सहमति हो तो सदन का समय 5 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाये ?

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष: सदन का समय 5 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2016-17 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

प्रो. रविन्द्र बलियाला (रतिया) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी सर्विस सैक्टर में टैक्सी कम्पनियों के साथ एम.ओ.यू. करके सुधार लाना चाहते हैं। वर्तमान में प्रदेश के हालात देखकर मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि आज प्रदेश के लोगों में असंतोष व्याप्त है। जहां तक आटोनोमस इंवेस्टमेंट की बात है तो वर्तमान में विकट परिस्थितियों में सरकार को खुद निवेश

[प्रो. रविन्द्र बलियाला]

के लिए आगे आना चाहिए। यह बिल्कुल साफ है कि असंतोष की स्थिति में प्राईवेट लोग इंवेस्टमैंट करने के लिए कभी भी आगे नहीं आयेंगे। जब प्रदेश में इस तरह से मंदी व असंतोष की स्थिति व्याप्त है तो इस स्थिति में निवेश की संभावनाएं बहुत मुश्किल लगती है। हमें निवेश के मामले में शंका ही नजर आ रही है। इसके अतिरिक्त जो क्षेत्र जैसेकि सोनीपत या खरखौदा निवेश के लिए चिन्हित किए गए हैं यहां पर अभी पिछले दिनों हुए उपद्रवों को देखते हुए भी निवेश की संभावनायें नगण्य ही नजर आती हैं। आज प्रदेश में कितनी ही अपहरण तथा डकैतियों की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। आज अखबार इस तरह की वारदातों की खबरों से अटे पड़े हैं। कहने का मतलब यह है कि प्रदेश में निवेश के लिए अभी तक परिस्थितियां पैदा ही नहीं की गई हैं। सरकार ने जो बातें निवेश के संबंध में कही हैं वह मात्र कल्पना है। इनको मुंगेरी लाल के हसीन सपने की संज्ञा अगर दे दी जाये तो गलत नहीं होगा। जिस प्रकार सरकार इंवेस्टमैंट की बात कह रही है, इस तरह की चीजें महज कुछ दिन में संभव नहीं हो सकती हैं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा की आर्थिकी कृषि पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। आज किसान की कितनी बुरी हालत हो चुकी है, इसके बारे में सभी को अच्छी तरह से मालूम है। किसान को पिछली तीन फसलों का भी भाव नहीं मिल पाया है तो ऐसी स्थिति में उसकी परचेजिंग पावर किस तरह से बढ़ पायेगी। माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि हमने टैक्स फ्री बजट देने का काम किया है। 500 रुपये तक की परचेज करने पर कर नहीं लगाने तथा वैट की दरों को 12.5 प्रतिशत से 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। यह अच्छी बात है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा चूंकि सर्विस सैक्टर बहुत छोटा उद्योग है तो ऐसे में उसमें कितने लोगों को रोजगार सुलभ करवाया जा सकेगा ताकि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ सके और इसका कितना मल्टीप्लॉयर इफेक्ट होगा तथा इस उद्योग से आर्थिकी कितनी मजबूत होगी। अध्यक्ष महोदय, मैनुफैक्चरिंग सैक्टर के बारे में भी बात की गई थी। इस सैक्टर से संबंधित विषय को मंत्री महोदय ने क्लीयर कर दिया था अत: इस पर ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक रीयल एस्टेट्स की बात है तो इस सैक्टर में इंवेस्टमैंट की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। बहादुरगढ़, रोहतक, झज्जर तथा गुड़गाव में तो रीयल एस्टेटस की बाढ़ सी आई हुई है लेकिन इस सैक्टर में भी इंवैस्टमैंट कितना कारगर साबित होगा यह भी देखने वाली चीज है। आज हम देखते हैं कि पंजाब के जीरकपुर तथा इसके साथ लगते इलाकों व हरियाणा व चंडीगढ़ के साथ लगते इलाकों में काफी बड़ी मात्रा में फ्लैट्स बनाये गये हैं। रीयल एस्टेट्स में इतनी भारी मंदी आ चुकी है तो ऐसी स्थिति में नई कंपनियां किसी प्रकार से इंवैस्टमैंट करेंगी। यह समझ से परे की बात है। सरकार को पता नहीं किस तरह से फायदा होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी चीन और जापान की यात्राएं कर चुके हैं और दावा करते हैं कि प्रदेश में विकास को बढ़ावा देने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के एम.ओ.यू. साईन हुए हैं। वास्तव में यह रीयल एस्टेट्स के क्षेत्र से ही संबंधित थे। एम.ओ.यू. भले ही साईन हुए हों लेकिन प्रदेश में कोई निवेश हुआ हो, यह कही भी नजर नहीं आता है। (विघ्न)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय साथी को बीच में रोकने के लिए मजबूरन खड़ा होना पड़ रहा है। तीन-चार बार यह समान विषय इसी महान सदन में माननीय विपक्ष के साथियों के द्वारा उठाया गया है। तीनों-चारों बार उसकी सही सूचना व जवाब दे दिया गया है। उसके बावजूद भी लिखने वाला, बताने वाला और पढ़ाने वाला फिर उन्हीं लाईनों को कट-कॉपी पेस्ट कर देते हैं और प्रोफेसर बलियाला जैसे विद्वान आदमी उसको दोहरा देते हैं।

(शोर एवं व्यवधान) इसलिए सदन का समय बचाने के लिए मैं मजबूरन इनको इंट्रप्ट कर रहा हूँ। जो बात पहले सदन में आ चुकी है, उन पर बार-बार सदन में चर्चा नहीं की जानी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी अपने आपको ज्यादा ज्ञानी समझने लग गये हैं और हमारी पार्टी के सदस्य पर "विद्वान" शब्द का प्रयोग करके कटाक्ष करने का काम कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु: अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है मैंने तो बिल्कुल आदर सहित बलियाला जी के लिए "विद्वान" शब्द का प्रयोग किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री परमिन्दर सिंह ढुल: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को हमारी पार्टी के सदस्य को बीच में इंट्रप्ट करने का कोई हक नहीं है। उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, प्रोफेसर बलियाला जी आपसे अनुमति लेकर खड़े हुए हैं। प्रोफेसर बलियाला बिना किसी तथ्य के सदन में कोई बात नहीं कर रहे हैं। अगर माननीय वित्त मंत्री जी को लगता है कि कोई बात गलत कही जा रही है तो आप बजट निकालकर देख सकते हैं और जब वित्त मंत्री जी बजट पर अपना उत्तर देंगे तो उस समय प्रोफेसर बलियाला व फिर किसी अन्य सदस्य द्वारा उठाई गई शंकाओं पर अपना वक्तव्य दे सकते हैं। मंत्री जी, आपको हमारे किसी भी सदस्य को इंट्रप्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। आप इनको अपनी बात कहने दें। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु: अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुमति लेकर खड़ा हुआ हूँ इसलिए मुझे अपनी बात पूरी करने का अधिकार है। माननीय बलियाला जी जिन विषयों पर अब सदन में बात कर रहे हैं उन पर पहले से जवाब व सूचना सदन के माध्यम से दी जा चुकी है इसलिए मैंने सदन का समय बचाने के लिए मजबूर होकर माननीय सदस्य को बीच में ही इंट्रप्ट करना पड़ा। जिस विषय पर सदन में पहले चर्चा हो चुकी है और जिसका जवाब भी दिया जा चुका है फिर उसी विषय को उठाने से सदन का समय ही खराब होता है। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो. रविन्द्र बलियाला: अध्यक्ष महोदय, जब तक हम संदर्भ में बात नहीं करेंगे तब तक समस्या हल नहीं होगी।

श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने उस दिन दिनांक 8 मार्च को दैनिक भास्कर में छपी खबर की एनालिसिस को दिखाया था। अध्यक्ष महोदय, या तो मंत्री महोदय गुमराह कर रहा है या वह दैनिक भास्कर अखबार लोगों को गुमराह कर रहा है। मैंने इस बारे में सारी बातें माननीय वित्त मंत्री जी को बताई थी। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो इन्फ्रस्ट्रक्चर के बारे में 1.43 की फिगर बताई थी, वह सही थी और इन्होंने अगले दिन उसको मान भी लिया था।

कैप्टन अभिमन्यु: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मेरे द्वारा सदन के पटल पर जो जवाब दिया गया था उसके बारे में भी अपने मुँह से बता दें तो बहुत अच्छा लगेगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया था कि जो जानकारी समाचार पत्र में छपी है वो गलत है। सदन के पटल पर जो जानकारी सरकार दे रही है, वह बिल्कुल सही है।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, बजट सत्र के दौरान यदि कोई समाचार पत्र गलत जानकारी देता है तो उसको नोटिस करना चाहिए। उस समाचार पत्र को इस बात के लिए दोबारा से कंडम करवाना चाहिए कि आप लोगों के बीच में एक गलत जानकारी दे रहे हैं।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: यदि सदन की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 5 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए ?

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, सदन की बैठक का समय 5 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2016-17 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता के सुझाव पर अमल करने के लिए मैं आवश्यक इसलिए नहीं समझता हूँ क्योंकि अगर गलत जानकारी अखबार में पढ़कर के उसको उद्घृत किया है और मैं सदन के पटल पर उसको गलत प्रमाणित करने की बात कह रहा हूँ। गलत जानकारी का उपयोग या दुरुपयोग माननीय प्रतिपक्ष नेता ने किया है, इसलिए आप स्वयं जाकर कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो करें, लेकिन सदन के पटल पर जो जानकारी दी जा रही है, वह बिल्कुल सही है। यह काम हमारा नहीं है कि कोई भी हर गलत खबर पर टिप्पणी करें। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो. रविन्द्र बलियाला: अध्यक्ष महोदय, मैं औद्योगिक सुरक्षा की बात कर रहा था। आज से 13 वर्ष पूर्व चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने औद्योगिक सुरक्षा बल में कर्मचारियों का चयन किया था। अध्यक्ष महोदय, इन औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मचारियों को दोबारा से बहाल करके नौकरी दी जाये। रीयल एस्टेट क्षेत्र में 23 कम्पनियों द्वारा जो निवेश हुआ है, उनको पूरा करने के लिए जो वायदे किए गए हैं, उन्हें किस तरह से पूरा किया जायेगा ? सरकार इस बात को भी बताने का कष्ट करें ? पिंजौर में एच.एम.टी. लि. कम्पनी के कर्मचारियों को 2 महीने से लेकर14 महीने तक वेतन नहीं मिला है। सरकार एक तरफ जो इन्वैस्टमैंट को बढ़ाना चाहती है और दूसरी तरफ कर्मचारियों को वेतन नहीं दे रही है। स्कूलों में अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हुए हैं। इसके बारे में भी माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने लिखकर भी दिया हुआ था। कर्मचारियों की वेतनमान विसंगतियों को अभी तक दूर नहीं किया गया है। जिन कर्मचारियों की वेतनमान विसंगतियां दूर हो गई हैं, उनको भी अन्य कर्मचारियों की तरह अभी तक वेतन नहीं मिला है। कॉलेजिज में प्रौफेसर्ज के वेतनमान में विसंगतियों को दूर करने के लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी ने वायदा किया हुआ है, देखते हैं कि वह वायदा पूरा होता है या नहीं ? पिंजौर में एच.एम.टी. लि. कम्पनी के जिन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, वो भूखमरी की कगार पर पहुँच गए हैं। इस कम्पनी में लगभग 10 हजार कर्मचारी काम करते हैं। एच.एम.टी. लि. कम्पनी की वर्तमान कीमत 3 हजार करोड़ रुपये के बराबर है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करता हूँ कि इन कर्मचारियों को वेतन दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, सदन में जो सबसे बड़ा काम होता है, वह मेजें थपथपाने का होता है कि यह बजट टैक्स फ्री बजट है। यदि माननीय सदस्यों द्वारा बताए गए 4-5 बिन्दुओं पर माननीय वित्त मंत्री जी अगर ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि कितने लोगों

[प्रो. रविन्द्र बलियाला]

को फायदा होगा, किस तरह से फायदा होगा और राहत देने का क्या काम किया है ? एक अन्य प्वायंट है, इसमें लिखा गया है कि पत्तेदार सब्जियों को काटने के काम में लाए जाने वाले छोटा टोका पर कर में कितनी छूट दी गई है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : बलियाला जी, आपका टाइम हो चुका है और मैं पहले ही तीन बार टाइम बढ़ा चुका हूं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप वाइंड अप कर लीजिए तो आपको कंक्लूड करना चाहिए। अब मैं आपको बोलने के लिए और समय नहीं दे सकता। अब सदन कल दिनांक 30 मार्च, 2016 प्रात: 10:00 तक के लिए स्थगित किया जाता है।

*14.40 बजे (तत्पश्चात सदन बुधवार 30 मार्च, 2016 प्रात: 10:00 बजे तक के लिए *स्थगित हुआ।)

———————————

54374—HVS—H.G.P., Chd.